खबरें जो सोच बदल दे

शुभ लाभ

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 । शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 । हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित । website : https://www.shubhlabhdaily.com । संपादक : गोपाल अग्रवाल । पृष्ठ : 14 । मूल्य-8 रु.। वर्ष-7 । अंक-93

बिम्सटेक समूह शिखर से इतर बैठक में पीएम मोदी ने उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज

युनुस को सुनाई खरी खरी

बैंकॉक/नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से द्विपक्षीय मुलाकात कर ली लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बरकरार है। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने बहु-क्षेत्रीय और तकनीकी सहयोग के लिए बिम्सटेक समूह के नेताओं की शिखर बैठक से इतर यह मुलाकात की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को

हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं, माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचें

दोहराया है। मिसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुहम्मद यूनुस के साथ चर्चा के दौरान बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने सीमा पर कानून का सख्त पालन करने और अवैध सीमा पार करने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सीमा सुरक्षा को सख्त बनाने पर भी बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया । बता दें कि बांग्लादेश बिम्सटेक समूह का आगामी अध्यक्ष है। पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास आ गयी थी। यह खटास तब और बढ़ गयी थी जब पिछले सप्ताह चीन की यात्रा के दौरान यूनुस ने बीजिंग से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और विवादास्पद रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि यूनुस ने कहा था, भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं।

▶10 पर

मणिपुर हिंसा में 260 लोग मारे गए, लेकिन बंगाल में चुनावी संघर्ष में ही 250 लोग मार दिए गए : शाह

सामान्य स्थिति होते ही मणिपुर में हटेगा राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्य सभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखा। सदन ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच नॉर्थईस्ट में 11,327 हिंसक घटनाएं हुईं, लेकिन मोदी सरकार के दस साल में ये घटनाएं 70 प्रतिशत घटकर 3,428 रह गई हैं। सुरक्षाबलों की मृत्यु में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 85 प्रतिशत की कमी हुई है। मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट में 20 शांति समझौते किए हैं और 10 हजार से अधिक युवाओं ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 लोग मारे गए हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनावी हिंसा में ही ढाई सौ लोग मार दिए गए हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मणिपुर सरकार के सामने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि विपक्ष के पास यह प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त सदस्य ही नहीं हैं। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जद (यू) के 1 और कांग्रेस के 5 विधानसभा सदस्यों से चर्चा की। जब अधिकतर सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तब कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लगाया गया, जबकि दिसंबर, 2024 से आज तक मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 13 फरवरी, 2025 से 7 साल पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में उस वक्त विपक्ष की सरकार थी और तब

▶10 पर

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

राज्यसभा की कार्यवाही की शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए कि बजट सत्र में सदन की उत्पादकता 90 प्रतिशत रही है। सत्र का समापन वंदे मातरम् की धुन के साथ हुआ।

इससे पहले उन्होंने सदन में शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई उल्लेख किया। सत्र के अंतिम दिन सदन में पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने को लेकर हंगामा भी हुआ और सदन की कार्यवाही सुबह दो बार स्थगित की गयी। राज्यसभा का यह सत्र 31 जनवरी को आरंभ हुआ था और चार अप्रैल को समाप्त हो गया। सदन में इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में केपी शर्मा ओली से मुलाकात पर पीएम मोदी बोले

नेपाल भारत के लिए बेहद अहम

बैंकॉक, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुकवार को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय और घनिष्ठ संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी और उनके नेपाली समकक्ष ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, लोगों के बीच संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

▶10 पर

वक्फ विधेयक संसद से पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय की खोज में अहम क्षण : मोदी

नई दिल्ली , 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित होने की आज सराहना की और कहा कि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

▶10 पर

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद जावेद

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

बिल को असांविधानिक करार देने की अपील

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इसके साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पहली याचिका भी दायर हो गई है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने यह याचिका दाखिल की है। सांसद जावेद ने वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में इस विधेयक के माध्यम से किए गए संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है। जावेद के अलावा हैदराबाद से चुन कर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्तावित कानून को चुनौती दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुस मुस्लिमीन के सांसद ओवैसी ने लोकसभा में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे लंबी चर्चा के दौरान भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। ओवैसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए इस विधेयक के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बिल की प्रति फाड़ने की बात कही थी।

संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के कई संगठन और विपक्ष के नेता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके सही उपयोग के लिए है तथा इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यसभा में

▶10 पर

बजट सत्र 2025 में संसद ने बनाया नया रिकॉर्ड

वक्फ संशोधन विधेयक पर 17 घंटे से अधिक चली चर्चा : रिजीजू

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने संसद के आज समाप्त हुए बजट सत्र में वक्फ़ (संशोधन) विधेयक पर दोनों सदनों में रिकॉर्ड समय तक हुई चर्चा को ऐतिहासिक बताया और इसमें बिना स्थगन या हंगामा किये भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को धन्यवाद दिया।

श्री रिजीजू ने संसद भवन परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक में लोकसभा में 14 घंटे से अधिक और राज्यसभा में लगभग 17 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा में तीन अप्रैल को तड़के तीन बजे तक और राज्यसभा में आज सुबह चार बजे तक कार्यवाही चली और इसमें कोई बाधा या स्थगन नहीं हुआ। इस प्रकार से एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले कभी किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए वह सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में सरकार को अपेक्षा के अनुरूप ही वोट मिले हैं। राज्यसभा में एक दल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया था और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की छूट दी थी, जिस पर उसके सांसदों ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया। यदि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने व्हिप जारी नहीं किया होता तो सरकार को ज्यादा समर्थन मिलता। उन्होंने दावा किया कि कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने निजी तौर पर कहा है कि व्हिप का बंधन नहीं होता तो वे विधेयक का समर्थन करते। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह श्रीमती गांधी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वक्तव्य में जबरदस्ती बुलडोज़ करके विधेयक पारित कराने की बात गलत है। सबने देखा है कि दोनों सदनों ने लंबी बहस की और सब संशोधन प्रस्तावों एवं मतदान के जरिये इसे नियमानुसार पारित किया गया है। इसलिए बुलडोज़ शब्द का इस्तेमाल अनुचित है।

▶10 पर

खामोशी को कमजोरी ना समझे मोदी सरकार : उमर अब्दुल्ला

वक्फ बिल के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी बैठक?

श्रीनगर, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुआई में उपमुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास फेयरव्यू गुपकार में एक आपातकालीन बैठक हुई । इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक और गठबंधन के सहयोगी शामिल हुए। बैठक के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने नई दिल्ली से आखिरी बार आग्रह किया कि वह जम्मू-कश्मीर में लोगों के व्यापक जनादेश को कमतर न आंके और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने दे।

मीडिया को जानकारी देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा, आज की बैठक में संसद में पारित वक्फ बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बिल देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा अहम मुद्दा जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा एनसी के नेतृत्व वाली सरकार को दिया गया जनादेश है। हमने एक बार फिर मांग की है कि भारत सरकार इस जनादेश का सम्मान करे, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विधायकों ने आज सर्वसम्मति से ये दोनों प्रस्ताव पारित किए।

उन्होंने कहा कि केंद्र को हमारी चुप्पी और सहयोग को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा, हम आखिरी बार यह अपील अनुरोध के तौर पर नहीं बल्कि सख्त चेतावनी के तौर पर कर रहे हैं। हमें मजबूर न करें और उस जनादेश का सम्मान करें जिसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं।

▶10 पर

अभिनेता मनोज कुमार का निधन

मुंबई, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया।

वह 87 वर्ष के थे। वह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे एवं उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी।

श्री मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। फिल्म निर्देशक मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनके निधन पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

श्री मनोज कुमार को फिल्म उद्योग में उनके योगदान पर 1992 में पद्म श्री एवं 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कार्टून कॉर्नर

मौसम हैदराबाद

अधिकतम : 32^0
न्यूनतम : 24^0

महज पांच महीने की जम्मू कश्मीर सरकार

सीएम और एलजी में शुरू हो गई तकरार

सुरेश एस डुग्गर
जम्मू, 04 अप्रैल।

महज पांच महीने में ही जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तकरार शुरू हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कुछ प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा।

इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वे अपने अधिकारों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और वे अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 46 विधायकों द्वारा हाल ही में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर निराशा व्यक्त करने के तुरंत बाद, एलजी सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सभी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में निर्धारित संवैधानिक ढांचे के भीतर सख्ती से की गई है। उपराज्यपाल ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद ने

2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और मैंने पूरी तरह से उस अधिनियम द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर काम किया है। मैंने कभी भी अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हूं। मैंने कभी उनका उल्लंघन नहीं किया है, न ही मैं ऐसा कभी करूंगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर गठबंधन ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए, जिसमें वक्फ (संशोधन) विधेयक और उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों का विरोध किया गया। नेकां विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि गठबंधन वक्फ (संशोधन) विधेयक की कड़ी निंदा करता है और इसे अल्पसंख्यक विरोधी और मुस्लिम विरोधी करार देता है। उन्होंने वक्फ सम्पत्तियों और जम्मू-कश्मीर में बड़े मुस्लिम समुदाय पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने संकल्प लिया है कि लोगों के जनादेश का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर के एलजी और केंद्र सरकार के साथ समन्वय को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि वे एकतरफा फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील कर रहे हैं, खासकर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक तबादलों के मद्देनजर।

▶10 पर

भारत ने नेपाली वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया

काठमांडू

बैंकॉक,04 अप्रैल (एजेंसियां)। नालीदार चादरें और प्लाइ लकड़ी सहित विभिन्न वस्तुओं पर भारतीय मानक प्रमाण पत्र ब्यूरो के नए सिरे से लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। बैंकाक में शुक्रवार की शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री की साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने शुक्रवार को बताया कि भारत को नेपाली वस्तुओं के निर्यात और भारतीय बाजारों में माल की बिक्री और वितरण के लिए सुविधा प्रदान करने के भारत सरकार से किए गए आग्रह को उधर से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल के साथ नेपाल की वस्तुओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आग्रह किया था। मंत्री भंडारी ने कहा कि गत 11 और 12 जनवरी को नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई थी। इसके बाद भारतीय पक्ष ने समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत ने सीमेंट, नालीदार चादरें, सैनिटरी पैड और जूते सहित वस्तुओं के निर्यात पर बीआईएस को अनिवार्य कर दिया है।

नेपाल ने पांच महीने से भारत को सीमेंट का निर्यात रोक दिया था और एक महीने पहले से प्लाईवुड के आयात पर भी रोक लगा दी थी। भारत के नए प्रावधानों के मुताबिक बीआईएस का नवीनीकरण नहीं करने पर नेपाल की वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता है। बैंकाक में शुक्रवार की शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री की साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के तीन स्तंभ समृद्धि, लचीलापन और खुलापन न केवल सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं, बल्कि नेपाल की समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित भी होते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में शुक्रवार को बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बिम्सटेक को न केवल बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए, बल्कि हमारे क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के अवसर का भी लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का निर्माण हमारी क्षमता को और अधिक उपयोग करने और हमारे पास मौजूद संसाधनों के सही उपयोग के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि हमारे क्षेत्र की सभी अर्थव्यवस्थाएं समान नहीं हैं, हमें सदस्य राज्यों को विशेष जरूरतों के साथ तरजीही समर्थन देना चाहिए, ताकि वे आम समृद्धि साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने पूरी मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर दिया है, इसलिए नेपाल की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ओली ने कहा कि हमारे उच्च हिमालय बारहमासी जल टावर और एशिया के कूलिंग स्टेशन हैं।

कैलासा: एक भगोड़े का दिव्य धोखा बोलीविया में भूमि हड़पने की साजिश

लापाज। स्वघोषित 'संप्रभु राष्ट्र', 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा', जिसने अपने पासपोर्ट, 'कॉस्मिक संविधान' और आधिकारिक मुद्रा के साथ दुनिया का ध्यान खींचा लेकिन अब धोखाधड़ी और भूमि हड़पने के आरोपों से घिरा हुआ है। इसका नेता नित्यानंद, जो एक भगोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, अलौकिक शक्तियों का दावा करता हैं। लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियां अब उजागर हो रही है। हाल ही में बोलीविया में हुई घटनाओं ने उसके दावों की पोल खोल दी है। जहां अधिकारियों ने 'भूमि तस्करी' के आरोप में कैलासा के 20 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बोलीविया के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कैलासा को मान्यता नहीं देने की घोषणा की है। बोलीवियाई मीडिया द्वारा की गई जांच में नित्यानंद के अनुयायियों द्वारा स्वदेशी समूहों, जिसमें बाउरे समुदाय शामिल है, से व्यापक भूमि पट्टे हासिल करने के प्रयासों का खुलासा हुआ। बाउरे नेता पेड्रो गुआसिको ने बताया कि जंगल की आग के बाद सहायता की प्रारंभिक पेशकशें एक समस्याग्रस्त 1,000 साल के पट्टा समझौते में बदल गईं। कैलासा अधिकारियों ने 25 साल के समझौते में वार्षिक भुगतान के रूप में लगभग 200,000 डॉलर का वादा किया था, लेकिन बाद में अनुबंध को 1,000 साल तक बढ़ा दिया गया और इसमें वायु क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण के अधिकार शामिल थे। गुआसिको ने स्वीकार किया कि उनके समूह ने हस्ताक्षर करने की गलती की ।

इजराइली सेना में फिर बरसाए रिहायशी इलाके व स्कूल पर बम, कई लोगों की मौत

दीर अल बलाह। इजराइली लड़ाकू जेट ने गुरुवार को गाजा पट्टी में कहर बरपाया है। इजराइली हवाई हमलों

में गाजा में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। इसमें उत्तरी गाजा के स्कूल पर हवाई हमला भी शामिल है, जिसमें शरण लिए 33 लोग मारे गए हैं। स्कूल पर हुई बमबारी में 70 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में इजराइल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइली सेना ने कहा है कि उसने आक्रामक कार्रवाई तेज की है जिसका इरादा हमास पर नया दबाव डालना और उसे खदेड़ देना है। फलस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गाजा शहर के तुफ्फाह में स्थित एक स्कूल से 14 बच्चों और पांच महिलाओं के शव बरामद किए गए लेकिन मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 70 घायलों में कुछ की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि निकटवर्ती हिजाय्याह इलाके में घरों पर हुए हमलों में 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। इजराइली सेना ने कहा कि उसने गाजा सिटी इलाके में हमास कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया है।

ऐसा क्या करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप कि एच 1बी वीजा धारकों की दिल की धड़कनें बढ़ी

वॉशिंगटन,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से दुनिया में हलचल है। वह एक ओर कुछ देशों पर टैरिफ अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सख्ती दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके सख्त इमिग्रेशन कानून से वहां रह रहे हजारों एच-1बी वीजा धारक आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें अमेरिका छोड़ने का डर सता रहा है। इसी खौफ के बीच गूगल और अमेजन जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों ने अपने एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका ना छोड़ें।

इन मशहूर कंपनियों को डर है कि शायद ट्रंप प्रशासन अमेरिका छोड़ने के बाद हजारों प्रवासी एच-1बी वीजा धारकों को दुबारा लौटने की इजाजत ना दे। इसके बाद हजारों भारतीय सहित कई देशों के एच-बी वीजा धारक पेशेवर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन में हाई स्किल्ड पेशेवरों के वीजा अस्वीकृति की दर बढ़ सकती है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में पैदा हुए लोगों के जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के ट्रंप प्रशासन की कोशिशों से भी एच-1बी वीजा धारकों में डर है। उन्हें लग रहा है कि उनके भविष्य में अपनी अमेरिकी नागरिकता खो सकते हैं।

बता दें कि एच1बी वीजा कार्यक्रम कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों पर अस्थायी रूप से विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की इज्जत देता है। भारत की विशेषरूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां इस कार्यक्रम से काफी लाभान्वित हुई हैं। हर साल लॉटरी सिस्टम के जरिए 65,000 एच-1बी वीजा जारी किए जाते हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर, 2024 की अवधि में विभिन्न नियोक्ताओं को जारी किए गए कुल 1.3 लाख एच1बी वीजा में से लगभग 24,766 वीजा भारतीय मूल की कंपनियों को जारी किए गए। इनमें से इंफोसिस ने 8,140 लाभार्थियों के साथ अग्रणी स्थान हासिल किया। उसके बाद टीसीएस (5,274) और एचसीएल अमेरिका (2,953) का स्थान रहा।

रनवे छूते ही लगा तेज झटका, उछलने लगा प्लेन, टर्की में फंसे 250 पैसेंजर

लंदन। 260 यात्रियों को लेकर लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट वीएस 358 के यात्रियों को बताया गया कि टर्की के दियारबाकिर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला हैं। चूंकि, लैंडिंग की वजह मेडिकल इमरजेंसी बताई गई थी, लिहाजा चाह कर भी कोई कुछ नहीं कह सकता था। पैसेंजर की जान यह जानकर भी हलक में अटक गई कि जिस दियारबाकिर एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड होने वाला है, वह कोई कामर्शियल एयरपोर्ट नहीं, बल्कि टर्किश आर्मी की एयर बेस है। कुछ मिनटों के बाद प्लेन रनवे के करीब पहुंच चुका था। वहीं, प्लेन ने जैसे ही रनवे से टच किया, पैसेंजर्स को एक तेज झटका लगा। प्लेन किसी गेंद की तरफ रनवे पर कुछ देर तक उछलता रहा। प्लेन में पैदा हुए इन हालात ने हर किसी को दहशत से भर दिया। किसी तरह प्लेन टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचने में कामयाब रहा। और, इसी के साथ पैसेंजर्स के लिए परेशानियों और दर्द से भरे एक नए सफर की शुरुआत हो गई। शुरुआत में सभी को यही उम्मीद थी कि यह बस एक छोटा-सा ठहराव है। लेकिन प्लेन से बाहर निकलने के बाद सभी को पता चला कि हार्ड लैंडिंग की वजह से प्लेन के टायर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लिहाजा अगला प्लेन आने तक सभी पैसेंजर को इसी एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा। बीते 24 घंटे से मुंबई आ रहे 250 पैसेंजर इसी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दियारबाकिर एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो गए। पैसेंजर्स का दावा है कि वहां का एयरपोर्ट स्टाफ न अंग्रेजी समझते थे, न हिंदी। यहां न कोई हमें समझा रहा है, न कोई रास्ता दिखा रहा है। हम भ्रमित और असहाय हैं। छोटे-छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे है, बुजुर्गों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। पैसेंजर्स एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर रात बिताने को मजबूर हैं। न कोई एयरलाइन रिप्रजेंटेटिव है, न कोई मदद करने वाला। हालांकि इस बीच वर्जिन अटलांटिक ने आश्वासन दिया है कि होटल और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

एक व्यक्ति ने लोगों पर किया चाकू से हमला खुद को भी किया घायल

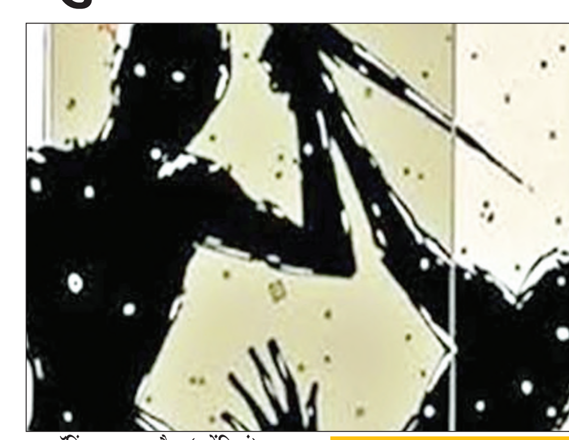

वॉशिंगटन,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

अमेरिका में एक व्यक्ति ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छह लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर नशे की हालत में था और उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना गुरुवार को मोंटेलो एवेन्यू और मेग्स प्लेस एनई के पास घटी।

पुलिस के मुताबिक पहले सड़क पर चलते समय खुद को चाकू मारा और फिर अपने साथ मौजूद एक महिला परिचित पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने दूसरों पर भी चाकू से हमला किया, इनमें दो वह लोग भी शामिल थे जो इस हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे।

स्थानीय पुलिस ने एक्स पर घोषणा की कि मोंटेलो एवेन्यू और

छह लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया

सिम्स प्लेस एनई के इलाके में चाकू से हमला करने की घटना की जांच कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है, तो 202-727-9099 पर कॉल करें या 50411 पर टेक्स्ट करें। हमले में घायल चार महिलाओं और दो पुरुषों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें एक दादी और उनकी दो पोतियां भी शामिल हैं। पीड़ितों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने संदिग्ध को आस-पास के क्षेत्र में जमीन पर पड़ा पाया। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू उससे कुछ दूरी से बरामद किया गया। संदिग्ध का नाम पुलिस ने उजाकर नहीं किया है, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया है और वर्तमान में उसकी सर्जरी की जा रही है। घटना के बाद आस-पास की कई सड़कें बंद कर दी गई। जांच जारी रहने के कारण आगे की जानकारी का इंतजार है।

नाटो बैठक में अमेरिकी विदेशमंत्री से हाथ मिलाते हुए लार्स लोकी रेसमुसन

बेल्जियम में डेनमार्क के विदेशमंत्री लार्स लोकी रेसमुसन नाटो बैठक में अमेरिकी विदेशमंत्री से हाथ मिलाते हुए।

प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात, भूकंप त्रासदी पर संवेदना जताई

बैंकॉक,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में आए भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि पर एक बार फिर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट पर कहा, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के भाइयों और बहनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

उन्होंने लिखा, हमने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से मुलाकात की।

उन्होंने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शिनावात्रा से हुई मुलाकात का विवरण साझा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री थाकसिन शिनावात्रा से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्हें शासन और नीति निर्माण से संबंधित मामलों में व्यापक अनुभव है। वे भारत के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और अटल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री शिनावात्रा और मैंने भारत-थाईलैंड सहयोग और इससे हमारे संबंधित देशों के लोगों को किस तरह लाभ होता है, इस बारे में विस्तार से बात की। हमने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति येओल को संवैधानिक न्यायालय ने बर्खास्त किया

सियोल,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को पिछले साल की गई अपनी अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग का सामना कर रहे येओल को उनके पद से तत्काल हटाने की घोषणा की। संवैधानिक न्यायालय ने शुक्रवार सुबह 11:22 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनकर संवैधानिक न्यायालय के बाहर एकत्र लाखों लोग खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाते हुए न्यायालय के पक्ष में नारे लगाए।

कोरिया टाइम्स अखबार के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने राष्ट्रपति यून सुक येओल को पद से तत्काल हटाने की घोषणा की। जैसे ही न्यायालय के बाहर लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पर महाभियोग की सजा शब्द दिखाई दिया, लोग उछल पड़े। एक-दूसरे को गले लगाया। कई लोग तो लोकतंत्र की जीत पर फूट-फूट कर रोने लगे। इस दौरान यह लोग काफी देर तक नारा लगाते रहे- विजय! विजय! लोकतंत्र अमर रहे। यह देखकर अपदस्थ नेता यून सुक येओल ने कहा, मुझे सच में खेद है और दिल टूट गया है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका।

संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति येओल के महाभियोग को बरकरार रखा। इसके बाद उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया। राष्ट्रपति को पद से हटाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। संवैधानिक न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने 8-0 के मत से पक्ष में मतदान किया। उल्लेखनीय है कि नेशनल असेंबली ने 111 पहले येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। येओल पर तीन दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने सुबह 11 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 11:22 बजे कहा कि येओल को तत्काल राष्ट्रपति पद से हटाने का फैसला किया गया है।

इससे पहले मार्च 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के महाभियोग के बाद आठ वर्षों में दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति की यह पहली बर्खास्तगी है। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत, न्यायालय के फैसले के 60 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए। संभावना है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तीन जून या उससे पहले होगा। अब येओल और उनकी पत्नी किम कीन ही को मध्य सियोल के हन्नाम-डोंग में राष्ट्रपति निवास खाली करना होगा।

माफिया मुक्त हुआ वक्फ, मुसलमानों को मिली नई आज़ादी: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

नई दिल्ली 04 अप्रैल (एजेंसियां)। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 - 2025 पारित होने के बाद देशभर में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल और मंच के हजारों कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सलाम किया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण को हर्ष और उल्लास से मनाएं। यह कानून किसी मज़हब या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, न्याय और विकास का प्रतीक है। यह यतीमों, विधवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने वाला कानून है।

मंच ने देशवासियों से अपील की है कि देश को तोड़ने, लड़ाने, भड़काने और बहकाने वाली विकृत मानसिकता वाले दलों और संगठनों से सचेत रहें। मंच ने कहा है कि भारत को अंग्रेजों से आजादी 1947 में मिली लेकिन वक्फ को माफियाओं और भूमि जेहादियों से आजादी आज मिली है। इस दिन और प्रधानमंत्री का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मंच ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम समाज को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी तथाकथित मुस्लिम हितैषी पार्टियों की सियासी गुलामी से भी मुक्त करता है। मंच ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमान डर, भ्रम और कट्टरता से बाहर निकलें और विकास के साथ आगे बढ़ें।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बताया कि इस विधेयक के समर्थन में मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के कोने-कोने में जाकर 5000 से ज्यादा जनसभाएं, संवाद, गोष्ठियां, लेख अभियान और टीवी डिबेट आयोजित कीं, जिससे समाज में जागरूकता फैली। वक्फ संपत्तियों में हो रही गड़बड़ियों, बंदरबांट और राजनीतिक स्वार्थों की सच्चाई को उजागर किया गया। सैकड़ों विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वक्फ संपत्तियों में चल रहे घोटालों और बंदरबांट की सच्चाई सामने लाई गई। अफवाहों और ग़लत बयानों का खंडन करते हुए लोगों को समझाया गया कि इस कानून से किसी की आस्था को कोई खतरा नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक सुधार का मार्ग है।

वक्फ कानून की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समाधान को लेकर लिखी गई पुस्तक इस्लाम के प्रति सम्मान और मुसलमानों के लिए उपहार इस आंदोलन की वैचारिक रीढ़ बनी। इसके विमोचन में किरेन रिजिजू, जगदंबिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, संघ के संपर्क प्रमुख रामलाल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मोंटेनेग्रो की एंबेसडर जेनिस दरबारी शामिल थे। पुस्तक को किरेन रिजिजू ने वक्फ का इनसाइक्लोपीडिया बताया और हर किसी को पढ़ने की सलाह दी। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहल-ोत तक भी पहुंची।

मंच के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह पुस्तक जन जन तक पहुंची जिसमें वक्फ में चल रही गड़बड़ियों को बखूबी उजागर किया गया था। साथ ही साथ बिल के समर्थन में विस्तार से बताया गया था। कानून बनने के बाद क्या संभावित लाभ हाशिए पर रह रहे मुसलमानों को पहुंचेगा, इस पर भी व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया था। पुस्तक में बताया गया था कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा, पारदर्शिता लाएगा और समाज के वंचित तबके को उसका हक दिलाएगा। यह 'वक्फ से विकास' की सोच को साकार करेगा और मुस्लिम समाज को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक भविष्य की ओर ले जाएगा।'

पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि वक्फ के पास लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति है लेकिन सालाना आमदनी मात्र 163 करोड़ की है जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर आज के वैल्युएशन और इनफ्लेशन के हिसाब से देखें तो आमदनी लगभग सवा लाख करोड़ सालाना होनी चाहिए। इस आमदनी से वक्फ बोर्ड अस्पताल, विश्विद्यालय, स्कूल, नर्सिंग होम, स्किल डेवलपमेंट सेंटर इतियादी खोल सकता था। इससे मुसलमानों की शिक्षा, रोज-गार, स्वास्थ्य सभी में फायदा होता, बेरोजगारी दर भी घटती। परंतु वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं लिया। जबकि दूसरी तरफ माता मंगला फाउंडेशन ने 1000 बेड का अस्पताल खोला, माता वैष्णव देवी ट्रस्ट ने 470 एकड़ में विश्वविद्यालय खोला। इसी प्रकार रिलायंस फाउंडेशन और आगा खान जनहित के कार्यक्रम करता है। लोगों के वक्फ से ही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के निवासियों को अनधिकृत निर्माणों पर दी अंतरिम राहत

नई दिल्ली 04 अप्रैल (एजेंसियां)। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी (चरण 1-5) में 4,000 से अधिक अनधिकृत निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का शुक्रवार को आदेश जारी कर वहां के निवासियों को बड़ी राहत दी।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने प्रभावित निवासियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

पीठ इस मामले में संबंधित पक्षों की नोटिस भी जारी किया।

शीर्ष अदालत का यह आदेश यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश के जवाब में आया है, जिसमें अधिकारियों को दो महीने के भीतर इन निर्माणों के खिलाफ 'त्वरित कार्रवाई' करने का निर्देश दिया गया था।

कथित तौर पर ये याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे और उन्हें बिना सुनवाई के अपनी संपत्ति खोने का डर था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा,इस बीच, अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की तारीख तक यथास्थिति (जैसी आज है) पक्षों द्वारा बनाए रखी जाएगी। आज पारित यथास्थिति के आदेश के मद्देनजर, हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता भी कोई निर्माण नहीं करेंगे।

याचिकाकर्ताओं में कई निवासियों (जिनमें लगभग 2,100 इकाइयों के मालिक और अधिभोगी शामिल हैं) को आसन्न सीलिंग और तोड़ फोड़ का सामना करना पड़ा जो आज से शुरू होने वाला था।

अदालत की अंतरिम राहत आगे के निर्देश जारी होने तक किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई को रोकती है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2024 को हरियाणा के अधिकारियों को दो महीने के भीतर अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ 'शीघ्र कार्रवाई' करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी की।

यह मामला 2021 में डीएलएफ सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और डीएलएफ-3 वॉयस द्वारा दायर याचिकाओं के बाद सामने आया।

इन याचिकाओं में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ शिकायतों के संबंध में 2018 की कार्रवाई रिपोर्ट और जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) के एक ज्ञापन के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द करने और उनकी उपयोगिता सेवाओं को बंद करने की सिफारिश की गई थी।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये अवैध निर्माण ज़ोनिंग प्लान, 2016 और 2017 के बिल्डिंग बाय-लॉ और हरियाणा बिल्डिंग कोड का घोर उल्लंघन है।

अदालत ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के बेतरतीब और अनियोजित विकास पर लगाम नहीं लगाई गई, तो गुरुग्राम का बुनियादी ढांचा- जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति, सीवरेज, वायु गुणवत्ता, परिवहन और बिजली शामिल है- पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने इन उल्लंघनों को बढ़ावा देने में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी स्वीकार किया। अदालत ने देखा कि अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं की एक 'शक्तिशाली लॉबी' कॉलोनी के स्वरूप को तेज़ी से बदल रही है।

पीठ ने टिप्पणी की,यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कुछ समूहों/भू-माफियाओं की एक शक्तिशाली लॉबी स्थानीय प्रशासन/आधिकारिक प्रतिवादियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से विकसित कॉलोनी के मूल चरित्र को बर्बाद कर रही है, वह भी केवल इसलिए क्योंकि अधिकारियों ने आँखें मूंद ली हैं और ऐसे अवैध और अनधिकृत निर्माण/अवैध विकास की अनुमति दे रहे हैं; जो उनकी नाक के नीचे खतरनाक दर पर हो रहे हैं।

मोदी ने की बिम्सटेक देशों में पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा

नई दिल्ली 04 अप्रैल (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक देशों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है।

श्री मोदी ने शुक्रवार को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन के दौरान पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की।

श्री मोदी ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हमारे सामूहिक सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुझे यह घो-षणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत बिम्सटेक देशों में कैंसर देखभाल में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

इस बीच आयुष मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड और भारत के बीच मजबूत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ हैं और इनके बीच घनिष्ठ पारस्परिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है। दोनों देश पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने और विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

थाईलैंड के बाद श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे मोदी

नई दिल्ली 04 अप्रैल (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद वे श्रीलंका की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले सितंबर में पदभार संभालने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका द्वारा मेजबानी किए जाने वाले पहले विदेशी नेता बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा में समग्र द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय चर्चा के बाद, दोनों देश एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र पर अपने सैन्य प्रभाव को बढ़ाने के चीन के निरंतर प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। यदि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यह भारत-श्रीलंका संबंधों में एक बेहतर प्रगति का संकेत होगा, जो अंततः उस कटु अध्याय को पीछे छोड़ देगा, जिसमें भारत ने लगभग 35 साल पहले श्रीलंका से भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) को वापस बुला लिया था।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2022 में हंबनटोटा बंदरगाह पर चीनी मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज 'युआन वांग' के डॉकिंग के बाद भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चल रहा था। अगस्त 2023 में कोलंबो बंदरगाह पर एक और चीनी युद्धप-ोत डॉक किया गया।

भारत और श्रीलंका के बीच अन्य द्विपक्षीय समझौतों को भी मजबूत करने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिसानायका के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन भी शामिल है। इससे पहले, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जो नई दिल्ली और कोलंबो के बीच पहला समझौता होगा। श्रीलंका के साथ समग्र संबंधों पर, मिस्री ने कहा कि श्रीलंका हमारी 'पड़ोसी पहले' नीति का एक अभिन्न अंग है, और आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

प्रथम पुण्यतिथि

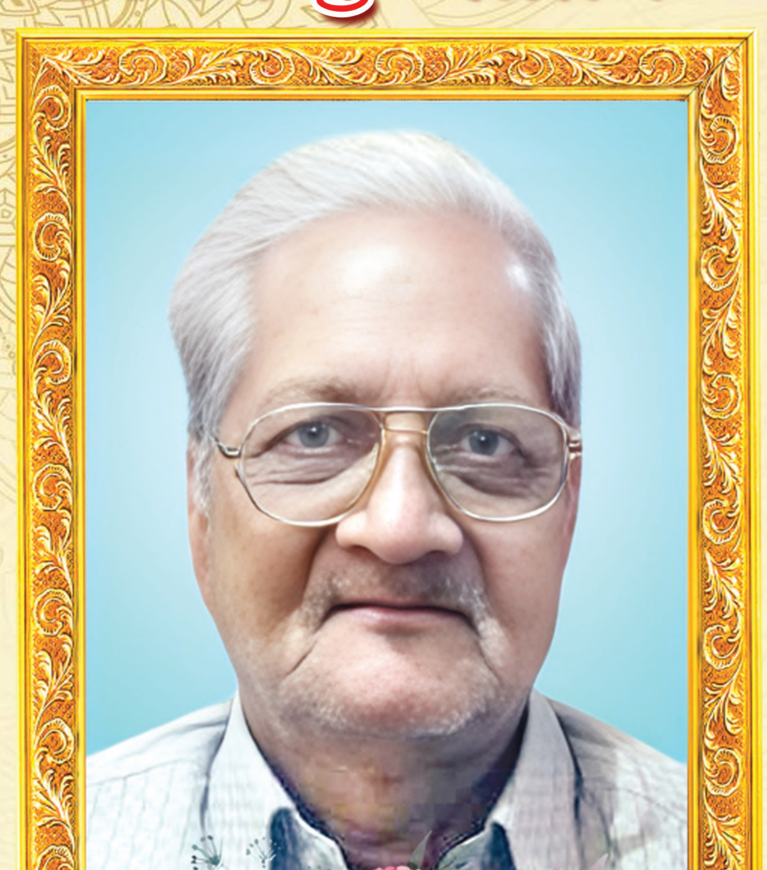

स्व. श्री विष्णुदयालजी अग्रवाल
सुपुत्र : स्व. श्री राधाकिशनजी अग्रवाल
स्वर्गवास : शुक्रवार, दि. 5-4-2024
मीठी-मधुर स्मृतियाँ आपकी, कभी नहीं मिट पाएँगी।
आपका व्यवहार आपकी बातें, सदैव हमें याद आएँगी ।।
शोकाकुल : सुरेश कुमार, गोपाल, रमेश, नन्दलाल (भाई), अनिल (पुत्र), नरेश कुमार, बजरंगलाल, रविन्द्र कुमार, दिलीप कुमार (भतीजे), कमल, तनिष्क (पौत्र) एवं समस्त रामस्वरुप (बसईवाले) परिवार ।
फर्म: राधाकिशन विष्णुदयाल (बसईवाले)
म.नं. 10-5-17, फतेहनगर, पोस्ट ऑफिस लेन,
हैदराबाद, फोन : 9290887874, 9948122252

1960 से लेकर 1980 तक, मनोज कुमार ने हर दशक में दी यादगार फिल्में

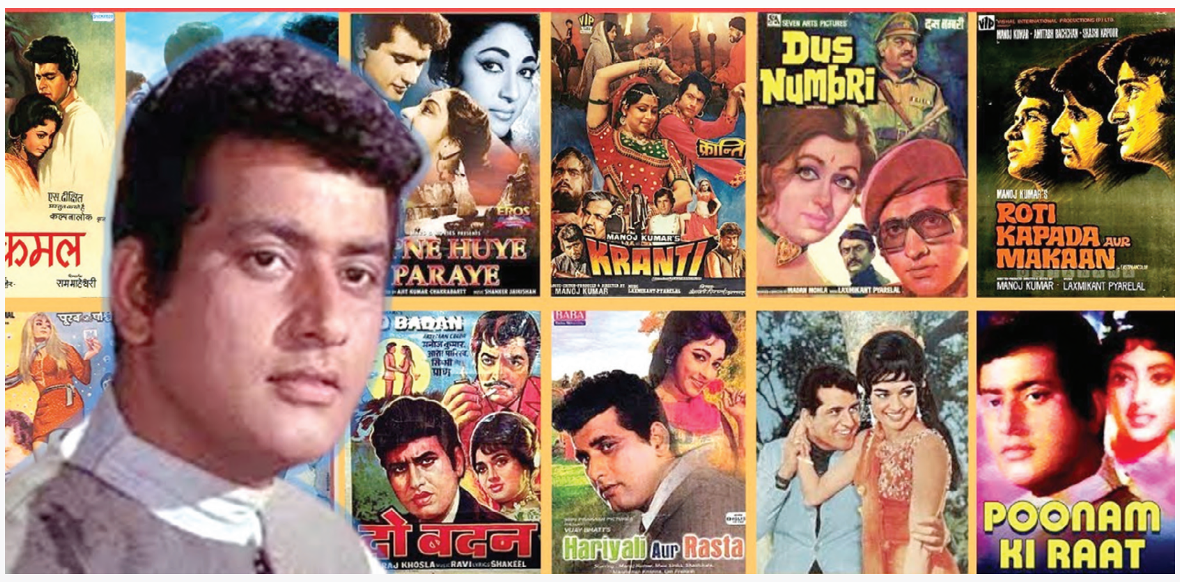

87 साल की उम्र में पीढ़ियों को अपने अभिनय से मुत्तासिर करने वाला अदाकार छोड़ कर चला गया। और पीछे सौंप गया वो विरासत जिस पर उसकी फिल्मी बिरादरी को ही नहीं, पूरे भारत को गर्व है। शाहकार ऐसा जो 'पूरब' से निकल कर 'पश्चिम' के लंदन तक गूंजा। विरले ही होता है कि कोई कलाकार आए और सिल्वर स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दशकों तक लगातार ऐसी फिल्में दे जो वर्षों तक दिलो-दिमाग को कुरेदती रही। हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी ऐसी ही शख्सियत का नाम था। गोस्वामी दिलीप कुमार के जबर फैन थे। एक फिल्म देखी जिसमें दिलीप के किरदार का नाम मनोज था, फिर क्या था, अपना नाम मनोज रख लिया। देशभक्ति रगो में समाई थी, इसलिए मां भारती को समर्पित एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, लोगों ने प्यार से 'भारत कुमार' पुकारना शुरू कर दिया। उन्हें अपने देश और इसकी संस्कृति पर बड़ा नाज था, और यह झलक उनकी फिल्मों में भी दिखी। फिल्मी सफर 1957 में फिल्म 'फैशन' से शुरू हुआ, जो 80 के दशक तक कायम रहा। कुछ ऐसे चलचित्र थे जिन्होंने मनोज कुमार के बहुआयामी व्यक्तित्व से सीधा साक्षात्कार कराया। 1960 से 1980 के दशक तक 7 फिल्मों में निभाए किरदार अब भी लोगों के जेहन में खुरच कर लिखे जा चुके हैं।

बात उन सात फिल्मों की जो ट्रेंडसेटर भी थीं, सुपरहिट भी और मर्मस्पर्शी भी। चॉकलेटी हीरो की इमेज को तोड़ती फिल्म थी शहीद, जो 1965 में रिलीज हुई। कौन भूल सकता है भगत सिंह का वो कालजयी किरदार। ये फिल्म आजादी के बेखौफ परवानों की कहानी कहती थी।

60 के दशक में दो फिल्में आईं और दोनों ने कामयाबी की नई इबारत लिखी। एक थी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनुहार पर बनी उपकार (1967) और दूसरी थी प्योर लव स्टोरी 'पत्थर के सनम'।

उपकार एक कल्ट फिल्म रही। गुलशन बावरा का गीत 'मेरे देश की धरती' उस दौर में भी हिट था और आज की जेन अल्फा भी इसे उतनी ही शिद्दत से जीती है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस फिल्म को मनोज कुमार ने बड़े मनोयोग से रचा था। शास्त्री जी के 'जय जवान जय किसान' का नारा फिल्म का आधार था।

1967 में ही पत्थर के सनम पर्दे पर आई। दो हसीनाओं के बीच जूझते एक शख्स राजेश की कहानी थी। 'राजेश' उपकार के 'भारत' से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया।

इसके बाद 1970 में रिलीज हुई 'पूरब और पश्चिम'। भारतीय सिने इतिहास की पहली फिल्म जिसका विषय एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे। एक पिता का दर्द जो कमाई के चक्कर में विदेश तो चला गया, लेकिन वहां अपनी बेटी में आए बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा है। उस दर्द को बखूबी बयां किया गया। ये भी सुपरहिट फिल्म रही। इंदीवर का लिखा गीत 'प्रीत जहां की रीत सदा' उस दौर के हिट गीतों की लिस्ट में शुमार हुआ।

फिर आई शोर। 1972 में रिलीज फिल्म ने खामोशी से कामयाबी का शोर मचा दिया। पिता-पुत्र के रिश्तों को बुनती फिल्म ने लोगों को हंसाया तो रुलाया भी खूब। ये उस साल की सुपरहिट मूवी रही।

1974 की रोटी, कपड़ा और मकान समाज के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा जड़ती थी और सत्ता में बैठे रसूखदारों के कानों तक देश के युवा और मध्यम वर्ग की दुश्वारियां पहुंचाती थी। मल्टीस्टारर फिल्म को खूब पसंद किया गया। इसके गाने भी जोरदार थे।

1981 में आई 'क्रांति' ने एक बार फिर मनोज कुमार का दम दुनिया को दिखाया। सितारों से भरी फिल्म में देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा लोगों को खूब भाया। 'क्रांति' भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई।

मनोज कुमार ने 3 दशक तक फैन बेस को बनाए रखना। हर तबके तक अपनी बात पहुंचाना यही खासियत थी उनकी। मिट्टी से प्यार, संस्कृति पर गर्व और बड़ों का आदर-सम्मान करने का पाठ भी इस कलाकार ने अपनी अद्भुत शैली से सबके सिखाया। मुंह पर हाथ फेरकर, झुककर झटके से कनखियों से देखना एक स्टाइल बन गया, जिसकी नकल उतार कइयों ने कामयाबी बटोरी।

मनोज कुमार के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर

अभिनेता मनोज कुमार 87 वर्ष की आयु में शुक्रवार को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत भी गमजदा है। सलमान खान, संजय दत्त और रणवीर सिंह समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि जब भी भारतीय सिनेमा का जिक्र होगा वह हमेशा याद किए जाएंगे। अभिनेता सलमान खान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मनोज कुमार जी... एक सच्चे लीजेंड। आपने कभी न भूल पाने वाली फिल्में और यादें दीं। इसके लिए धन्यवाद...।

सुभाष घई ने लिखा, अलविदा मनोज जी। भारत के ग्रेट फिल्म निर्माता जिन्होंने अपनी कविता, गीत, ड्रामा, बेहतरीन शिल्पकला और सिनेमा के माध्यम से देशभक्ति से भरी फिल्मों का निर्माण किया। हमारी जेनरेशन में हम उनके प्रशंसक हैं और उनकी देशभक्ति और सिनेमाई अभिव्यक्ति की भावना की प्रशंसा करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक फिल्म निर्माता और व्यक्ति दोनों के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं यह नहीं भूल सकता कि कैसे वह हमेशा मेरी फिल्में देखने के बाद मुझे प्रेरित करते थे। न केवल मैं, बल्कि पूरा देश आपको याद करेगा।

अभिनेता मनोज कुमार के निधन से आहत संजय दत्त ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मनोज सर, आप हमेशा याद आएंगे।

इंस्टाग्राम पर मनोज कुमार की एक तस्वीर शेयर कर रणवीर सिंह ने भावनाएं व्यक्त कीं। वहीं, ईशा देओल ने लिखा, मनोज जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिले। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं।

रवि किशन ने कहा, भारत की बात सुनाता हूं... मनोज कुमार के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। भारत उनके अंदर कूट-कूट कर भरा था। उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके निधन से हुई क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है।

भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मनोज जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

पूनम ढिल्लों ने बताया कि मनोज कुमार ने सबको सिखाया कि सार्थक फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि मनोज जी प्रेरणादायी और महत्वाकांक्षी दोनों थे - हर कोई उनके जैसा निर्देशक बनना चाहता है। उन्होंने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि साफ-सुथरी और सार्थक फिल्में बनाने का उदाहरण भी पेश किया। मुझे लगता है कि जब देशभक्ति की फिल्मों की बात आती है, तो उन्होंने वाकई सबको दिखाया कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को कैसे प्रेरित किया जाए।

अभिनेत्री काजोल ने 'क्रांति', 'पत्थर के सनम', 'पूरब और पश्चिम', 'रोटी कपड़ा और मकान' फिल्म का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में ही नहीं थीं, वे भावनाएं थीं, वे प्रेरणा थीं। आप हमेशा याद किए जाएंगे।

सलमान खान के द बॉलीवुड बिग वन टूर से प्रशंसक निराश

सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाती नहीं दिख रही है।अब इस बीच सलमान ने अपने नए टूर का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम द बॉलीवुड बिग वन है। हालांकि, भाईजान के प्रशंसक उनके इस टूर से निराश हैं।

आइए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं।सिकंदर ने सलमान के फैंस को काफी निराश किया है। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों का दुख साफ झलकता है।सलमान के प्रशंसक उनसे अच्छी फिल्मों की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाईजान के प्रशंसकों का मानना है कि उन्हें सही स्क्रिप्ट और निर्देशक चुनने की जरूरत है।एक ने लिखा, भाई ऐसे टूर में समय बर्बाद मत करो। एक लिखते हैं, ये सब छोड़ो, कोई अच्छा निर्देशक चुनें, जो आपको बेहतर तरीके से पेश करना जानता हो।एक प्रशंसक ने सलमान की सेहत की चिंता करते हुए लिखा, भाई सारी चीजों को छोड़ो और आराम करो अपनी सेहत पर ध्यान दो। कृप्या थोड़ा सोच समझकर कोई स्क्रिप्ट चुनो। एक ने लिखा, ये सब छोड़ो भाई, अच्छी फिल्में निकालो।टूर में सलमान के साथ माधुरी दीक्षित, कृति सैनन, सारा अली खान, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी भी होंगे।यह टूर 4 मई को मैनचेस्टर में और 5 मई को लंदन में होगा।

निर्देशक डॉ. प्रशांत शाह का अभिनंदन

अभिनेता, निर्देशक, निर्माता डॉ. प्रशांत शाह द्वारा 200 से अधिक म्युजीकल अल्बम रिलीज करने, युट्युब में एक लाख से अधिक सब्सक्राईबर पूर्ण होने पर युट्युब द्वारा सीलवर बटन प्रदान करने एवं आगामी 14 अप्रैल को उनकी फिल्म बीट्टु की रिलीज पर उनका लव फॉर काऊ फाउंडेशन की ओर से चेयरमेन जसमत पटेल, मेनेजींग ट्रस्टी रिद्धीश जागीरदार, टस्ट्री मुकेश चौहान, जैन राजनीतिक चेतना मंच के दिनेश गोसर, रायल हेल्थ कल्ब के निदेशक डॉ. डी.डी. शाह द्वारा शॉल, स्मृति चिन्ह द्वारा अभिनंदन किया गया। यह अभिनंदन काचीगुडा स्थित रायल हेल्थ केयर सेन्टर में किया गया।

जसमत पटेल ने डॉ. प्रशांत को युट्युब मे एक लाख से अधिक सदस्य पूर्ण होने पर एवं आगामी फिल्म रिलीज पर शुभकामनाएं दी और उनसे निवेदन किया है कि वे अपनी फिल्म की कमाई का कुछ अंश गौसेवा मे दान देवे।

51 साल की मलाइका अरोड़ा ने कैमरे के सामने दिखाया हुस्न का जलवा

बॉलीवुड की फिटनेस और फैशन क्वीन मलाइका अरोड़ा आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस भले ही इन दिनों किसी फिल्म में नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन वो आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अक्सर फैंस का सारा अटेंशन अपनी ओर खींच लेती हैं। अब हाल ही में दें कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भले ही 51 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अपनी हॉटनेस से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं।अब हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनका सिजलिंग अंदाज देखकर फैंस एक बार फिर से मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का बेहद ही स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ है, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टनिंग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं।बालों का स्टाइलिश लुक में बन बनाकर और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने आउटलुक को बेहद ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। उनका ये कातिल अवतार इंटरनेट पर आते ही तबाही मचाने लग गया है।बता दें कि मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट भी काफी जबरदस्त है।

मलाइका अरोड़ा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं।एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस से फैंस के बीच लाइमलाइट बटौरती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से छाने लगता है। बता दें कि एक्ट्रेस बॉलीवुड की सबसे फिट लेडी हैं और आए दिन अपनी तस्वीरों से फैंस का अटेंशन अपनी ओर खींच लेती हैं।बता

मोनालिसा का पूल साइड लुक हुआ वायरल

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस और स्टनिंग लुक्स के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूल साइड की कुछ हॉट और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा ब्लू कलर की प्रिंटेड आउटफिट में नजर आ रही हैं और उनका यह बोल्ड अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है।मोनालिसा ने इन तस्वीरों के साथ एक रोमांटिक कैप्शन दिया- इश्क में।।, जिससे उनके फैंस के बीच और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया। कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। किसी ने उन्हें हॉटनेस क्वीन कहा, तो किसी ने बॉस लेडी का टैग दे दिया।मोनालिसा की यह तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल हो गईं। महज कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस के अलावा कई सेलेब्स ने भी उनके लुक की तारीफ की है। इससे पहले भी मोनालिसा अपनी वेकेशन और ट्रेडिशनल लुक वाली तस्वीरों को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं।मोनालिसा न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री बल्कि टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। बिग बॉस में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी।

नवरात्रि में कन्या पूजन से मिलेगी परेशानियों से मुक्ति

चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत 30 मार्च से सर्वार्थसिद्धि योग में हुई और नवरात्रि 6 अप्रैल तक रहेंगे। चैत्र नवरात्रि की धूम पूरे देश में है। माता की भक्ति में लीन भक्तों को अब अष्टमी और रामनवमी का इंतजार है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी और रामनवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो गई है। वहीं इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। नवरात्र के दौरान अलग-अलग दिनों में देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन नौ दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं सम्पन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान नौ कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो जातक को कभी धन की कमी नही होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है।

नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है। लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही हैं कि 2 से 10 साल तक उम्र की नौ कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाएं तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं।

कन्या पूजन महाष्टमी और रामनवमी

नवरात्रि में कन्या पूजन या कुमारी पूजा, महाष्टमी और रामनवमी दोनों ही तिथियों को किया जाएगा। महाष्टमी को मां महागौरी और रामनवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जिन घरों में महाष्टमी और महानवमी की पूजा होती है, वहां इस दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और उन्हें गिफ्ट बांटे जाते हैं।

पुराणों में है कन्या भोज का महत्व

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्री के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है। क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए दस वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं।

नवरात्रि की अष्टमी-नवमी तिथि पर करें कन्या पूजन

कन्या और देवी के शस्त्रों की पूजा

अष्टमी को विविध प्रकार से मां शक्ति की पूजा करें। इस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए।

हर आयु की कन्या का होता है अलग महत्व

2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन-धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख-समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी माना गया है। इनकी पूजन से रोग-मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या शांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है।

अष्टमी तिथि शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 08:12 बजे से शुरू हो रही है। यह तिथि 5 अप्रैल को रात 07.26 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में नवरात्र की अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजित मुहूर्त में 11:59 से लेकर 12:49 तक सकते है।

नवमी तिथि शुभ मुहूर्त

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को रात 07.26 मिनट से शुरू हो रही है। वहीं, इसका समापन 6 अप्रैल को रात 07.22 मिनट पर होगा। ऐसे में नवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन अभिजित मुहूर्त में 11:58 से लेकर 12:49 तक सकते है।

इस तरह करें पूजन

कन्या पूजन के दिन घर आईं कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी नौ कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्य का पहला हिस्सा देवी मां को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो मां दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर आपका सामाथ्र्य नहीं है तो आप अपनी इच्छानुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामथ्र्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है।

विवाह में देरी

यदि शादी में देरी हो रही है तो पांच साल की कन्या को खाना खिलाकर। श्रृंगार का सामान भेंट करें।

धन संबंधी समस्या

पैसों की कमी से परेशान हैं तो चार साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें।

शत्रु बाधा और काम में रुकावटें

नौ साल की तीन कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़ें दें।

पारिवारिक क्लेश

तीन और दस साल की कन्याओं को मिठाई दें।

बेरोजगारी

छह साल की कन्या को छाता और कपड़ें भेंट करें।

सभी समस्याओं का निवारण

पांच से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करें। सौन्दर्य सामग्री भी दें।

नीतिका शर्मा
ज्योतिषाचार्या एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर
श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर, अजमेर

अष्टमी या नवमी कब हवन करना होगा शुभ?

जानें नियम, मुहूर्त और महत्व

नवरात्र में हवन अष्टमी या नवमी किसी भी तारीख में कर सकते हैं, जो साधक अष्टमी के दिन नवरात्र व्रत का पारण करते हैं, वे अष्टमी के दिन हवन करें और जो लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, वे नवमी के दिन हवन करें। ऐसा माना जाता है कि हवन व कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं, वे हवन जरूर करें, तो चलिए हवन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।

चैत्र नवरात्र के दौरान कब और किस मुहूर्त में करें हवन?

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र नवरात्र के प्रमुख अनुष्ठान में हवन करना भी है। आमतौर पर अष्टमी और नवमी तिथि पर हवन करना शुभ माना जाता है। इन तिथियों पर आर ब्रह्म मुहूर्त में हवन कर सकते हैं। वहीं, नवमी तिथि पर हवन के लिए कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है।

हवन शुभ मुहूर्त

इस साल चैत्र नवरात्र की अष्टमी 5 अप्रैल को और नवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन हवन का मुहूर्त सुबह 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। वहीं, नवमी का हवन मुहूर्त सुबह 11 बजकर 58 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा।

हवन करते समय करें इन मंत्रों का जाप

ऊं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः पथ्यावतीः।।
स्वस्ति नो वृषपर्वा विश्वेदेवा स्वस्तये।।
ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे।।
ऊं दुं दुर्गायै नमः।।

हवन के नियम

हवन के लिए एक हवन कुंड तैयार करें।
हवन में घी, तिल, जौ, गुग्गल, लोबान, और अन्य हवन सामग्री का उपयोग करें।
मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करें।
हवन के बाद मां दुर्गा की आरती करें।

हवन का धार्मिक महत्व

हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
हवन से वातावरण शुद्ध होता है।
हवन करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।
हवन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।

कन्या पूजन में क्या है लांगुर का महत्व? इनके बिना अधूरी है पूजा

नवरात्र की पावन अवधि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। इस अवधि में साधक माता के निमित्त व्रत भी करते हैं।

नवरात्र के आखिर में कन्या पूजन भी जरूरी रूप से किया जाता है और इस दौरान लांगुर भी बुलाए जाते हैं, जिनके बिना कन्या पूजन अधूरा होता है।

किसका स्वरूप होते हैं लांगुरा

लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, नवरात्र की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। इस दिन पर 8-9 या इससे अधिक कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन करते हैं व उन्हें भोजन कराते हैं। इस दौरान इन कन्याओं के साथ एक बालक भी बिठाया जाता है, जिसे लांगुर कहते हैं। जहां छोटी कन्याएं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, वहीं लांगुरा को भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है।

क्यों जरूरी है लांगुरिया

भैरव बाबा मां दुर्गा के पहरेदार माने गए हैं। यही कारण है कि नवरात्र के कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के साथ लांगुर को भी बिठाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मान्यता है भैरव बाबा हमेशा मां दुर्गा की पहरेदारी के लिए उनके साथ रहते हैं। ऐसे में कन्याओं की तरह की लांगुरिया भी पूजन करना चाहिए और उन्हें भी श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है।

वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोग 2 लांगूर भी बुलाते हैं, जिनमें से एक भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है और दूसरे को भगवान गणेश का। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा-अर्चना या शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। ऐसे में कहीं-कहीं कन्या पूजन के दौरान दो लांगुरिया बैठाने का विधान है।

देवी सती के अंगों से बने हैं 51 शक्तिपीठ, दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट

जब उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता शिव जी का अपमान कर हैं, तो उन्होंने अग्नि कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब शिव जी को इस बात का पता चला, तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर का दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के शरीर को और सम्पूर्ण विश्व में घूमने लगे।

इससे पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, जिसे रोकना जरूरी था। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग व आभूषण जिन स्थानों पर गिरे, आज वहां शक्तिपीठ स्थापित आज हम आपको इन्हीं 51 शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका वर्णन देवी पुराण में मिलता है।

देवी के 51 शक्तीपीठ

देवी बाहुला – माना जाता है कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में माता सती का बायां हाथ गिरा था। आज अजेय नदी के पास माता सती की देवी बाहुला के रूप में पूजा की जाती है।

मंगल चंद्रिका – पश्चिम बंगाल के ही वर्धमान जिले के पास उज्जनि में माता मंगल चंद्रिका रूप विराजमान हैं। इस स्थान पर देवी सती की दाईं कलाई गिरी थी।

भ्रामरी देवी – मान्यताओं अनुसार, पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी में माता सती का बायां पैर गिरा था। आज यहां पर मां सती के भ्रामरी रूप की पूजा होती है।

देवी जुगाड्या – पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास माता सती जुगाड्या रूप में विराजमान है। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि देवी का दाएं पैर का अगूंठा गिरा था।

मां कालिका – पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता के कालीघाट में कालीपीठ स्थापित है। इस पीठ को लेकर मान्यता है कि इस स्थान पर मां के बाएं पैर का अगूंठा गिरा था। यहां पर माता को कालिका नाम से पूजा जाता

महिषमर्दिनी – माना जाता है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मां सती का भ्रूण भी गिरा था। इस स्तान पर माता महिषमर्दिनी नाम से विद्यमान हैं।

देवगर्भ – मान्यताओं के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बीरभुम जिले में माता सती की अस्थियां गिरी थी। आज इस स्थान पर देवगर्भ के नाम से विराजमान हैं।

देवी कपालिनी – कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के ही पूर्व मेदिनीपुर जिले में मां सती की बायीं एड़ी गिरी थी। यहां पर माता के कपालिनी रूप की पूजा की जाती है।

फुल्लरा – पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मां सती होंठ भी गिरे हैं। इस स्थान पर माता सती फुल्लरा नाम से जानी जाती हैं।

अवंति – माता सती का ऊपरी होंठ मध्य प्रदेश के उज्जयिनी में क्षिप्रा नदी तट पर गिरा था, जहां उन्हें अवंति नाम से जाना जाता है।

नंदिनी – पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम जिले माता सती के नंदिनी रूप की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार, इस स्थान पर देवी सती के गले का हार गिरा था।

देवी कुमारी – पश्चिम बंगाल में ही रत्नाकर नदी के पास माता सती का दायां कंधा गिरा था। आज यहां देवी कुमारी नाम से प्रसिद्ध

देवी उमा – भारत नेपाल बॉर्डर पर मां सती का बायां कंधा गिरा था। जहां देवी की पूजा उमा रूप में की जाती है।

कालिका देवी – ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में माता सती के पैर की हड्डी गिरी थी। यहां देवी कालिका रूप में विद्यमान हैं।

विमला देवी – मान्यताओं के अनुसार, बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद जिले में माता सती के माथे का मुकुट गिरा थी। इस स्थान पर देवी विमला नाम से पूजी जाती हैं।

मां भवानी – माना जाता है कि बांग्लादेश के ही चिट्टागौंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत के पर मां की दायीं भुजा गिरी थी। यहां मां सती को भवानी नाम से भी जाना जाता है।

सुनंदा – मान्यताओं के अनुसार, बांग्लादेश में शिकारपुर में स्थित बरिसल में माता सती की नाक गिरी थी। यहां पर माता का सुनंदा रूप विराजमान हैं।

देवी जयंती – बांग्लादेश के जयंतिया परगना नामक स्थान पर मां सती की बायीं जांघ गिरी थी। यहां पर देवी जयंती के नाम से विद्यमान हैं।

महालक्ष्मी – मान्यताओं के अनुसार, बांग्लादेश के जैनपुर गांव में मां का गला गिरा थी। यहां देवी की पूजा महालक्ष्मी के रूप में होती है।

यशोरेश्वरी – माना है कि बांग्लादेश के खुलना जिले में मां सती के हाथ और पैर का कुछ भाग गिरा था। यहां पर देवी को यशोरेश्वरी नाम से पूजा जाता है।

देवी अर्पण – बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में भी मां का एक शक्तिपीठ स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान देवी के बाएं पैर की पायल गिरी थी। यहां देवी को अपर्णा के रूप में जाना जाता है।

देवी इंद्रक्षी – श्रीलंका में भी शक्तिपीठ स्थापित है, जिसे लंका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर मां के दाएं पैर की पायल थी। यहां माता के इंद्रक्षी रूप की पूजा-अर्चना होती है।

माता ललिता – मान्यताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रयाग संगम में मां सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। यहां माता सती की पूजा ललिता रूप में की होती है।

देवी मणकर्णी – वाराणसी में मणिकर्णिका पर स्थित मां विशालाक्षी मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि इस स्थान पर मां के कान की मणि गिरी थी, इसलिए उन्हें यहां पर विशालाक्षी या मणकर्णी नाम से पूजा जाता है।

देवी शिवानी – पौराणिक प्रसंग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट माता सती का दायां वक्ष गिरा था। यहां पर देवी शिवानी नाम से विराजमान हैं।

चूड़ामणि – उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मां सती के केश की चूड़ामणि गिरी थी। जहां माता सती की पूजा उमा के रूप में की जाती है।

श्रावणी – तमिलनाडु के देवी का मंदिर स्थापित है, जिसे लेकर मान्यता है कि इस स्थान पर मां सती की पीठ गिरी थी। यहां पर उन्हें श्रावणी नाम से पूजा जाता है।

सावित्री – मान्यताओं के अनुसार, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां सती की एड़ी गिरी थी। इस स्थान पर माता को सावित्री रूप में जाता है।

देवी गायत्री – राजस्थान के अजमेर में देवी सती की गायत्री रूप में पूजा होती है। माना जाता है कि गायत्री पर्वत पर मां सती की कलाई गिरी थी।

मां काली – मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शोंदेश शक्तिपीठ स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार, यहां मां सती बायां नितंब गिरा था।

देवी नर्मदा – वहीं मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी तट के पास मां सती का दायां नितंब गिरा था। यहां पर देवी को नर्मदा नाम से पूजा जाता है।

देवी नारायणी – तमिलनाडु के कन्याकुमारी-तिरुवंतपुरम मार्ग में मां सती की ऊपरी दाड़ गिरी यहां देवी का नारायणी रूप विराजमान हैं।

वाराही – उत्तर प्रदेश के पंचसागर में मां सती की निचली दाढ़ गिरी थी। यहां पर देवी की वाराही नाम से पूजा-अर्चना की जाती है।

श्री सुंदरी – आंध्र प्रदेश के कुरनूल श्रीशैलम में मां सती का दाएं पैर की पायल गिरी यहां पर देवी को श्री सुंदरी नाम से पूजा जाता है।

चंद्रभागा – गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास मां का अमाशय गिरा था। यहां देवी की पूजा चंद्रभागा नाम से की जाती है।

भ्रामरी देवी – महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी घाटी में मां सती ठोड़ी गिरी थी। यहां पर माता भ्रामरी नाम से पूजित हैं।

राकिनी देवी – आंध्र प्रदेश में माता सती को समर्पित कोटिलिंग्शेवर मंदिर स्थापित है, जहां उनकी पूजा राकिनी रूप में की जाती है। माना जाता है कि इस स्तान पर मां सती का गाल गिरा था।

देवी अंबि– राकिनी रूप में राजस्थान के भरतपुर में मां सती के बायें पैर की अंगुली गिरी थी। यहां पर माता सती को अंबि नाम से जाना व पूजा जाता है।

महाशिरा – नेपाल में भी माता का एक शक्तिपीठ स्थापित है, जो पशुपति मंदिर के पास स्थित है। ऐसा माना है कि यहां देवी के दोनों घुटने गिरे थे। आज यहां गुजयेश्वरी मंदिर स्थापित है, जो मांमहाशिरा या महामाया के रूप की पूजी जाती हैं।

गंडकी चंडी – नेपाल के पोखरा में गण्डकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ मंदिर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार, इस स्ठान पर देवी का गिरा था। यहां देवी को गण्डकी रूप में पूजा जाता है।

जयदुर्गा देवी – कर्नाटक के एक स्थान पर मां सती के दोनों कान गिरे थे। इस स्थान को जयदुर्गा के नाम से जाना जाता है।

कोट्टरी देवी – पाकिस्तान में भी माता का एक शक्तिपीठ स्थापित है, जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रान्त की लारी तहलीस में हिंगलाज में स्थापित है। माना जाता है कि यहां देवी सती का सिर गिरा था।

महिष मर्दिनी – माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता सती की आंखें गिरी थीं। इसलिए इस पर नैना देवी मंदिर स्थापित है।

देवी अंबिका – हिमाचल के कांगड़ा जिसे माता सती की जीभ गिरी थी। यहां पर माता सती के अंबिका रूप की पूजा की जाती है।

देवी महामाया – कश्मीर के पहलगाम स्थित अमरनाथ में मां सती का गला गिरा था। यहां देवी को के रूप में पूजा जाता है।

त्रिपुरमालिनी – पंजाब के जालंधर में माता सती का दायां वक्ष गिरा था। यहां पर देवी की पूजा त्रिपुरमालिनी के रूप में की जाती है।

माता अंबाजी – गुजरात के अंबाजी मंदिर स्थित है, जहां देवी सती का ह्रदय गिरा था। यहां माता पूजा अंबाजी नाम से की जाती है।

मां दाक्षायनी – तिब्बत में मानसरोवर के पास मानस शक्तिपीठ स्थापित है। यहां माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। इस स्थान पर शक्तिपीठ की देवी को दक्षायणी नाम से जाना जाता है।

देवी विमला – उड़ीसा में भुवनेश्वर में माता सती मां सती की पूजा विमला रूप में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार, यहां देवी की नाभि गिरी थी।

त्रिपुर सुंदरी – त्रिपुरा के माताबढ़ी पर्वत शिखर के उदरपुर में माता सती कोत्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। मान्यताओं के अनुसार, यहां देवी का दायां पैर गिरा

कामाख्या देवी – ऐसा कहा जाता है कि असम के गुवाहाटी के कामगिरी में माता सती की योनि गिरी थी। यहां कामाख्या मंदिर स्थापित है, जो काफी प्रसिद्ध भी है।

संपादकीय

भारत पर 'जैसे को तैसा टैरिफ'

जैसा कि पूर्व घोषित था, उसी के मुताबिक अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 फीसदी 'जैसे को तैसा टैरिफ' भारत पर थोपने की घोषणा की है। इसे 'मुक्ति-दिवस' कहा जा रहा है। इस जमात में जापान, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील और सिंगापुर आदि देश भी शामिल हैं, लेकिन अमरीका ने भारत के संदर्भ में यह 'दोस्ती का ढोल' पीटने के बावजूद किया है। हालांकि भारत-अमरीका के बीच 43 लाख करोड़ रुपए का 'व्यापार सौदा' भी निर्णायक चरण में है। इस साल के अंत तक इस पर मुहर लगाई जा सकती है। क्या उस व्यापारिक विमर्श में टैरिफ का मुद्दा शामिल नहीं किया जा सकता था? एलन मस्क की टेस्ला कार, प्रीमियम बाइक हार्ले डेविडसन और अमरीकी बर्बन व्हिस्की आदि पर भारत पहले ही टैरिफ-कटौती की घोषणा कर चुका है। अमरीका अपना गेहूं, सेब, बेबी कॉर्न, मक्का सहित कई अन्य अनाज भी भारत में खपाना चाहता है। क्या भारत अनाजों की पैदावार में सक्षम नहीं है? यदि हम सक्षम हैं, तो 'जैसे को तैसा टैरिफ' झेलने या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लिहाजा सबसे बड़ा बाजार भी है। चीन भी भारत के साथ अपने कारोबारी समीकरणों, खासकर आयात, को विस्तार देने के पक्ष में है। यदि अमरीका के साथ, टैरिफ चस्पां करने के बाद, व्यापार प्रभावित होता है, तो यूरोप और एशिया में नई संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। भारत का 'यूरोपीय संघ' के साथ 'मुक्त व्यापार समझौता' भी आखिरी दौर में है। भारत के कुल व्यापार का करीब 14 फीसदी यूरोपीय संघ के साथ होता है, जबकि अमरीका के साथ करीब 18 फीसदी है। बहुत ज्यादा फासला नहीं है। इसे बढ़ा कर भरपाई की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमरीका के देश भी भारत के नए व्यापारिक साझेदार बनने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को मात देने का सबसे कारगर तरीका यह है कि बाकी देश आपस में मौजूदा टैरिफ के आधार पर ही वसूली करें। इससे अमरीका दुनिया के व्यापारिक दायरे में अलग-थलग पड़ सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप 'जैसे को तैसा कर' लगाकर अमरीका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के पक्षधर हैं, जबकि यह योजना पलटवार साबित हो सकती है। अमरीका में टैरिफ घोषणा के बाद से खलबली मची है। कई क्षेत्रों के व्यापारी और उद्योगपति सकते में हैं। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अमरीकी अर्थव्यवस्था में 35 फीसदी मंदी के आसार हैं। औसतन हर अमरीकी परिवार पर 35,000 रुपए सालाना का बोझ बढ़ सकता है। टैरिफ से आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और खाद्य उत्पाद आदि महंगे हो जाएंगे, नतीजतन महंगाई और उसके साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। खुद राष्ट्रपति ऐसी आशंकाएं जता चुके हैं, लेकिन उनके सलाहकारों के अनुमान हैं कि 'जैसे को तैसा टैरिफ' से अमरीका के खजाने में 43 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व आएगा। अमरीका के करीब 200 व्यापारिक साझेदार हैं। उनमें देश, प्रदेश-इलाके, क्षेत्रीय संघ आदि शामिल हैं। टैरिफ वर्ग करीब 12,500 हैं। 'जैसे को तैसा टैरिफ' के बाद कई और नए टैरिफ सामने आएंगे। अमरीकी प्रशासन के लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा। भारत के लिए भी नई चुनौतियां आएंगी। बहरहाल चीन की प्रतिक्रिया भी गौरतलब है। चीनी विदेश मंत्री ने ट्रंप के टैरिफवाद को 'ब्लैकमेलिंग' करार दिया है। यह अमरीका को कितना फायदा या नुकसान देता है, यह सोचने के बजाय भारत को अपने अनुकूल निर्णय लेने चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने 26 फीसदी 'जैसे को तैसा टैरिफ' भारत पर थोपने की घोषणा की है। इसे 'मुक्ति-दिवस' कहा जा रहा है। इस जमात में जापान, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील और सिंगापुर आदि देश भी शामिल हैं, लेकिन अमरीका ने भारत के संदर्भ में यह 'दोस्ती का ढोल' पीटने के बावजूद किया है। हालांकि भारत-अमरीका के बीच 43 लाख करोड़ रुपए का 'व्यापार सौदा' भी निर्णायक चरण में है। इस साल के अंत तक इस पर मुहर लगाई जा सकती है। क्या उस व्यापारिक विमर्श में टैरिफ का मुद्दा शामिल नहीं किया जा सकता था? एलन मस्क की टेस्ला कार, प्रीमियम बाइक हार्ले डेविडसन और अमरीकी बर्बन व्हिस्की आदि पर भारत पहले ही टैरिफ-कटौती की घोषणा कर चुका है। अमरीका अपना गेहूं, सेब, बेबी कॉर्न, मक्का सहित कई अन्य अनाज भी भारत में खपाना चाहता है। क्या भारत अनाजों की पैदावार में सक्षम नहीं है? यदि हम सक्षम हैं, तो 'जैसे को तैसा टैरिफ' झेलने या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लिहाजा सबसे बड़ा बाजार भी है। चीन भी भारत के साथ अपने कारोबारी समीकरणों, खासकर आयात, को विस्तार देने के पक्ष में है।

सरकार को पता चला कि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ में अल्लाह को दिया जा चुका है

वक्फ को लेकर उभरता विवाद

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

जाहिर है जब सम्पत्ति अल्लाह को समर्पित कर दी गई है तो उसकी सार संभाल तो इसी संसार के कुछ लोग अल्लाह की तरफ से करेंगे। अल्लाह की तरफ से सार संभाल करने का अधिकार इन 'कुछ' लोगों को कौन देता है, यह प्रश्न सदा विवाद का विषय बना रहेगा। अल्लाह को दान की गई इन सम्पत्तियों से जो आमदन होती है उसका कुछ हिस्सा, इन सम्पत्तियों की सार संभाल करने वाला व्यक्ति अपने मेहनताने के एवज में अपने पास भी रख सकता है। इसलिए विवाद बढ़ता रहेगा। जिसके नियंत्रण में अल्लाह को दी गई यह सम्पत्ति आ जाती है, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। 1947 में अंग्रेजों के चले जाने के उपरांत कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उसने 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया।

वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ कोई भी चल या अचल सम्पत्ति अल्लाह को समर्पित कर देना। जाहिर है जब सम्पत्ति अल्लाह को समर्पित कर दी गई है तो उसकी सार संभाल तो इसी संसार के कुछ लोग अल्लाह की तरफ से करेंगे। अल्लाह की तरफ से सार संभाल करने का अधिकार इन 'कुछ' लोगों को कौन देता है, यह प्रश्न सदा विवाद का विषय बना रहेगा। अल्लाह को दान की गई इन सम्पत्तियों से जो आमदन होती है उसका कुछ हिस्सा, इन सम्पत्तियों की सार संभाल करने वाला व्यक्ति अपने मेहनताने के एवज में अपने पास भी रख सकता है। इसलिए विवाद बढ़ता रहता है। जिसके नियंत्रण में अल्लाह को दी गई यह सम्पत्ति आ जाती है, वह इसे छोडऩा नहीं चाहता। 1947 में अंग्रेजों के चले जाने के उपरांत कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उसने 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। सरकार को पता चला कि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ में अल्लाह को दिया जा चुका है। कहा जाता है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के नाम पर अल्लाह को दी जा चुकी है। वक्फ के पास इस समय देश की आठ लाख एकड़ से अधिक जमीन है। बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी। इस मसले की जड़ तक जाना जरूरी है। दरअसल इस देश में अरबों, तुर्कों व मुगलों के हमले 712 में शुरू हो गए थे। 1200 तक आते-आते उन्होंने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसमें से कुछ हिस्सा अलग-अलग समय में अल्लाह को भी दे दिया। व्यावहारिक रूप से अल्लाह को देने का मतलब मुल्ला मौलवियों को देना ही था। ये मुल्ला मौलवी इस देश के रहने वाले तो थे नहीं, बल्कि ये भी इन्हीं हमलावरों के साथ मध्य एशिया से आए थे। एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) के राज में देसी मुसलमानों (डीएम) को लगता था कि शायद मुल्ला मौलवी वक्फ की इस सम्पत्ति से, उनकी हालत सुधारने के लिए भी ध्यान देंगे, लेकिन न तो ऐसा हुआ और न ही आगे होने की सम्भावना थी, क्योंकि 1954 में वक्फ बोर्ड बन जाने से सारे अधिकार कानूनी रूप से एक वर्ग विशेष के हाथों में दे दिए गए। देसी मुसलमान, जिन्हें एटीएम मूल का मुसलमान पसमांदा, अरजाल, अलजाफ, न जाने और कितने निंदनीय शब्दों से

सम्बोधित करता है, अपने ही देश में अपनी ही सम्पत्ति अशरफ के हाथों लुटती देखता रहा। समय समय पर इस वक्फ अधिनियम में संशोधन होते रहे और एटीएम का शिकंजा और कसता गया। भारत के मुसलमानों में दो वर्ग हैं, पहला वर्ग उन मुसलमानों का है जिनके वंशज इस मुल्क में हमलावर के रूप में आए थे। यह वर्ग एटीएम कहलाता है। दूसरा वर्ग उन मुसलमानों का है जो यहीं के लोग हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हमलावरों के मजहब में शामिल हो गए थे। उन्हें देसी मुसलमान या डीएम कहा जाता है। इस मुल्क में यदि कोई सम्पत्ति अल्लाह के नाम पर दान भी की जाती है तो वह यकीनन देसी मुसलमानों की ही हो सकती है। हमलावर अरब, तुर्क या मुगल अपने देशों की जमीन या सम्पत्ति तो उठाकर लाए नहीं थे जिसे उन्होंने हिन्दुस्तान में आकर वक्फ के नाम कर दिया। वक्फ का असूल है कि जो सम्पत्ति वक्फ को जाती है वह उसकी अपनी सम्पत्ति होनी चाहिए। दूसरे की कब्जाई गई सम्पत्ति को वक्फ के नाम नहीं किया जा सकता। अब केवल उदाहरण के लिए यदि अपने वक्त में औरंगजेब ने कोई जमीन वक्फ की हो तो उसको वक्फ माना ही नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके पूर्वजों द्वारा बलपूर्वक कब्जाई सम्पत्ति है। एक और उदाहरण लिया जा सकता है। दो फरीकों में किसी सम्पत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है। पहले फरीक के कब्जे में वह सम्पत्ति है लेकिन उसको लग रहा है कि वह केस हार जाएगा। इसलिए वह केस का फैसला आने से पहले ही वह सम्पत्ति मौलवी से मिल कर वक्फ के नाम कर देता है। वक्फ बोर्ड की दलदल में फंस गई यह सम्पत्ति अब वापस असली मालिक को नहीं मिल सकती। यह नियम बना पंखा है कि एक बार वक्फ के नाम हो चुकी सम्पत्ति वापस नहीं हो सकती। असली मालिक वक्फ बोर्ड के इस तानाशाही रवैए के खिलाफ फरियाद भी उसी वक्फ बोर्ड के पास कर सकता है। हाई कोर्ट में अपील तक नहीं की जा सकती। अभी वक्फ बोर्ड अधिनियम में असमानी धारा है जिसे अधिनियम में धारा 40 कहा जाता है। इसके अनुसार यदि वक्फ बोर्ड के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि कोई जायदाद वक्फ की है तो वह उसे वक्फ सम्पत्ति घोषित कर सकता है। कोई सम्पत्ति किसकी है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है न कि विश्वास की। लेकिन वक्फ बोर्ड सम्पत्ति के मामले में प्रमाण की बजाय विश्वास को ही तरजीह देता है। यानी वक्फ स्वयं भी बहुत सी सम्पत्ति को, स्वयं ही विश्वास करके, वक्फ की सम्पत्ति घोषित कर देता है। इस प्रकार भारत की बहुत सी सम्पत्ति को उसने खुद ही वक्फ सम्पत्ति घोषित कर रखा है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की तो अनेक सम्पत्तियों को वक्फ अपना मानता ही है और सरकार ने भी अभी तक इस मामले में मौन स्वीकृति दे रखी थी। नए अधिनियम में इसको रोकने का प्रयास किया गया है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि वक्फ की इन सम्पत्तियों से अर्जित आय का लाभ देसी मुसलमानों को मिलना चाहिए था, उनको अपने रोजगार चलाने में मदद की जानी चाहिए थी, उनके लिए अच्छे आधुनिक स्कूल खोले जाने चाहिए थे। लेकिन उनके विकास के नाम पर उनके लिए मध्यकालीन मदरसे खोल दिए गए और बाकी आमदन एटीएम ने अपने लिए रख ली। मुगलों का राज खत्म हो जाने के बाद भी बहुत ही शातिराना तरीके से उनके वंशजों ने इस मुल्क की बहुत बड़ी सम्पत्ति पर कब्जा जमा रखा है। उस कब्जे को छुड़ा कर, यदि उसे मुसलमानों को ही देना है तो उसे देश के देसी मुसलमानों के हवाले किए जाने की सख्त जरूरत है। वक्फ बोर्ड में किए जा रहे परिवर्तन उस दिशा में उठाए गए कदम कहे जा सकते हैं। भारत का देसी मुसलमान तो वक्फ बोर्ड अधिनियम में किए जा रहे परिवर्तनों से प्रसन्न है, लेकिन एटीएम भयंकर विरोध कर रहा है। कुछ दिन पहले ही वह औरंगजेब की कब्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब तो मुगल साम्राज्य समाप्त होने से पहले भारत में जो जायदाद वक्फ के बहाने उनको उनके भरण पोषण के लिए दे गया था, वह भी उनके हाथों से छिन्नती नजर आ रही थी। यह सम्पत्ति अब देसी मुसलमानों के हित के लिए प्रयोग होने वाली थी।

दृष्टि कोण

इतिहास पुनर्लेखन का काम कैसे हो?

भारत वर्ष में इन दिनों इतिहास पुनर्लेखन लगातार बहस का विषय बना हुआ है। इतिहास लेखन में आमतौर पर वस्तुपरक लेखन का दावा किया जाता है, किन्तु यह दावा आंशिक रूप से ही सही है। इतिहास लेखन में व्यक्तिपरक लेखन की संभावना हमेशा बनी रहती है। ज्यादातर इतिहास विजेताओं द्वारा लिखे गए, इसलिए उनमें विजेताओं का महिमामंडन या उनके पक्ष को सही ठहराने की वृति हमेशा बनी ही रहती है। किन्तु जहां भी किसी पक्ष से असंबद्ध लेखकों द्वारा लेखन हुआ वहां-वहां इतिहास की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता की कसौटी पर तुलनात्मक रूप से खरी उतरती है। भारतवर्ष का आधुनिक प्रचलित इतिहास मुस्लिम आक्रांताओं, अंग्रेजी शासन और वाम विचारधारा से जुड़े इतिहासकारों की देन है, जिसमें बहुत मेहनत से काम हुआ है। किन्तु उसमें निष्पक्षता का स्तर असंदिग्ध नहीं है। क्योंकि उन सभी के अपने-अपने निहित स्वार्थ हैं या भारत को देखने की अपनी विशिष्ट दृष्टि है, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। मुस्लिम आक्रांता ऐसे देशों से आए थे जहां खाने, जीने के साधन पर्याप्त मात्र में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए लूट के अतिरिक्त दूसरा लक्ष्य था कि भारत में ही बस कर यहां की सुख-सुविधाओं का अपनी इच्छा से उपभोग कर सकें। उनके लिए दूसरे देशों में जाकर इस्लाम को फैलाना भी पुण्य का काम था, इसलिए अनेक देशों को जीत कर इस्लाम फैलाने के लिए भी उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और अपने इस लक्ष्य को जायज ठहराने की दृष्टि से इतिहास लेखन हुआ। अंग्रेजों की दृष्टि तत्कालीन ईसाई दृष्टि थी, जिसके अनुसार जो भी लोग ईसाइयत का ज्ञान नहीं रखते और मानते वे लोग बर्बरता में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए हमें वहां ईसाइयत का संदेश लेकर जाना है। यह हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हालांकि यूरोप का ठंडा जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव भी उसके पीछे का कारण रहा है, जिस कमी को पूरा करने के लिए उपनिवेशवाद का सहारा लिया गया और तमाम एशियाई, अफ्रीकी और अमरीकी देशों पर कब्जा करने की मुहिम शुरू हुई और कुछ देशों की आबादी को पूरी तरह नष्ट करके खुद वहां के मालिक बन गए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया। जहां इस तरह का कब्जा करके पूरी आबादी को ही प्रतिस्थापित करना संभव नहीं था, वहां उन्होंने स्थानीय सभ्यताओं और संस्कृतियों को घटिया साबित करने और पाश्चत्य सभ्यता को स्थापित करके अपने शासनों को सुनिश्चित करने का कार्य किया। इतिहास लेखन का उनका कार्य इसी दृष्टि से किया गया। ज्यादातर परिकल्पनाएं जिनकी स्थापना की गई, वे उनके उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने वाली थीं। बड़ी चालाकी से उन्होंने, जो तथ्य या घटनाएं उन्हें अपने उपयुक्त नहीं लगीं, उनका विलोपन कर दिया गया या अनदेखा किया गया। हालांकि उन्होंने तथ्यात्मकता और वस्तुपरकता को आधार बना कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना की, किन्तु तथ्यों और घटनाओं की व्याख्या अपने यूरोपीय दृष्टिकोण से करने के कारण बहुत सी जाने या अनजाने गलतियां कीं जो उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी थीं। उदाहरण के लिए भारत की दयनीय स्थिति का झूठा चित्रण करके अपने आप को उन्नत साबित करने का काम नई शिक्षा द्वारा किया गया, जबकि धर्मपाल द्वारा इकठ्ठे किए गए ब्रिटिश रिकॉर्ड के आंकड़ों से यह साबित होता है कि उनका यह कथानक झूठा है। 1822-25 के मद्रास प्रेसीडेंसी में किए गए सर्वे के अनुसार उस समय भी प्रेसीडेंसी में 11575 स्कूल और 1094 कॉलेज थे जिनमें क्रमशः 157195 और 5431 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। जातिगत बनावट के बारे में भी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं, जिनके अनुसार तमिल भाषी क्षेत्र में शूद्र और उनसे निचली जातियों से संबंधित 70 से 80 फीसदी विद्यार्थी थे, उडिया क्षेत्र में 62 फीसदी, 54 फीसदी मलयालम भाषी क्षेत्रों में और 50 फीसदी तेलगु क्षेत्रों में थे। यही बात यहां उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के बारे में भी लागू होती है। उत्तरप्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी लोहे का प्रयोग होता था, किन्तु 18वीं शताब्दी सीई तक भी यहां बढिया किस्म का स्टील बनाया जाता था, यह बात कम ही लोग जानते हैं। उस समय प्रति वर्ष उच्च कोटि का स्टील बनाने वाली कम से कम 10000 ऐसी भट्ठियां कार्यरत थीं जो साल में बीस टन तक स्टील तैयार कर रही थीं। चेचक के इलाज के लिए इनोकुलेशन की जाती थी और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अंग मरम्मत की जाती थी। सुश्रुत के सदियों बाद तक यह विद्या 18वीं शताब्दी तक मौजूद थी। यह भारतीय सेवा के तत्कालीन अफसर डा. बैरी द्वारा वर्णित पूना में उनके द्वारा देखे गए एक आपरेशन से पता चलती है।

कुछ अलग

मंच हमारा, माला तेरी...

जिस समय वे मेरे यहां आए, चिंता की लकीरें ललाट पर स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। वे मेरे परमप्रिय थे। सो बोला-'क्यों, क्या बात है? मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। इतने चिन्तित होने की बात क्या है?' वे और अधिक गमगीन हो गए। लगभग रुआंसे होकर बोले-'शर्मा मुझे बचा लो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरी इज्जत दांव पर लग गई है। तुम तो घर के आदमी हो, दूसरे से कह भी नहीं सकता।' मैंने कहा-'गिरधर जी मामला क्या है? आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी इज्जत दांव पर लगा दूंगा, आखिर बात क्या है?' गिरधर जी अपना मुंह मेरे कान के पास लाए और बोले-'शर्मा अपनी संस्था का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष बीतने को आया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। साफ बात है संस्था आर्थिक विषमता में जी रही है। इस वर्ष सम्मान समारोह नहीं हुआ तो सारी बात खाक में मिल जाएगी, दूसरा गुट बदनामी करने पर तुला है।' मैंने कहा, 'तो कहिए, मुझे करना क्या है?' गिरधर जी बोले, 'तुम ऐसा करो, इस वर्ष का सम्मान ले लो। मेरी और संस्था की नाक बच जाएगी।' मैं उनकी बात पर हंस पड़ा और बोला, 'इसमें गिरधर जी चिन्ता की क्या बात है? इस वर्ष का साहित्य शिरोमणि सम्मान मैं ले लूंगा। आप तो चिन्ता को त्यागो और सम्मान की तैयारी करो।' गिरधर जी लगभग पसर से गए और मौन साध गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने फिर कहा-'क्यों अब क्या बात है? मैं सम्मान ले लूंगा, मना थोड़े ही कर रहा हूं।' 'शर्मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैंने अभी कहा कि संस्था पूरी तरह दिवालिया है। मंच तो दे सकती है, लेकिन माला और दुशाला का इंतजाम कैसे होगा, सम्मान लेने वाले तो बहुत से हैं। तुम्हारी खुशामद करने का मेरा मतलब यही है कि तुम मंच के अलावा सारा इंतजाम नेपथ्य से करो। वरना संस्था की मान्यता खतरे में पड़ सकती है, सम्मान का सारा व्यय तुम्हें ही संभालना होगा।' गिरधर जी की बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। हालांकि सम्मान की लार मेरे मुंह में आ चुकी थी। वैसे भी साहित्य का कोई पुरस्कार सम्मान मुझे अभी तक नहीं मिल पाया था। मैंने कहा-'मैं आपकी बात समझ गया गिरधर जी, लेकिन पैसे से तो मैं भी बहुत तंग हूं, गए महीने पी. एफ. से लोन लेकर घर की व्यवस्था की थी। अब यह सम्मान आ गया। मुझे यह सम्मान, अपमान जैसा लग रहा है। मंच आपका और माला-दुशाला मेरा, बात कुछ हजम नहीं हो रही।' गिरधर जी अत्यंत निराश भाव से बोले-'तो फिर रहने दो शर्मा। मैं किसी और से बात करता हूं। मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आया था कि घर के आदमी हो। तुम्हारा सम्मान भी कभी नहीं हुआ। फूल-मालाओं से लदवा देता सार्वजनिक रूप से पीछे क्या हुआ, किसने देखा है। मान-सम्मान के लिए तो लोग पता नहीं क्या-क्या जोड़-तोड़ करते हैं। तुम क्या पत्नी के आभूषण दांव पर नहीं लगा सकते? देखो, सभी जगह ऐसा होता है, खर्चा क्या है, कार्ड छपवाने हैं, पचास मालाएं लानी हैं, शॉल लाना है और दो सौ आदमियों के जलपान की व्यवस्था करनी है। कुल पांच हजार में 'साहित्य शिरोमणि' हो जाओगे।' अब मैं सोच में पड़ गया हूं।

देश दुनिया से

पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौती को गंभीरता से लेने की जरूरत

यहां मेरा उद्देश्य हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंदरूनी स्थिति को उजागर करना है। आज के अखबारों ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का कथित बयान भी छापा है, जिसमें उन्होंने दिवंगत पीए संगमा द्वारा संसद में 2014 में दिए एक भाषण का एक वीडियो साझा किया है, संगमा उसमें कथित तौर पर कुकी लैंड और क्षेत्र में अन्य छोटे-छोटे राज्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। बीरेन सिंह ने कहा कि आज भी मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य को अस्थिर किया जा सके। इस बयान पर मेघालय के मुख्यमंत्री और पीए संगमा के बेटे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने पिता का बचाव किया है। मैंने भविष्य में बांग्लादेश (और पाकिस्तान) की संभावित भूमिका और हमारी अपनी आंतरिक खींचतान (महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा दिए जा रहे असंयमित बयानों को देखते हुए) को सामने लाने के लिए गहरे उतरकर मनन किया है। 2023 तक और मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होने तक, दशकों की अशांति और हिंसा के बाद पूर्वोत्तर में शांति कायम थी। नगालैंड में युद्ध विराम था और असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में निर्वाचित सरकारें थीं। भारत सरकार ने सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की मदद से क्षेत्र में शांति बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली में सराहनीय काम किया था। पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच संवाद और एकीकरण में सुधार हुआ और क्षेत्र के लोग पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे हिस्सों में जाने लगे। पर्यटन भी फलने-फूलने लगा। हालांकि, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले में सिफारिश की गई कि राज्य सरकार को इस क्षेत्र के मुख्य समुदाय मैतेई को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए भारत सरकार से कहना चाहिए और इस प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देनी चाहिए (जिसका एक अर्थ बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ी इलाके में भूमि खरीद को खोलना भी निकलता है)। इस फैसले से होने वाले नुकसान की संभावना का अंदाजा लगाते हुए राज्य सरकार को न्यायिक साधनों से इस फैसले को चुनौती देने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए थे (ऐसा वह आसानी से कर सकती थी)। बाहरी लोगों की आमद खुलने की आशंका की वजह से पहाड़ी जनजातियों में अपनी ज़मीन और पहचान खोने का डर बना और उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया, जो कभी-कभी हिंसक भी थी, व्यक्त की। दुर्भाग्यवश, राज्य स्तर पर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया और स्थिति को अशांति और हिंसा में बदलने दिया गया। बड़ी संख्या में घाटी वासियों और पहाड़ी लोगों के बीच झड़पें हुईं और पुलिस के शस्त्रागार लूट लिए गए और बहुत से हथियार गायब हो गए (जिनमें से अधिकांश बरामद नहीं हो पाए)। सेना और पी.एम.एफ. का समुचित इस्तेमाल नहीं किया गया और पुलिस भी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब किसी तरह शांति बहाल हुई है, लेकिन सामाजिक ताना-बाना बिखर चुका है और चुप्पी ही एकमात्र संवाद है। पहाड़ी लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस नहीं जा पा रहे। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जिसे एक भड़काऊ बयान विस्फोट में बदल सकता है। समुदायों और सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरुआती दौर में आरंभ नहीं की गई और राज्य सरकार ने जोर-जबरदस्ती वाले तरीकों का इस्तेमाल करना चुना, जो विफल रहा। पूर्वोत्तर में स्थिति संभालने लिए उच्चतम स्तर की राजनीतिक सूझबूझ और राजनीति कौशल की आवश्यकता है। हमें पहले स्थिति को बिगड़ जाने देना और फिर आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अन्य राज्यों पर एक नज़र डालना चाहूंगा- मिजोरम में लंबे समय से शांति है, लेकिन अब कुछ आशंकित करने वाले संकेत दिखाई देने लगे हैं। जैसा कि मीडिया में बताया गया है कि भारत सरकार ने मिजोरम सरकार से कहा है कि वह म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं को शरण न दे और उनके लिए शिविर न बनाए। हालांकि, बताया जाता है कि मिजोरम ने फिर भी ऐसे शिविरों की स्थापना कर रखी है। इसी तरह, मिजोरम सरकार से मणिपुरी शरणार्थियों को भी न लेने और शिविर न लगाने की हिदायत दी गई। हालांकि, उसने वहां के लोगों को भी आने दिया और शिविर बना दिए- ये अच्छे संकेत नहीं हैं। मेघालय भी मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों के हितों के प्रति सहानुभूति रखता है और नगालैंड भी। पूर्वोत्तर को अब पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है...इन राज्यों में सदा ही जनजातीय और धार्मिक आधार पर मतभेद रहे हैं। ये जनजातियां सात राज्यों में फैली हुई हैं और मणिपुर की इन जनजातियों की चिंताएं मेघालय और नगालैंड में भी गूंजती हैं, इसलिए एक राज्य में जो घटित होता है उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से म्यांमार और मणिपुर एवं मिजोरम के बीच हिंसा नीत संबंध रहा है, शरणार्थी संकट के मद्देनजर इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में एक खिलाड़ी बनने के लिए बेताब है और उस पर रणनीति बनाते समय चीन को ध्यान में रखना होगा। मणिपुर में संघर्ष के मौजूदा दौर में मणिपुर एवं मिजोरम, दोनों जगह, भूमिगत तत्व सक्रिय हो गए हैं, सीमा पार करने और तस्करी में भी वृद्धि हुई है। भूकंप के बाद म्यांमार से लोगों और भूमिगत तत्वों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। सीमा प्रबंधन में सुधार करना होगा। कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर में बाहरी और आंतरिक, दोनों ही स्थितियों पर उच्चतम स्तर पर बारीकी से नज़र रखने और निर्णय लेने की आवश्यकता है। इन स्थितियों के नियमित रणनीतिक प्रबंधन को राज्य स्तर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उनका नजरिया एक सीमा तक होता है। समय बहुत अहम होता है और ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसमें उद्देश्य स्पष्ट हों और उनकी प्राप्ति हेतु रणनीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के तरीके और साधन निर्धारित हों।

आप का नजरिया

मेलों की पगड़ी

हिमाचल के मेलों में समाज और समाज के मेलों में नया रिवाज अब रौनक के संदर्भों को बदल रहा है। जाहिर है मेलों में व्यापार का आनंद बढ़ा है और आनंद के बाजार में मेले बड़े हो गए हैं। जो इन्हें गांव या शहर के मेले समझते हैं, वे गलत हैं या मेला संस्कृति को हम गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी होली के मेले में सुजानपुर-पालमपुर में बड़े कलाकार देखे गए, तो युवाओं का त्योहारी जोश हर शहर के चौक-चौराहे पर आकर मदहोश हो गया। मेले अब महज कुश्ती के नहीं रहे, टमक पर बजती चोट के नहीं रहे। वहां मिट्टी के बरतनों की खरीददारी से कहीं आगे 'ट्रेड फेयर' के व्यापारी आ गए। इसलिए मेले का ग्राउंड बिकता है और क्यों न बिके। अगर दाड़ी मेले का डोम बिक कर नगर निगम धर्मशाला के आय की शिनाख्त करे, तो ऐसे दर्जनों मेला ग्राउंड विकसित होने चाहिएं, लेकिन मेलों की संवेदना-संभावना को रौंद कर अगर सियासी और प्रशासनिक काफिले इन्हें अपनी महफिल का दास बना लें, तो सारा उद्देश्य हार जाता है। मेलों की सार्थकता अब इनके आयोजन की पारदर्शिता में है। नगरोटा के लिदबड़ मेले की सांस्कृतिक संध्या में हारती कुश्ती का जिक्र करते हुए पूर्व भाजपा विधायक अरुण कुमार कूका ने इसका पूरा इतिहास खंगाल दिया। मेलों में छिंज यानी कुश्ती के संदर्भ दरअसल नायकत्व की पहचान रही है। यह सामाजिक प्रश्रय की बेहतरीन मिसाल है जहां एक साल की तैयारी में विकसित होते युवाओं के शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन, ईमानदार तालियों का इंतजार करता है। ताज्जुब यह है कि सियासी वर्चस्व ने मेले से कुश्ती का ग्राउंड छीन लिया है या डोम के फैलाव ने कुश्तियों की अहमियत को कमजोर कर दिया। यह दीगर है कि मेलों में पगडियां बढ़ गईं और समाज को पीछे छोड़ सियासत का कुनबा, प्रशासन की रीत बन कर आगे दिखने लगा। आश्चर्य यह भी कि हिमाचल की इंद्रियां हर जगह राजनीति के लिए और सियासत सरीखी हो गई हैं। विडंबना यह है कि नलवाड़ मेलों में खूंटा गाडऩे की परंपरा के लिए अब बैल नहीं मिलते, लेकिन मेले में खूंटे से बंधी सियासत साफ दिखती है। नलवाड़ मेलों का उद्देश्य किसान या ग्रामीण आर्थिकी का शृंगार करता था, लेकिन अब वीआईपी समारोह की चाकरी में नेताओं का अभिनंदन करता है। बेशक हिमाचल में रामपुर के लवी मेले का अपना एक व्यापारिक ट्रैक रहा है, लेकिन अब दुकानदारी के फलक पर भगदड़ मची है। कहना न होगा कि मेलों में सियासी मेलों की खोज हो रही है, इसीलिए नेता बड़ा तो मेला राज्य स्तरीय हो जाएगा या किसी कस्बे में पड़ोस का कोई बड़ा पंजाबी गायक पहुंच जाएगा। नेताओं की पहचान में मेले होने लगें, तो समाज की भूमिका सिर्फ ताली बजाना है। आश्चर्य यह कि मेलों की सारी तालियां पगड़ीवालों, बाहरी कलाकारों और बाहरी पहलवानों के लिए ही रह गईं, जबकि अब देशी व्यापार का नए व्यापार से संघर्ष भी चुगली करने लगा है। मेले बढ़ें और बड़े भी हों, लेकिन इनके आयोजनों से अर्जित आर्थिकी का योगदान या तो सीधे राज्य को मिले या इनके विस्तार व प्रबंधन के लिए एक मेला विकास प्राधिकरण बने। मेलों का अध्ययन व सर्वेक्षण हो तो पता चलेगा कि हिमाचल में मेलों के तहत किस तरह ढाई, तीन सौ करोड़ का धंधा होने लगा है।

आज का राशिफल

मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ

आज मन प्रसन्न रहेगा उदासी दूर रहेगी.आप खुशहाल महसूस करेंगे कार्य में सफलता मिलने से मन हर्षित होगा. घर परिवार के बारे में भी विचार करेंगे और जरूरतो को पूरा करेंगे. परिवार में इज्जत रहेगी. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. सेहत में उतार–चढ़ाव रहेगा. गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहेगा. बच्चों का रवैया भी आप के अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य बहतर रहेगा , तंदरुस्ती बरकरार रहेगी ।

वृषभ – इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो

आज आय के स्त्रोत बढेंगे रुका हुआ धन वापस आएगा और अचानक कहीं से धन लाभ होगा. जिससे आर्थिक पक्ष में मजबूती आयेगी. आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे. आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी. आपका पढ़ाई में मन लगेगा. साथ ही नये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी दिन शुभ है. सफलता जरूर मिलेगी. कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ धन लाभ होगा आप कलाप्रेमी है तो आप के गुण और कला की तारीफ होगी ।

मिथुन – क,कि,कृ,घ,ड़,छ,के,को,ह

आज सुबह उठते ही कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी एवं आप अपने आपमे बहुत गर्व महसूस करेंगे आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है. आपको ख़ुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की एहमियत का एहसास होगा. आपके बच्चे भी घर में ख़ुशी और सुकून के माहौल को महसूस कर सकेंगे. बच्चों के साथ आपका दिन मजेदार गुजरेगा.कोई नया टेंशन मत आने देना हैं काम को समझदारी से सुलझाले।

कर्क – ही,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो

आज का दिन जरुर थोड़ा व्यस्तता मे बीतेगा सामाजिक तौर पर नयी चुनौती सामने होगी इसलिए आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करें.आप एक टीम के रुप मे काम करें चुनौतीया दूर रहेगी एवं विरोधी पस्त होंगे आपको लोगों से सराहना और सहयोग मिलने के संकेत है आपको अपने लोगों से या अपनी टीम से सम्मान मिल सकता है. दाम्पत्य जीवन मजेदार रहेगा एक नयी उर्जा रहेगी

सिंह – म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

आज का दिनमान आपके लिए उतार–चढ़ाव से भरा रहेगा. खर्चों में एकदम से तेजी आएगी जो शाम तक आपको परेशान कर सकती है लेकिन धैर्य रखने से बात बनेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें. बेवजह की बातों को दिमाग से ना लगाएं. किसी से झगड़ा ना करें. दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी राहत की सांस मिलेगी. एक–दूसरे से बातचीत होगी और जो लंबे समय से रुकी हुई बातें थी, वो अब होने लगेंगी. आपका दिल खुश हो जाएगा. काम के सिलसिले में दिनमान अच्छा है.

कन्या – टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो

आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. इस राशि के छोटे बच्चे आज पढ़ाई में अधिक रूचि लेंगे. इससे माता–पिता बहुत खुश रहेंगे. जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है. विवाह के लिए प्रस्ताव आयेगा. आज पुरे दिन परिवार का माहौल आनन्दमय बना रहेगा. स्वास्थ्य आज पहले से बढ़िया रहेगा. आपकी कोई खास इच्छा आज जरूर पूरी होगी. लवमेट के लिए आज का दिन फेवरेबल है.

तुला – र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. कार्य में सफलता मिलने से मन हर्षित होगा. घर परिवार के बारे में भी विचार करेंगे और जरूरतों को पूरा करेंगे. परिवार में इज्जत रहेगी. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. सेहत में उतार–चढ़ाव रहेगा. गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहेगा।

वृश्चिक – तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज सामाजिक और राजनीति गतिविधियों मे समय गुजरेगा आप की जान पहचान भी बढेगी आपको जो आपको सम्मान दिला सकता है. कुछ ऐसे काम जो आपकी इमेज को एक नया रंग दे सकते हैं, उन्हें करने की कोशिश करें. कुछ नया शुरू करने या नई जिम्मेदारी मिलने का दिन है. आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान मिलेगी. आपकी सलाह लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है.वर्तमान मे बनाए हुए सम्बन्ध भविष्य मे लाभ देंगे।

धनु – ये,यो,भ,भी,भू,धा,फा,ढा,भे

आज दिन कुछ कमजोर गुजरेगा . परिवार में किसी बात को लेकर खींचातानी हो सकती है जिसकी वजह से आप को थोड़ी परेशानी भी होगी लेकिन कोशिश करने से समाधान निकल जाएगा और समस्याएं दूर होंगी. गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. रिश्ते में रोमांस भी रहेगा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना भी बढ़ेगी. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा. आप अपनी बात कहने में सक्षम होंगे. यात्रा का योग बनेगा।

मकर – भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

आज धार्मिक ग्रंथों का पठन और श्रवण करेंगे मंदिर मे देव प्रतिमा को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे संतान सुख की प्राप्ति होगी. परिवार के सुख–सौभाग्य में वृद्धि होगी. ऑफिस में आज किसी से बहस होने की संभावना है. आपको इससे बचकर रहने की जरूरत है. कोई जरूरी केस का फैसला आपके पक्ष में आयेगा. ऐग्रिकल्चर मे निवेश आपको धन लाभ देगा ।

कुम्भ – गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

महनत अच्छा परिणाम देगी शतप्रतिशत फल मिलेगा आय में वृद्धि होगी. जिस काम की आपको उम्मीद थी, आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा. आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए. पारिवारिक कलह होगी इसलिए थोड़ा–सा वाणी पर संयम रखें. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपको नवग्रह शान्ति करानी चाहिए।

मीन – दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची

आज ऑफिस मे ओवरटाइम करना पडेगा.जिससे पारिवारिक तनाव बनेगा आप काम के दबाव से परेशान रह सकते हैं. करियर के मामलों में इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें. नकारात्मक लोगों और चीजों से दूर रहें. आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा सूर्य को रक्त पुष्प और गंध युक्त जल अर्पण करें।

आज का पंचांग

दिनांक : 04 अप्रैल 2025 , शुक्रवार
विक्रम संवत : 2082
मास : चैत्र , शुक्ल पक्ष
तिथि : सप्तमी रात्रि 08:15 तक
नक्षत्र : आर्द्रा रात्रि 05:21 तक
योग : शोभन रात्रि 09:44 तक
करण : गर प्रातः 08:54 तक
चन्द्रराशि : मिथुन
सूर्योदय : 06:08 , सूर्यास्त 06:29 (हैदराबाद)
सूर्योदय : 06:14, सूर्यास्त 06:31 (बैंगलोर)
सूर्योदय : 06:06 , सूर्यास्त 06:24 (तिरुपति)
सूर्योदय : 06:00 , सूर्यास्त 06:20 (विजयवाडा)

शुभ चौघड़िया
चंचल : 06:00 से 07:30
लाभ : 07:30 से 09:00
अमृत : 09:00 से 10:30
शुभ : 12:00 से 01:30
राहुकाल : प्रातः 10:30 से 12:00
दिशाशूल : पश्चिम दिशा
उपाय : दूध पीकर यात्रा करें
दिन विशेष : कालरात्रि पूजनम् , भद्रा रात्रि 08:13 से , मलमास चालू है ।

* पाण्डित्य विषय में सम्पर्क करें *

पं.चिदम्बर मिश्र (टिल्लू महाराज)
हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा एवं मूल पारायण, वास्तुशान्ति, गृहप्रवेश,शतचंडी, विवाह, कुंडली मिलान, नवग्रह शान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं
फक्कड़ का मन्दिर, रिकाबगंज, हैदराबाद, (तेलंगाना)
9246159232, 9866165126
chidamber011@gmail.com

वक्फ प्रशासन में तय होगी पारदर्शी जवाबदेह व निष्पक्ष व्यवस्था :भजनलाल

जयपुर,04 अप्रैल (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक–2025' के संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प का प्रमाण होने के साथ ही देश में समानता, पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने इस अभूतपूर्व विधेयक के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं और अपारदर्शिता को समाप्त करने के लिए यह संशोधन आवश्यक था। यह वक्फ प्रशासन में पारदर्शी, जवाबदेह एवं निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ–साथ गरीब व जरूरतमंदों को सशक्त भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के अनुचित विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।

शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी समाजों, खासकर गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। तीन तलाक समाप्त करके मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया।

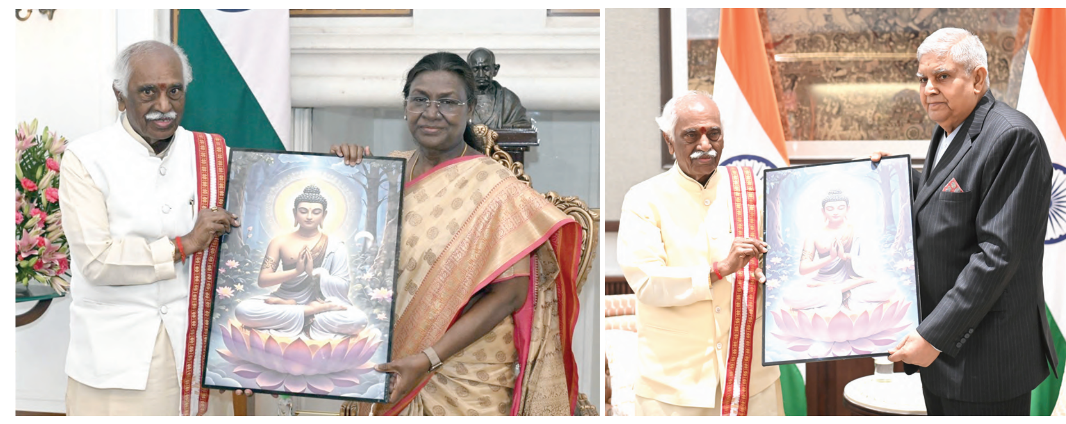

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार दि. 4 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति निवास, नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की।

जब्त बजरी और अन्य खनिज की 15 दिन में होगी नीलामी की कार्रवाई : रविकांत

जयपुर,04 अप्रैल (एजेंसियां)। प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त बजरी व अन्य खनिज की 15 दिन में नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, वहीं अवैध खनिज परिवहन गतिविधियों में जब्त वाहनों को 21 अप्रेल तक न्यायालयों से राज्यसात करवाने की कार्रवाई आरंभ कर उन्हें भी नीलामी किया जाएगा।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त शुक्रवार को खनिज भवन में माइंस विभाग के मुख्यालय सहित फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग द्वारा औचक अभियान की आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी है और विभागीय अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश के साथ ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम धमाके मामला

चार आरोपी दोषी करार, 8 अप्रैल को सजा का ऐलान

जयपुर,04 अप्रैल (एजेंसियां)। वर्ष 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान चांदपोल इलाके में मिले जिंदा बम के मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत 8 अप्रैल को इनकी सजा पर फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार दिया है। इससे पहले इन्हीं चारों को सीरियल ब्लास्ट के मुख्य मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आठ मामलों में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के उस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो फिलहाल लंबित है।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 180 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के पास खड़ी साइकिल पर नौंवा बम मिला, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया था। एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। जांच के दौरान कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पत्रकार और स्थानीय लोग शामिल थे। मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि मंदिर के पास साइकिल किसने रखी थी। साथ ही तर्क दिया कि यह मामला पहले के आठ मामलों से तथ्यात्मक रूप से मिलता–जुलता है, जिनमें हाईकोर्ट पहले ही आरोपियों को बरी कर चुका है। फिलहाल, चार में से दो आरोपी–सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ–जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद जमानत पर बाहर हैं। अब सभी की सजा पर 8 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा।

दिया कुमारी ने किया एसआईपीएफ विभाग द्वारा विकसित चैटबॉट का लोकार्पण

जयपुर,04 अप्रैल (एजेंसियां)। प्रदेश के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी अब एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी । राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विकसित चैटबॉट के माध्यम से उन्हें यह जानकारी प्राप्त होगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री कार्यालय से इस चैटबॉट का लोकार्पण किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा किया गया यह नवाचार राज्य के लाखों कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए ऋण आदि की सुविधा में साहूलियत देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा सूचना तकनीक एवं अन्य नवाचारों के द्वारा जन–सुविधाओं को सुलभ करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे है। उसी कडी में यह महत्वपूर्ण पहल है। शासन सचिव वित्त (व्यय) नवीन जैन ने बताया कि विकसित किये गए एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से एसआईपीएफ मोबाईल एप, वेबसाईट एवं पोर्टल पर हिंदी एवं अग्रेजी भाषा में राज्य कार्मिक उनके राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के तहत ऋण एवं आहरण की पात्रता, खाते जमा राशि, मनोनीत व्यक्ति की जानकारी आसानी से तथा किसी भी समय प्राप्त कर सकते है।

मनोज कुमार पर फिल्माए हुए नगमे हमेशा याद किए जाएंगे: विज

चंडीगढ़,04 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि फिल्म अभिनेता और कलाकार मनोज कुमार आज 87 साल की आयु पूरी करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए लेकिन उनका किरदार हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके गीतों और उनकी अदाकारी में हमेशा भारत की संस्कृति की सुगंध आती थी और उनके गाए हुए और फिल्माए हुए नगमे हमेशा याद किए जाएंगे। विज आज मशहूर कलाकार और फिल्म एक्टर मनोज कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह बात बोल रहे थे।

उल्लेखनीय है कि फिल्म कलाकार मनोज कुमार का सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरब–पश्चिम, क्रांति, रोटी–कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं थी।

गौरतलब है कि उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। मनोज कुमार काफी समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में होगा। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए चार फिल्म फेयर जीते। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया।

किसानों और मजदूरों की मदद के लिए अब दस रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, अगस्त तक खुलेंगी 200 नई अटल कैंटीन

चंडीगढ़। ,04 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और मेहनती श्रमिकों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इन लोगों को जल्द ही पूरे राज्य में सिर्फ 10 रुपये में ताजा और स्वस्थ भोजन उपलब्ध होगा। इस परियोजना का लक्ष्य न केवल भोजन की मदद करना है, बल्कि पेट को कुछ सम्मान भी दिलाना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर इन 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे। महिला स्वयं सहायता संगठनों के माध्यम से संचालित ये कैंटीन महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के साथ–साथ रोजगार को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगी। सरकार का लक्ष्य धीरे–धीरे हरियाणा में 600 अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनाना है। वर्तमान में, राज्य में 175 सब्सिडी वाली कैंटीन चल रही हैं – श्रम विभाग 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 53 और चीनी मिलें 7 कैंटीन की आपूर्ति करती हैं। अगस्त में 200 और कैंटीन स्थापित होने के बाद कुल 375 कैंटीन होंगी। हर थाली में स्वाद, स्वच्छता और गरिमा होगी। हालांकि इन कैंटीनों में केवल 10 रुपये में मिलने वाला भोजन किफायती होगा, लेकिन सामग्री की गुणवत्ता, स्वाद या गरिमा पर कोई छूट नहीं होगी। मानक बनाए रखने और हर व्यक्ति के लिए समान सेवा की गारंटी देने के लिए, मुख्यमंत्री ने सभी कैंटीनों में एक समान मेनू लागू करने का भी निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कैंटीनों के पूर्ण डिजिटलीकरण का आदेश दिया है। यह क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों और पड़ोसी कैंटीनों, संचालन के घंटों और मेनू की जानकारी तक आसान एकल–क्लिक पहुंच के लिए एक विशिष्ट वेबसाइट के साथ आएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में हरियाणा का रहेगा विशेष योगदान : सैनी

चंडीगढ़,04 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। इसी तरह से हम सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सरकार की नीतियों व कल्याणकारी योजनाओं को घर–घर तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री अपने निवास चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में अंबाला से आए सैकड़ों लोगों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत सुरक्षित, लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने वाला, तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र बन रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों को चिंता करने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का विकास तेज गति से हो रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिली है। ट्रिपल इंजन की सरकार तीन गुना तेजी से काम करके देश व प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो किसानों की सभी फसलों को शत प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने में 1.50 लाख लोग संत कबीर कुटीर में उनसे मिलने पहुंचे, जिनमें से 75 हजार लोगों के काम किए गए। अन्य लोगों के काम भी तीव्र गति से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा साहब डॉ भीम राव आंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उदघाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की नई यूनिट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस यूनिट पर 7272 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो कि वर्ष 2028 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यमुनानगर में पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी, पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व मंत्री संतोष सारवान, बंतो कटारिया सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कड़ी मेहनत व लग्न से इंसान बनाता है अपनी पहचान

चंडीगढ़,04 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान कड़ी मेहनत से बनाता है। ऐसे होनहार व्यक्तियों पर न केवल उनके अभिभावकों को बल्कि स्थानीय क्षेत्र के लोगों को भी गर्व होता है। शशांक गुप्ता उनमें से एक हैं जिन्होंने नारायणगढ़ के नेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और उनका चयन आज शैक्षणिक सत्र 2025 –26 के लिए शेर्लोट एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर फ़ेलोशिप, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड में हुआ। मुख्यमंत्री ने शशांक गुप्ता को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने शशांक गुप्ता के पिता शैलेन्द्र गुप्ता को भी फोन कर उन्हें बेटे की सफलता के लिए बधाई दी।

डुमरियागंज में गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का उद्घाटन

भारत ने कभी तलवार के बल पर शासन नहीं किया : योगी

सिद्धार्थनगर, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह पावन धरा दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश देती है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी तलवार के बल पर शासन नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वासंती नवरात्र की सप्तमी तिथि है, जो महाकाली को समर्पित है। सनातन परंपरा तमसो मा ज्योतिर्गमय के सूत्र से शुरू होती है। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली के उद्घाटन पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारत की परंपरा ने हमेशा ज्ञान की आराधना की है। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चारों ओर से आने वाली ज्ञान की धारा को ग्रहण करना प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग और सज्जन शक्ति को इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों बाद उन्हें यहां आने का अवसर मिला है। उन्होंने 2008 के समय को याद करते हुए कहा कि तब यहां अराजकता और असुरक्षा का माहौल था। बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे और तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में विकास और शिक्षा की कोई जगह नहीं थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत में व्यापक बदलाव आया है।

पहले भारत के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यह एक भारत, श्रेष्ठ भारत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया भारत अपनी ताकत और सौहार्द का अहसास करा रहा है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह बल, बुद्धि और वैभव में कितना भी मजबूत हो, मगर जबरन किसी पर न तो आधिपत्य स्थापित करेगा ना ही किसी का आधिपत्य स्वीकार करेगा।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश हर क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विरासत और विकास का बेहतर समन्वय ही कल्याणकारी जीवन की कुंजी है। अयोध्या में 500 साल की दासता की बेड़ियां टूटने और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश अपनी विरासत पर गर्व करता है, तो महाकुम्भ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु सनातन धर्म के सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने भारतीय परंपरा की शांतिपूर्ण प्रकृति पर विशेष जोर डालते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी तलवार के बल पर शासन नहीं किया।

भगवान राम ने माता सीता को खोजते हुए लंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया। उन्होंने कहा था कि लंका कितनी भी स्वर्णमयी हो, लेकिन जन्मभूमि और जननी से बढ़कर कुछ नहीं। इसी तरह किष्किंधा में श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और दंडकारण्य में ऋषियों को सुख प्रदान किया। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन यहीं बीता था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म ने करुणा और मैत्री के बल पर दुनिया को आकर्षित किया, न कि तलवार के दम पर।

मुख्यमंत्री ने 2014 से पहले के समय को याद करते हुए कहा कि तब कुछ लोग राम और कृष्ण को मिथक बताते थे और भारतीय परंपरा को अपमानित करना अपना अधिकार समझते थे। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी विरासत और विकास के समन्वय से नई ऊंचाइयों को छुआ है।काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए वेदों और उपनिषदों को देखना होगा।

आधुनिक विज्ञान जहां नहीं पहुंच सका है, उसका भी मार्गदर्शन उपनिषद कर सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा शुरू हुई है, जिससे मेडिकल, इंजीनियरिंग और मानविकी के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। उन्होंने 18 अटल आवासीय विद्यालयों, 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों के उन्नयन का विशेष रूप से जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोर-क्षनाथ ज्ञानस्थली का पहला सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें अब तक 150 छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर शुरू हुआ यह केंद्र एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में क्षेत्र को आलोकित करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता, संस्कार और मातृभूमि की परंपराओं से शिक्षा को जुड़ना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कविता शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक जय प्रताप सिंह, श्यामधनी राही, विनय वर्मा, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, निदेशक प्रवीण पांडेय, प्रदीप सिंह, आकाश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

अच्छी आवासीय सुविधा देकर लोगों का जीवन स्तर बढ़ा रही सरकार

सीएम योगी ने अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया

लखनऊ, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वासियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे अनंत नगर आवासीय सुविधा के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए कहा कि अच्छी आव-ासीय सुविधा देकर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अच्छी आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में 7 हजार करोड़ रुपए की लागत से अनंत नगर आवासीय स्कीम लेकर आयी है।

इस योजना के साथ ही एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत एजुकेशन हब स्थापित करने के लिए 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आरक्षित की गई है। सीएम योगी ने कहा कि योजना के अंतर्गत हाईराइज अपार्टमेंट से साथ प्लॉट भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत की गई है जो कि अत्यंत सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त हो, उनका जीवन और भी आसान हो इस दिशा में अनंत नगर आवासीय योजना की स्कीम फलदायी है तथा यह वन ट्रिलियन डॉलर के प्रदेश के सपने को सच करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्ष में अच्छी आवासीय सुविधा देने तथा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने क्षेत्र में बड़े कदम बढ़ाए हैं। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग तथा निर्धारित समयसीमा से पूर्व सस्ती आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध कराना आज की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह कार्य आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो एक हाई राइज बिल्डिंग के बनने में 5 से 10 वर्षों का समय लगता था। वहीं, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है जिससे लोगों को अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

सीएम योगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि दो वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत एक अच्छा प्रयास किया गया। कोविड कालखंड के दौरान भी अत्याधुनिक तकनीक आधारित इस योजना का कार्य बढ़ता रहा। सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंत नगर आवासीय योजना भी इसी प्रकार की तकनीक पर निर्मित किया जाए। लोगों को अच्छी लेकिन सस्ती आवासीय सुविधा प्राप्त हो तथा एक हरा-भरा आध्यात्मिक वाता-वरण उन्हें प्राप्त हो। एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। यह न केवल शासन की प्राथमिकता है बल्कि इसी आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अगर यहां पर हम समाज के हाई इनकम ग्रुप को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं, अत्यंत कम आय वर्ग के और प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकने वाले लोगों को भी लाभान्वित करने का विशेष प्रावधान किए गए हैं।

सीएम योगी ने कहा कि प्री-प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा वहां प्राप्त हो यह हमारी प्राथमिकता है। एक ही इंटीग्रेटेड परिसर में सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो इसका प्रावधान अनंत नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जितनी देर में यह स्कीम आई है उतनी ही जल्दी अनंत नगर योजना वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है, यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए उपलब्ध होगी।

सीएम योगी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कहा कि अभी से हमें तैयारी करनी होगी। यह योजना आम लोगों तक शीघ्र उपलब्ध हो।

हम ईज ऑफ लिविंग को तो सुनिश्चित करेंगे ही बल्कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े यह लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा।

अब अरब जगत भी देखेगा यूपी का ठाठ

दुबई में होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट में यूपी का होगा पर्यटन-शोकेस

लखनऊ, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों से समृद्ध उत्तर प्रदेश के ठाठ का दर्शन अब जल्द ही अरब जगत भी बड़े स्तर पर होने जा रहा है। दुबई में 28 अप्रैल से एक मई के मध्य वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध अरेबियन ट्रैवल मार्ट (एटीएम) का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग वहां यूपी की टूरिज्म ऑफरिंग्स को शोकेस प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है।

योजना के तहत, दुबई स्थित अरेबियन ट्रैवल मार्ट के वेन्यू पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा रोड शो तथा 50 स्क्वेयर मीटर क्षेत्र में भव्य पंडाल का संचालन किया जाएगा। यहां सूफी सर्किट, रिवर टूरिज्म, हेल्थ व वेलनेस टूरिज्म तथा ईको व रूरल टूरिज्म के प्रमुख पर्यटक गंतव्यों की जानकारी दी जाएगी।

इसके साथ ही, कन्नौज के इत्र की महक के साथ आगरा समेत प्रदेश के भव्य महलों व समृद्ध कला-संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। वहीं, वृंदावन के मयूर नृत्य, झांसी के बुंदेली नृत्य तथा लखनऊ के कथक नृत्य समेत कई प्रकार की प्रस्तुतियों का प्रदर्शन होगा।

पर्यटन विभाग द्वारा दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट एग्जीबिशन में यूपी की थीम पर बेस्ड भव्य पंडाल का संचालन करेगा। इस दौरान जिस पंडाल की स्थापना व संचालन किया जाएगा वह विभिन्न प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। यहां बी2बी व बी2जी बैठकों का संचालन हो सकेगा। यहां पर्यटन विभाग की वेबसाइट व मोबाइल ऐप को भी प्रमोट किया जाएगा तथा इनके जरिए मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा।

अरेबियन ट्रैवल मार्ट में उत्तर प्रदेश के शानदार पर्यटन आकर्षणों का अनुभव किया जा सकेगा। इसमें इत्र पर्यटन-भारत की इत्र राजधानी, सूफी सर्किट, उत्तर प्रदेश की शाही विरासत, स्मारक, किले और आगरा की शान, पर्यावरण व ग्रामीण पर्यटन, पारंपरिक स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र तथा नदी पर्यटन जैसी थीम व फोकस एरिया को प्रमोट किया जाएगा। आकर्षक एंट्री गेट्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तथा सेल्फी प्वॉइंट्स समेत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहां आगंतुकों के लिए उपलब्ध रहेंगी।

अरेबियन ट्रैवल मार्ट के एग्जिबिशन में संचालित होने वाले उत्तर प्रदेश के पंडाल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी लोगों को देखने को मिलेगी।

महाकुंभ के बाद विदेशों त्रिवेणी के पावन जल की मांग

जर्मनी भेजा गया एक हजार बोतल गंगा जल

प्रयागराज, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। त्रिवेणी के पावन जल की डुबकी से कोई छूट न जाए इसके लिए योगी सरकार ने अग्निशमन विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों में त्रिवेणी पवित्र जल पहुंचाया।

अब इसी त्रिवेणी के जल की मांग विदेशों से भी आनी शुरू हो गई है। इसकी पहली खेप प्रयागराज से भेज भी दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के समापन के बाद प्रदेश के सभी जिलों में संगम के जल को महाप्रसाद रूप में पहुंचाने का निर्णय लिया था जो किसी कारण वश यहां महाकुंभ में आने से वंचित रह गए। लेकिन अब देश

के बाहर भी यही पवित्र गंगा जल भेजने की मांग आई है जिसकी पहली खेप भी प्रयागराज से भेज दी गई है।

प्रयागराज के एनआरएलएम उपायुक्त राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि जनपद की जसरा की नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की तरफ से त्रिवेणी के गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में कांच के 1000 बोतल में त्रिवेणी का पवित्र गंगा जल यहां से जर्मनी भेजा गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के माध्यम से यह जल विदेश भेजा गया है। जर्मनी से जो श्रद्धालु किसी कारण वश महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए यह त्रिवेणी का जल भेजा गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के समय ही जनपद में बड़े स्तर त्रिवेणी के गंगा जल की पैकेजिंग की शुरुआत महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से हो गई थी। जसरा की नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की प्रभारी नमिता सिंह बताती हैं कि

महाकुंभ के आयोजन के बाद अब तक 50 हजार से अधिक बोतल में पैक किया हुआ गंगा जल स्वयं सहायता समूह की उनकी महिलाओं द्वारा भेजा चुका है। हाल ही में उन्होंने नागपुर के शिव शंभू ग्रुप सोसायटी को 50 हजार बोतल त्रिवेणी का जल भेजा है। 500 एम एल की बोतल में यह गंगा जल भेजा गया है। जबकि जर्मनी जो गंगा जल भेजा गया था वह 250 एम एल की बोतल में था।

यूपी के सभी 75 जिलों में अग्निशमन विभाग की तरफ से त्रिवेणी का पावन जल पहले ही पहुंचाया जा चुका है। यह सिलसिला अभी संपन्न चल ही रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में असम से निजी टैंकर लेकर परम शिवम शिव मंदिर योगाश्रम, गुवाहाटी के संत राजा रामदास त्रिवेणी संगम पहुंचे थे।

सीएफओ प्रमोद शर्मा का कहना है कि राजा रामदास जी ने टैंकर में गंगा जल भरवाने में विभाग का सहयोग मांगा और उनके विभाग ने उनके टैंकरों में जल भरकर उन्हें यहां से असम के लिए रवाना कर दिया गया था।

गोरखपुर को योगी के हाथों मिलेगा 2842 करोड़ का नवरात्र-उपहार

जीडीए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम

गोरखपुर, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार और रविवार को गोरखपुर को 2842 करोड़ रुपए के विकास कार्यों तथा औद्योगिक प्रगति का नवरात्र उपहार देंगे। वह शनिवार को जीडीए (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की 1642 करोड़ रुपए की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अगले दिन रविवार को मुख्यमंत्री गीडा में 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाली केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण कर गोरखपुर को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

सीएम योगी चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर शनिवार को पैडलेगंज-आरकेबीके रिंग रोड का लोकार्पण, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास, कार्निवाल पार्क का शुभारंभ और आवासीय योजना गोरक्ष एंक्लेव का उद्घाटन करने के साथ ही जीडीए की कुल 107 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन सभी विकास परियोजनाओं की सम्मिलित लागत 1642 करोड़ रुपए है।

पैडलेगंज-आरकेबीके रिंग रोड महानगर के एक हिस्से में जाम की समस्या का समाधान करने में कारगर प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री रामगढ़ताल इलाके में जीडीए की शानदार आवासीय योजना गोरक्ष एंक्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। 55 करोड़ रुपए के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को 4313 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दो ब्लॉक में 86 बहुमंजिला फ्लैट बनाए गए हैं। उद्घाटन के अवसर सीएम योगी किसी एक या कुछ फ्लैट्स का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

यह सभी जानते हैं कि योगी सरकार रामगढ़ताल क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से चमका रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र की साझेद-ारी के तहत मेसर्स जेएसआर द्वारा आल इन वन कार्निवाल पार्क विकसित किया गया है। यहां एडवेंचर पार्क, आर्केड जोन, बीआर पार्क, इंफ्लेटेबल पार्क और एम्यूजमेंट पार्क को तैयार किया गया है। इन व्यवस्थाओं में कई प्रकार के मनोरंजक गेम्स का आनंद उठाया जा सकेगा। समग्र रूप से इस कार्निवाल पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे। जीडीए रामगढ़ताल के सामने 25 एकड़ में विस्तृत और 1410 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर, क्लब एंड फाइव स्टार होटल का निर्माण कराने जा रहा है। इसका शिलान्यास शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथों होगा। इसकी क्षमता 5000 व्यक्तियों की होगी। इसका निर्माण तीन साल में पूर्ण करने का लक्ष्य है। कन्वेंशन सेंटर में एलीट क्लब, आध्यात्मिक पुस्तकालय और इवेंट एंड एग्जीबिशन लॉन का भी प्रावधान किया गया है।

सीएम योगी रविवार को गीडा के सेक्टर 26 में केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के लिए केयान की तरफ से 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत केयान ने अनाज (चावल, मक्का) आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया है। प्रथम चरण में इसकी उत्पादन क्षमता तीन लाख लीटर की है। तीन चरणों में इसके विस्तार के बाद कुल उत्पादन क्षमता दस लाख लीटर प्रतिदिन की हो जाएगी। इस प्लांट का शिलान्यास 12 अगस्त 2023 को सीएम योगी ने किया था और अब रविवार को उनके हाथों उद्घाटन होने जा रहा है।

हैदराबाद पर मिली जीत के बाद केकेआर के उपकप्तान वेंकटेश अय्यर ने कहा–सकारात्मक लेकिन सही इरादे दिखाना जरूरी

कोलकाता,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के उप–कप्तान वेंकटेश अय्यर ने टाटा आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) पर मिली 80 रनों की धमाकेदार जीत के बाद टीम के प्रदर्शन पर विस्तार से बात की। उन्होंने मैच की स्थितियों को पढ़ने और उसी के अनुसार ढलने के महत्व को रेखांकित किया। अय्यर ने 29 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 60 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली, जिससे केकेआर ने ईडन गार्डन्स में पिछले सीज़न के फाइनल की पुनरावृत्ति में 200 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। अय्यर ने मैच के बाद कहा, आक्रामकता का एक मूल लेकिन महत्वपूर्ण अर्थ है सकारात्मक लेकिन सही इरादा दिखाना, अगर हमारी टीम 50 पर 6 है और मैं तब भी हर गेंद को हिट करने जाऊं, तो वह भले ही सकारात्मक लगे, लेकिन सही नहीं है। स्मार्ट क्रिकेटर कहलाने के लिए ज़रूरी है कि हम स्थिति को समझें और फिर प्रतिक्रिया दें। अय्यर ने स्पष्ट किया कि केकेआर के लिए आक्रामकता का मतलब हर गेंद पर बाउंड्री मारना नहीं है। आक्रामकता का अर्थ है परिस्थितियों को समझना और उन्हें अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए, यह जानना। उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज़ अंकृष रघुवंशी की भी सराहना की, जिनकी सलाह ने उन्हें पिच को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। रहाणे और अय्यर ने 51 गेंदों में 81 रनों की साझेदारी की, जिसमें रहाणे ने 38 रन बनाए और रघुवंशी ने अर्धशतक जमाया। अय्यर ने कहा, टाइमआउट के दौरान मुख्य बातचीत अजिंक्य और अंकृष द्वारा की गई। उन्होंने यह समझाया कि यह पिच इतनी आसान नहीं है कि आते ही हिटिंग शुरू कर दें। आपको थोड़ा समय लेना होगा। केकेआर की बल्लेबाज़ी रणनीति में अय्यर और रिंकू सिंह ने आधार तैयार किया, जिसके बाद अंतिम ओवरों में आक्रमण की योजना थी।

अय्यर ने कहा, मेरे पास यह लग्ज़री है कि हमारे पास रिंकू, रमनदीप और रसेल जैसे बल्लेबाज़ हैं। अगर मैं कुछ गेंदें लेता हूं, तो भी हम उसे कवर कर सकते हैं। हमारे पास एक इंजन रूम है जो किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता है। एसआरएच की अत्यधिक आक्रामक बल्लेबाज़ी रणनीति पर बात करते हुए, जिसे केकेआर के गेंदबाज़ों – विशेषकर वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती (तीन–तीन विकेट) – ने धराशायी कर दिया।

न्यूज ब्रीफ

हॉपमैन कप मिश्रित टीम टेनिस टूर्नामेंट 16 से 20 जुलाई तक, इटली करेगा मेजबानी

बारी (इटली)। प्रतिष्ठित हॉपमैन कप का आयोजन इस वर्ष 16 से 20 जुलाई तक इटली के बारी शहर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट विंबलडन के एक हफ्ते बाद आयोजित होगा। इस मिश्रित टीम टूर्नामेंट में इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और गत विजेता क्रोएशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। हॉपमैन कप में हर टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी शामिल होता है। प्रत्येक टाई में एक पुरुष एकल, एक महिला एकल और एक मिश्रित युगल मैच खेला जाता है। यह टूर्नामेंट एटीपी या डब्ल्यूटीए रैंकिंग अंक प्रदान नहीं करता। मेजबान इटली की ओर से जैस्मिन पाओलिनी और फ्लावियो कोबोली खेलेंगे। अन्य देशों की टीमों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पाओलिनी पिछले साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन की महिला एकल उपविजेता रही थीं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सारा एरानी के साथ महिला युगल का स्वर्ण पदक भी जीता था। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हैरी हॉपमैन के नाम पर शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 1989 से 2020 तक लगातार खेला गया। 2023 में इसे फ्रांस में दोबारा शुरू किया गया था, जहां क्रोएशिया के डोना वेकिक और बोर्ना चोरिच की जोड़ी ने खिताब जीता था। करीब तीन दशक तक यह टूर्नामेंट पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में नए साल की शुरुआत में आयोजित होता रहा। पिछले साल यह टूर्नामेंट फ्रांस के नीस में होना था, लेकिन ओलंपिक के नजदीक होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। बारी में इसका आयोजन इटली के व्यस्त टेनिस कैलेंडर में एक और आयोजन को जोड़ता है, जहां मई में इटालियन ओपन, और नवंबर में एटीपी फाइनल्स व डेविस कप फाइनल्स भी आयोजित होते हैं।

पंचकूला में होगा पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता

नई दिल्ली। हरियाणा के पंचकूला में 24 मई को पहली बार नीरज चोपड़ा क्लासिक (एनसी क्लासिक) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने गुरुवार को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता की पुष्टि की है। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड कैटेगरी इवेंट होगी, जो इसे विश्व चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालीफिकेशन स्पर्धा बना देगी। इस इवेंट में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिता का आयोजन पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में किया जाएगा। वर्तमान विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने 2025 सीजन की शुरुआत 16 मई को कतर में होने वाले दोहा डायमंड लीग से करेंगे। यह इवेंट नीरज चोपड़ा क्लासिक से ठीक एक सप्ताह पहले होगा। नीरज ने भारत में अपना पिछला इवेंट 2024 फेडरेशन कप में खेला था, जहां उन्होंने 82.27 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था।

दोनो हाथों से गेंदबाजी करने वाले आईपीएल इहिहास के एकमात्र गेंदबाज हैं कामिंदू

मुम्बई। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे ऑफ स्पिनर कामिंदू मेंडिस दोनो ही हाथों से गेंदबाजी करने के कारण सबके आकर्षण का केन्द बने हुए हैं। उन्होंने ईडन गार्डन में हुए पहले ही मैच में दोनों हाथों से गेंदबाजी करते हुए विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। वह आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले पुरुष गेंदबाज हैं। मेंडिस को टीम ने केवल 75 लाख रुपए में खरीदा पर उनका प्रदर्शन इससे कहीं अच्छा रहा है। वह श्रीलंका की टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलते हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में वह कोलंबो क्रिकेट क्लब में शामिल हैं। मेंडिस ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत अक्टूबर 2018 में टी20 प्रारूप में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। इसके बाद से ही वह टेस्ट और एकदिवसीय में भी श्रीलंका की ओर से खेलते रहे हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते है। उनके नाम कई रिकार्ड भी हैं। मेंडिस टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के बाद से ही 8 मैचों में 50 से अधिक रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने डेब्यू के बाद लगातार 8 टेस्ट मैचों में 50 से अधिक रन बनाए हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गॉल टेस्ट में बनाया था। मेंडिस ने मात्र 13 टेस्ट पारियों में 5 शतक लगाये हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ दो–दो। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया है। इससे वह युवा टेस्ट बल्लेबाजों में शीर्ष पर पहुंच गये हैं। इस क्रिकेटर ने 12 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 74.72 की औसत से 1,184 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं।

लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया

सूर्यकुमार की कोशिश गई बेकार

नई दिल्ली,04 अप्रैल (एजेंसियां)। लखनऊ सुपरजाइंट्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ की चार मैचों में से यह दूसरी जीत है। मैच में टॉस हारने के बाद लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल में 203 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में पांच बार की चैंपियन मुंबई ने आखिरी ओवर में 191 रन ही बना सकी। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की यह चार मैचों में से तीसरी हार है।

लखनऊ के खिलाफ एकाना क्रिकेट स्टेडिय में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। मुंबई के दोनों ओवर बल्लेबाज विल जैक्स और रयान रिकेल्टन जल्दी आउट हो गए। इसके बाद मुंबई के लिए नमन धीर और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर मोर्चा संभाला। नमन धीर मुंबई के लिए 24 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने सधी हुई बैटिंग करते हुए टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाया। सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन बल्लेबाजी में वह टीम के लिए संघर्ष करते हुए दिखे।सूर्यकुमार के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और हार्दिक की जिम्मेदारी थी कि वह मैच को फिनिश करें, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने आखिर के तीन ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया।

लखनऊ सुपरजायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 203 रन बनाये।

एलएसजी ने के लिए मिचेल मार्श ने 31 गेंद में 60 जबकि एडेन मारक्रम ने 38 गेंद में 53 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने चार ओवर में 36 रन देकर पांच विकेट लिए।

खिलाड़ियों को जड़ी-बूटी आधारित सप्लीमेंट्स के अंधाधुंध उपयोग से बचने की चेतावनी, पूरी नींद जरूरी

पटियाला,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) में हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हरमोनाइजिंग मूवमेंट: योग और खेल विज्ञान का समन्वय में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खिलाड़ियों में नींद की कमी और हर्बल सप्लीमेंट्स का लापरवाह उपयोग उनकी सेहत और प्रदर्शन पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सतबीर सिंह खालसा ने कहा कि योग नींद को बेहतर बनाता है, जिससे मोटापा, मधुमेह, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, नींद मानसिक और शारीरिक पुनर्प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए खेल शिक्षा में नींद के महत्व को शामिल करना चाहिए।

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने भी इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा, योग आपके मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। खेल के दबाव वाले पलों में यह आत्मसंयम बनाए रखने में सहायक होता है। आधुनिक खेलों में मानसिक नियंत्रण, शारीरिक कौशल जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

सम्मेलन में हर्बल सप्लीमेंट्स के दुरुपयोग पर भी जोरदार चर्चा हुई। खेल प्राधिकरण (साई) के एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डॉ. वज़ीर सिंह फोगाट ने कहा कि खिलाड़ी ताकत, सहनशक्ति, इम्युनिटी और रिकवरी बढ़ाने के लिए हर्बल सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, जिन्हें अक्सर प्राकृतिक और सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, खेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा कुल 186 डोपिंग उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग में पाए गए। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. शिवकुमार हारती (एम्स, नई दिल्ली) ने कहा कि हर्बल सप्लीमेंट्स का सेवन खिलाड़ी की प्रशिक्षण तीव्रता, शारीरिक स्थिति और व्यक्तिगत लक्ष्य के अनुसार ही होना चाहिए। खेल पोषण विशेषज्ञ डॉ. वाणी भूषणम गोला ने चेताया कि बिना विशेषज्ञ सलाह के हर्बल सप्लीमेंट्स का सेवन विषाक्तता या हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है।

सर्बिया में फीफा प्रेसीडेंट गियानी इनफेंटिनो व यूईएफए प्रेसीडेंट एलेकसेंडर सीफेरिन

सर्बिया में फीफा प्रेसीडेंट गियानी इनफेंटिनो व यूईएफए प्रेसीडेंट एलेकसेंडर सीफेरिन कांग्रेस के दौरान तस्वीरों के साथ पोज देते हुए।

अनुभवी पिस्टल शूटर राही सरनोबत ने बताई जीवन के सबसे कठिन दौर से उबरने की कहानी

देहरादून,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

अनुभवी पिस्टल शूटर और दो बार की ओलंपियन राही सरनोबत ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में जबरदस्त वापसी करते हुए महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। 34 वर्षीय राही के लिए यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन दौर से उबरने की कहानी है।

हाउस ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट (गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन की पहल) के एक हालिया एपिसोड में राही ने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की कि कैसे उन्होंने न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम जैसी जटिल और रहस्यमयी बीमारी से लड़ाई लड़ी और अब एक बार फिर ओलंपिक पदक के सपने को जीने के लिए मैदान में उतरी हैं।

राही के बीमार होने की शुरुआत 2022 में हुई, जब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के नेशनल कैंप के लिए तैयारी कर रही थीं। अचानक उन्हें शरीर में जलन और तंत्रिकाओं में दर्द जैसी समस्याएं महसूस होने लगीं। कई टेस्टों के बावजूद कोई ठोस निदान नहीं मिला। उन्होंने बताया मैं बिस्तर पर लेट भी नहीं सकती थी, महीनों तक बैठकर सोती थी। बाद में न्यूरोलॉजिकल जांचों के बाद उन्हें न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम का पता चला। उन्होंने कहा, इस बीमारी का न तो कोई निश्चित पैटर्न है, न ही कोई तय इलाज। यह हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री पर निर्भर करता है। यही बात इसे और भी डरावना बना देती है।

राही ने बताया कि वे महीनों तक दिन में 17–20 घंटे सोती थीं, और बस छत को घूरती रहती थीं। उन्होंने कहा, मैं सामान्य जीवन नहीं जी पा रही थी, मैं बस वापस जिंदगी में लौटना चाहती थी, खेल तो बाद की बात थी। यह पहली बार नहीं था जब राही को खेल में वापसी करनी पड़ी हो। 2014 में उनकी शूटिंग हाथ की कोहनी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उबरने में उन्हें सात महीने लगे। फिर उन्होंने वापसी करते हुए 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता और 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन राही के अनुसार इस बार की वापसी बिल्कुल अलग रही।

उन्होंने बताया, पिछली बार यह एक सामान्य चोट थी, जिसका तय इलाज और प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार तो मैं सिर्फ सामान्य जीवन जीने की चाह रख रही थी। शूटिंग तो सोच में भी नहीं थी। ठीक होने की राह भी आसान नहीं रही। न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें दर्द के बावजूद फिजियोथेरेपी शुरू करने की सलाह दी। उनकी पहली कसरत थी – 20 मिनट तक बैठकर एक टीवी शो देखना। लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वे यह भी नहीं कर पाईं। फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके साथ दिन में कई घंटे काम किया।

आज राही खुद को एक बदली हुई एथलीट मानती हैं। उन्होंने कहा, अब मैं खुद के लिए खेलती हूं। अब यह दुनिया को कुछ साबित करने के लिए नहीं है। यह मेरा सपना है, जिसे एक कारण से मेरे अंदर डाला गया है। मैं इसे एक और मौका देना चाहती हूं।

उन्होंने अंत में कहा, अब खोने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं और भी साहसी बन गई हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे उस व्यक्ति के रूप में याद करें जिसने चीजों को मुमकिन बनाया।

हीरो हॉकी इंडिया लीग ने भारत में 4.1 करोड़ से अधिक दर्शकों को किया आकर्षित

पुरुषों की लीग ने 3.29 करोड़ और महिलाओं की लीग ने 1.51 करोड़ दर्शकों को जोड़ा

नई दिल्ली,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2024–25 की बहुप्रतीक्षित वापसी ने भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देशभर में खेल के प्रति जुनून को फिर से जीवंत कर दिया है। सात साल के अंतराल के बाद पुरुषों की लीग की वापसी और पहली बार महिला लीग की शुरुआत ने इस संस्करण को ऐतिहासिक बना दिया। लीग की रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या और डिजिटल प्रभाव इस बात का प्रमाण हैं कि हॉकी आज भी लाखों भारतीयों के दिलों की धड़कन बनी हुई है।

हीरो एचआईएल 2024–25 ने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है। इस बार कुल 4.08

करोड़ दर्शकों तक पहुंच दर्ज की गई, जो एचआईएल 2017 के 2.75 करोड़ दर्शकों की तुलना में 48 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि है। पुरुषों का फाइनल मुकाबला अकेले 30.7 लाख दर्शकों ने देखा, जबकि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय मैच 29.2 लाख दर्शकों तक पहुंचा। भारत के अलावा 18 हॉकी खेलने वाले देशों में 50 लाख से अधिक दर्शकों ने टीवी और ओटीटी के माध्यम से लीग का आनंद लिया।

इस बार लीग ने परंपरागत दर्शक वर्ग के अंतर को भी तोड़ा है। सामान्यत: पुरुष और महिला खेलों के दर्शकों में छह गुना तक का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन हीरो एचआईएल ने इस सोच को बदल दिया। कई मौकों पर महिला मुकाबलों को भी पुरुष मुकाबलों के समान दर्शक मिले। 44 पुरुष मुकाबलों को 3.29 करोड़ दर्शकों (2.35 करोड़ टीवी पर और 94 लाख ओटीटी पर) ने देखा, वहीं 13 महिला मुकाबलों को 1.51 करोड़ दर्शकों (1.05 करोड़ टीवी पर और 45.9 लाख ओटीटी पर) ने देखा।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, हीरो एचआईएल 2024–25 की सफलता भारत में हॉकी के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक है। प्रशंसकों, ब्रांडों और प्रसारकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया लीग की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। हम भविष्य में भी भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सिर्फ टीवी और स्ट्रीमिंग ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एचआईएल की गूंज सुनाई दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हॉकी इंडिया के 3,000 से अधिक पोस्ट्स पर 1 अरब से अधिक व्यूज़ दर्ज किए गए, जो एक सक्रिय और जीवंत हॉकी समुदाय का प्रमाण है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, हीरो एचआईएल की वापसी केवल आंकड़ों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रशंसकों और खिलाड़ियों में जागे नए उत्साह के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। महिला लीग की शुरुआत समावेशिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हीरो हॉकी इंडिया लीग की यह सफलता टोक्यो ओलंपिक के बाद से हॉकी की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाती है, जहां पहले सप्ताह में हॉकी ने कुल 6.9 करोड़ दर्शकों में से 15.2 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी।

भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधि में उत्पादन और बिक्री में मामूली गिरावट

नई दिल्ली,04 अप्रैल (एजेंसियां)।

भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधि में उत्पादन और बिक्री में मामूली गिरावट के साथ मार्च महीने में थोड़ी धीमी रही है, इसकी जानकारी शुक्रवार को एक मासिक सर्वेक्षण से मिली है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक फरवरी के 59.0 से घटकर मार्च में 58.5 पर आ गया है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के अनुसार, 50 से ऊपर अंक का मतलब है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है जबकि 50 से कम का आशय है कि संकुचन हो रहा है। एचएसबीसी के भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने इस संकेत को तर्कसंगत बताया, भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च 2025 में 58.5 रही है जो पिछले महीने से थोड़ा कम है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग काफी हद तक उत्साहजनक रही, हालांकि यह पिछले महीने की तुलना में क्रमिक रूप से कम रही। कीमत की दृष्टि से मार्च में तैयार माल शुल्क पर मुद्रास्फीति साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर आ गई है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग काफी हद तक उत्साहजनक रही

सर्वेक्षण प्रतिभागियों के अनुसार, मार्च में सेवा अर्थव्यवस्थाओं में भर्तियों की गतिविधि में कमी आई है। उपभोक्ता सेवा कंपनियां मार्च में सबसे अधिक उत्साहित रही हैं, उसके बाद वित्त एवं बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, तथा परिवहन, सूचना और संचार सेक्टर। इस दौरान, भारतीय निजी क्षेत्र की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि कंपनियों ने नए ऑर्डरों में वृद्धि का स्वागत किया है। एचएसबीसी इंडिया कम्पोजिट आउटपुट सूचकांक फरवरी के 58.8 से मार्च में सात महीने के उच्च स्तर 59.5 पर पहुंच गया है।

न्यूज़ ब्रीफ

व्हाइट हाउस के दस्तावेज में भारत पर शुल्क 27 से घटाकर किया गया 26 प्रतिशत

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' के दस्तावेज में भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। शुल्क नौ अप्रैल से लागू होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों के खिलाफ जवाबी शुल्क की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाई जाने वालीं नई शुल्क दरों का उल्लेख था।चार्ट के अनुसार, भारत ''मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं'' सहित 52 प्रतिशत शुल्क लेता है और अमेरिका अब भारत से 26 प्रतिशत का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। हालांकि, व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का जिक्र था लेकिन नवीनतम अद्यतन दस्तावेज में इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क के एक प्रतिशत कम होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

थॉमस कुक इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बने कार्तिक आर्यन

मुंबई। विदेशी मुद्रा सेवा प्रदाता थॉमस कुक इंडिया ने बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन को अपने बॉर्डरलेस यात्रा कार्ड के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि यह कदम विशेष रूप से युवा भारत को लक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कार्तिक आर्यन अपने करिश्माई व्यक्तित्व और युवाओं के साथ मजबूत जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रशंसक आधार, आकांक्षात्मक छवि, और विशेष रूप से मिलेनियल्स और जेनजेड के बीच उनकी पहचान उन्हें एक प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। वह भारत के नए युग के यात्री की भावना को व्यक्त करते हैं, जो उन्हें थॉमस कुक के फॉरेक्स विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है ।

पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर, दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए है और डीजल प्रति लीटर 87.62 रुपए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत दे सकती है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 94.72 रुपए है और डीजल प्रति लीटर 87.62 रुपए है। इसके अलावा मुंबई में प्रति लीटर की कीमत 103.94 रुपए और डीजल प्रति लीटर के दाम 89.97 रुपए है। वहीं कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 103.94 रुपए और डीजल का भाव 90.76 रुपए है। आखिर में चेन्नई में प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 100.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.44 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले 14 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम हुए थे। जबकि, उससे पहले 22 मई 2022 में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके बाद पेट्रोल 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल 16 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था। वहीं, पेट्रोलियम मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर ग्लोबल लेबल पर कच्चे तेल की कीमत अभी की तरह रही तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखने को मिल सकती है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

युनुस को...

उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए यूनुस ने कहा था कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। भारत ने इस टिप्पणी की निंदा की थी और बांग्लादेश के अधिकारियों ने यूनुस के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि यूनुस के बयान पर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की थी लेकिन बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना होने से पहले जारी किये गये अपने बयान में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार को जवाब देते हुए कहा था कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्सटेक के केंद्र में स्थित है। उन्होंने अपने बयान में पूर्वोत्तर राज्यों की प्रधानता को रेखांकित किया था।हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बिम्सटेक समूह के नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में भी एक साथ बैठे नजर आये। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा ने इस भोज की मेजबानी की थी। यूनुस के कार्यालय ने कुछ तस्वीरें साझा कीं थीं, जिसमें चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित होटल शांगरी-ला में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख को मोदी के बगल में बैठे देखा जा सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यालय के एक्स हैंडल पर मोदी की बैंकॉक में हुई सभी द्विपक्षीय मुलाकातों के फोटो अपलोड किये गये हैं मगर मोहम्मद यूनुस के साथ मोदी का कोई फोटो यह रिपोर्ट तैयार करते समय तक नहीं जारी किया गया था। यानि मुलाकात तो हो गयी है मगर रिश्तों की तल्खी बरकरार है और यूनुस को मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया है।बता दें कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात कर रहे थे वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर कड़ा रुख भी अपनाया है। मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि पांच अगस्त, 2024 से 23 मार्च तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित 2,400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और उम्मीद है कि पड़ोसी देश इन मामलों की गहन जांच करेगा और इनमें से किसी भी घटना को राजनीति से प्रेरित कहे बिना सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। दरअसल विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लिया है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर ध्यान दिया है और विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि 16 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ बैठक के दौरान ये अपेक्षाएं दोहराई गईं। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।

नेपाल भारत के...

नेपाल भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' के तहत नई दिल्ली का प्राथमिकता वाला साझेदार है।दोनों नेता भारत-नेपाल देशों और लोगों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। यह बैठक दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखती है। पीएम मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट किया, बैंकॉक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ एक सार्थक बैठक हुई। भारत नेपाल के साथ संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। हमने भारत-नेपाल मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। हमने इस वर्ष के बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के कुछ प्रमुख सकारात्मक परिणामों के बारे में भी बात की, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन और समुद्री परिवहन के क्षेत्रों में।इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके सामने हिंदुओं सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई।पिछले साल अगस्त में पड़ोसी देश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन और यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी हित के सभी मुद्दों को दोनों देशों के बीच रचनात्मक चर्चा के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से संबोधित और हल किया जाना जारी रहेगा।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संबंधों के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है।

वक्फ विधेयक संसद...

इससे विशेष रूप से उन लोगों को सहायता मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर रहने के साथ उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।

श्री मोदी ने लिखा, संसदीय और समिति चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार, जिन्होंने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार। एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद के महत्व की पुष्टि हुई है।प्रधानमंत्री ने लिखा, दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी का पर्याय रही है। इससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। संसद से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे।उन्होंने कहा, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां व्यवस्था अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी। व्यापक रूप से, हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक सहानुभूति रखने वाले भारत का निर्माण भी कर सकते हैं।

मणिपुर हिंसा में ...

वहां औसतन एक साल में 200 से अधिक दिन मणिपुर में बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहता था और 1000 से अधिक लोग एनकाउंटर्स में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जातीय हिंसा और नक्सलवाद में फर्क है। दो समुदायों के बीच जब नस्लीय हिंसा होती है और हथियार लेकर देश की सरकार और जनता के खिलाफ खड़े नक्सलवादियों, दोनों से निपटने का तरीका अलग-अलग है। विपक्ष को इन दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं दिखता है। शाह ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में सैकड़ों साल तक संदेशखली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा लेकिन विपक्ष ने कुछ नहीं किया और आर जी कार मामले में भी कुछ नहीं किया। यह डबल स्टैंडर्ड ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 लोग मारे गए हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनावी हिंसा में ही ढाई सौ लोग मार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष दो सीटें जीतकर हमें सबक सिखाना चाहता है लेकिन देश की जनता ने तीन आम चुनावों में लगातार इन्हें सबक सिखाया है। मणिपुर की जातीय हिंसा में अब तक 260 लोग मारे गए हैं जिनमें से 70 प्रतिशत पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मणिपुर में नस्लीय हिंसा हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि मणिपुर में 1993 से 1998 तक 5 साल तक नागा-कुकी संघर्ष हुआ, जिसमें 750 मौतें हुईं और छिटपुट घटनाएं एक दशक तक चलती रहीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। 1997-98 में कुकी-पाइते संघर्ष हुआ, जिसमें 50 से अधिक गांव नष्ट हुए, 13 हज़ार लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 5 हज़ार घर जलाए गए। शाह ने कहा कि 1993 में छह माह तक चले मैतेई-पंगल संघर्ष में 100 से अधिक मृत्यु हुईं थीं। इन हिंसाओं के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी पार्टी ने हिंसा का राजनीतिकरण नहीं किया था लेकिन आज विपक्ष राजनीतिक तंज कसकर मणिपुर के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से पहले, 7 साल के शासन में मणिपुर में एक भी दिन बंद और कर्फ्यू नहीं रहा और न ही हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण मणिपुर के जनजातीय और गैरजनजातीय समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि यह हिंसा न तो सरकारी विफलता है, न आतंकवाद और धार्मिक संघर्ष है, बल्कि हाई कोर्ट के एक फैसले की व्याख्या से दो समुदायों में फैली असुरक्षा की भावना के कारण हुई जातीय हिंसा है। उन्होंने कहा कि अगले ही दिन सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को स्टे कर दिया था क्योंकि वहएक असंवैधानिक आदेश था।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे अजय कुमार भल्ला को वहां का राज्यपाल बनाया गया है और अब वहां शांति है। उन्होंने सदन को बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई बैठकें हो चुकी हुई हैं, इस सदन के चलने के समय भी दो बैठकें हुई हैं और दोनों समुदायों की नई दिल्ली में जल्द ही एक और बैठक होने की संभावना है। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों समुदाय स्थिति को समझेंगे और संवाद का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य होते ही एक भी दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन उनकी पार्टी की नीति नहीं है।

वक्फ संशोधन ...

गुरुवार को चर्चा शुरू हुई और लगातार चली बैठक के बाद शुक्रवार तड़के यह विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी।इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है। विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा की बैठक (शुक्रवार) रात 2:30 बजे के बाद तक चली। विपक्ष के सभी संशोधन खारिज हो गए।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा।

वक्फ संशोधन ...

श्री रिजीजू ने कहा कि संसद का बजट सत्र, 2025, जो 31 जनवरी 2025 में शुरू हुआ था, चार अप्रैल, 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच दोनों सदन गुरुवार 13 फरवरी को मध्यावकाश के लिये स्थगित कर दिए जाने के बाद सोमवार 10 मार्च को पुनः समवेत हुए थे ताकि विभाग संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुतन मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपनी रिपोर्ट दे सकें। बजट सत्र के पहले आगके दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कुल नौ बैठकें हुई थी। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।श्री रिजीजू ने कहा कि इस सत्र के दौरान, कुल 11 विधेयक (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 1) पुरःस्थापित किए गये। सोलह विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए गए और 14 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए लौटाए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या 16 है। बजट सत्र, 2025 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग 118 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 119 प्रतिशत रही।उन्होंने कहा कि यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार 31 जनवरी, को संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री रामवीर सिंह बिधूडी ने पेश किया था और श्री रविशंकर प्रसाद ने इसका समर्थन किया था। इस मद पर लोकसभा में 12 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 23 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में 173 सदस्यों ने भाग लिया था। राज्यसभा में इसे श्रीमती किरण चौधरी ने पेश किया और श्री नीरज शेखर ने इसका समर्थन किया था। इस मद पर राज्यसभा में 15 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 21 घंटे 46 मिनट तक चर्चा की गयी। चर्चा में 73 सदस्यों ने भाग लिया था। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट शनिवार, 01 फरवरी को पेश किया गया। सत्र के पहले आग के दौरान दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोक सभा में 12 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 169 सदस्यों ने चर्चा में आग लिया तथा राज्य सभा इस पर 15 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 56 मिनट चर्चा हुई और चर्चा में 89 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को 21 मार्च को सदन में मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21 मार्च को ही लोक सभा में पुरःस्थापित, विचार और पारित कर दिया गया।उन्होंने कहा कि केंद्र के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैचः वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को भी 11 मार्च को लोक सभा में पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2025 लोक सभा द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया।उन्होंने कहा कि राज्यसभा में शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्यसभा ने केन्द्र के संबंध में वर्ष 2024-25 अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच, वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक को 18 मार्च को लौटा दिया। वर्ष 2025-20 के लिए केंद्र की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, 2025 को राज्य सभा द्वारा भी 27 मार्च को लौटा दिया गया। इस प्रकार संसद के सभी में संपूर्ण वितीर्थ 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया गया।श्री रिजीजू ने कहा कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति ट्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गयी, उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को भी दोनों सदनी में क्रमशः 3 और 4 अप्रैल, को स्वीकृत किया गया।उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपतियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपतियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपतियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके लागू करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को भी निरस्त कर दिया गया।संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने की मांग करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान करता है, राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है और राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करता है।उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 भी पारित किया गया जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है, जो सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराएगा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों संचालित करेगा। यह डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित करेगा।उन्होंने कहा कि भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए कानूनी को सरल बनाने और वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पारित किया गया है। बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया गया ताकि शासन मानकों में सुधार हो, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग में स्थिरता प्रदान की जा सके, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और नामांकन आदि के संबंध में ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

खामोशी का...

उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल की निंदा की और कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रित एक गहन चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों में आम सहमति थी कि संशोधन जम्मू कश्मीर में 'मुसलमानों और उनकी आस्था पर सीधा हमलाट है।कांग्रेस नेता व विधायक निजाम-उद-दीन भट ने कहा कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार में सभी विधायक सदन के नेता के पीछे मजबूती से खड़े हैं।

विधेयक वक्फ और जनादेश जैसे संवेदनशील मामलों पर, इस बात पर सर्वसम्मति है कि इन मुद्दों को केंद्र के साथ बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसने जम्मू-कश्मीर सरकार और राजभवन के बीच एक बड़ा गतिरोध पैदा कर दिया, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हाल ही में 48 जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) अधिकारियों के तबादलों का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इन तबादलों को अवैध करार देते हुए दावा किया है कि इन्हें निर्वाचित सरकार से आवश्यक मंजूरी के बिना किया गया।

सीएम...

तनवीर ने कहा कि गठबंधन जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों को कमतर नहीं होने देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र के साथ उनके समन्वय को गलत नहीं समझा जाना चाहिए, उन्होंने अधिकारियों से हाल के निर्णयों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है, जिसमें गठबंधन ने उन निर्णयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है, जो उनके अनुसार उनके अधिकार को दरकिनार करते हैं। आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।

ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब एलजी ने 14 अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और 26 सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट सहित 48 मध्यम श्रेणी के जेकेएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। एलजी ने पुलवामा, कुपवाड़ा, बसोहली, डोडा, अनंतनाग, सुंदरबनी, राजौरी, नौशेरा, बारामुल्ला, श्रीनगर, गंदेरबल, कठुआ, भद्रवाह और हंदवाड़ा में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के तबादले और नियुक्ति का आदेश दिया।अब्दुल्ला सरकार इस कदम को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन मानती है, और तर्क देती है कि अखिल भारतीय सेवा कैडर के बाहर के अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति निर्वाचित सरकार का विशेष विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से एलजी से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, उन्होंने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई सरकार के अधिकार को कमजोर करती है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया है, और चिंता व्यक्त की है कि राजभवन द्वारा बार-बार हस्तक्षेप निर्वाचित नेतृत्व की वैधता को कम कर रहा है। हालांकि एलजी और सरकार के बीच तनाव कुछ समय से चल रहा है, लेकिन सिन्हा के नवीनतम निर्देश ने केंद्र शासित प्रदेश में दो सत्ता केंद्रों के बीच दरार को और गहरा कर दिया है।

अब्दुल्ला ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू को 48 अधिकारियों के तबादले को रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में उनकी प्रत्यक्ष मंजूरी के बिना गैर-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की कोई पोस्टिंग न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एलजी का हालिया कदम नौकरशाही तंत्र पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास का संकेत देता है, खासकर ऐसे समय में जब निर्वाचित सरकार अपने प्रस्तावित शासन नियमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही है।

मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश ऐसे समय में आया है जब निर्वाचित सरकार लगभग एक महीने पहले बनाए गए व्यावसायिक नियमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही थी और बिना किसी भ्रम के सुचारू शासन की सुविधा के लिए मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को भेजी थी। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान अब्दुल्ला ने शासन में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, जब तक हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक व्यावसायिक नियम स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने पहले भी जम्मू-कश्मीर में दोहरे शासन मॉडल की आलोचना की है और इसे विनाश का नुस्खा बताया है।

कांग्रेस नेताओं ने भी सिन्हा के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता गुलाम अहमद मीर ने तर्क दिया कि अधिकारियों के तबादलों से पहले एलजी को नए शासन नियमों की मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासन में जनता के विश्वास को कम कर सकती है। मीर ने कहा, एलजी को अच्छी तरह से पता था कि दिल्ली में व्यावसायिक नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, फिर भी उन्होंने यह कदम उठाया। इससे गलत संदेश जाता है कि प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है।

BOOK YOUR DISPLAY CLASSIFIED ADVERTISEMENTS AT
Timings : 9 am to 7 pm
Head office
SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,
APIE, Balanagar, Hyderabad - 500 037
City office
SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
4th Floor, 19 Towers (T19),
Near Bus Stand, Ranigunj,
Secunderabad - 500 003
8688868345

शुभ लाभ
म्हारो भाग्यनगर
दैनिक हिन्दी शुभ लाभ, हैदराबाद, शनिवार, 05 अप्रैल, 2025

शुभ लाभ
आपकी सेवा में
शुभ लाभ से जुड़ी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए मो. 86888 68345 पर संपर्क करें।

दिव्यांगों के लिए नारायण कृत्रिम अंग मापन शिविर कल

हैदराबाद, 4 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एनजीओ नारायण सेवा संस्थान तेलंगाना में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक भव्य निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम रविवार, 6 अप्रैल को मिनर्वा गार्डन, गार्डन्स स्ट्रीट, चंपापेट, हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा।नारायण सेवा संस्थान के मीडिया एवं जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ के अनुसार, संगठन दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जिन्होंने दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण अपने अंग खो दिए हैं, साथ ही उन लोगों की भी सहायता करना है जो पुराने या भारी कृत्रिम अंगों से जूझ रहे हैं। पद्म श्री पुरस्कार विजेता कैलाश मानव से प्रेरित होकर, संगठन पिछले 40 वर्षों से मानवता और दिव्यांगों की सेवा के लिए समर्पित है।तेलंगाना के दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करने के मिशन के साथ, नारायण सेवा संस्थान 6 अप्रैल रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चंपापेट के मिनर्वा गार्डन में निःशुल्क दिव्यांग निदान, शल्य चिकित्सा चयन और नारायण अंग माप शिविर का आयोजन कर रहा है।संस्था की संरक्षक अलका चौधरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस निःशुल्क शिविर के महत्व पर प्रकाश डाला।उन्होंने बताया कि संस्थान के अनुभवी ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिक डॉक्टरों की एक टीम लाभार्थियों की जांच करेगी और उच्च गुणवत्ता वाले, हल्के और टिकाऊ नारायण कृत्रिम अंगों के लिए सटीक माप लेगी।ये कस्टम-मेड कृत्रिम अंग लगभग दो महीने बाद आयोजित होने वाले फिटमेंट कैंप में निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।शिविर समन्वयक महेंद्र सिंह रावत ने यह भी बताया कि शिविर में आने वाले रोगियों और उनके परिवारों को निःशुल्क भोजन, चाय और जलपान उपलब्ध कराया जाएगा।संवाददाता सम्मेलन के दौरान निदेशक गौर, संरक्षक चौधरी, पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता रिद्धेश जागीरदार, अभय चौधरी और समन्वयक रावत ने संयुक्त रूप से शिविर के पोस्टर का अनावरण किया।एक अन्य संरक्षक जसमत भाई ने बताया कि हैदराबाद से सम्मानित व्यक्तियों और मंत्रियों को शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।निदेशक गौर ने दिव्यांग व्यक्तियों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

भाग लेने के इच्छुक लोगों को अपनी दिव्यांगता के प्रमाण के रूप में अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें लानी होंगी।शिविर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति संस्था के हेल्पलाइन नंबर: 70235-09999 पर संपर्क कर सकते हैं।

1985 से, नारायण सेवा संस्थान मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रहा है।इसके संस्थापक कैलाश मानव को मानवीय सेवा में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने चिकित्सा सहायता, शिक्षा, कौशल विकास और खेल अकादमियों के माध्यम से हजारों दिव्यांग व्यक्तियों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। 2023 में, अग्रवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

अब तक नारायण सेवा संस्थान ने 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए हैं। संगठन अब तेलंगाना में दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों का विस्तार कर रहा है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर अपना जीवन पुनः प्राप्त करने और गतिशीलता हासिल करने में मदद मिल सके।

उमियाधाम मंदिर में गौ ग्रास के लिए गौ दान पात्र वितरित

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

लव फोर काऊ फाण्डेशन के पदाधिकारीयो द्वारा गौमाता के लिए प्रतिदिन एक रूपये दान योजना अभियान कार्याम का मेडचल जिल्ले के विभिन्न क्षेत्रो में जोर दार प्रचार प्रसार किया गया। आज यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में लव फोर काऊ फाउण्डेशन की ट्रस्टी रंजना शाह एवं विरेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि आज मेडचल स्थित उमियाधाम मंदिर में श्री कच्छ कडवा पाटीदार समाज (हैदराबाद - सिकंदराबाद) द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत धर्म मंगल महोत्सव में लव फॉर काऊ फाउंडेशन द्वारा गौमाता के प्रतिदन एक रूपये के दान के संकल्प अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रो में गौ ग्रास हेतु गौ दान पात्रो का वितरण किया तथा इसका जोरदार प्रचार प्रसार भी किया गया।

कथा वाचक प.पू. आशीषभाई व्यास को फाउंडेशन की ओर से लव फॉर काऊ फाउंडेशन के चेरमेन जसमतभाई पटेल, ट्रस्टी जसवंत सुराणी ने स्मृति चिन्ह भेटकर सम्मानित किया गया।

कथा कार्याम प्रांगण में दान पात्र का वितरण किया गया जिसका बडी संख्या में महिलाओ ने लाभ लिया। दान पात्रो को कथा वाचक प.पू. आशीषभाई व्यास द्वारा दानपात्रो का वितरण के पूर्व विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ किया गया। उनके स्व-हस्तो से गौ ग्रास हेतु गौ दान पात्रो में दान राशी को पात्र में डालकर इसमें सहयोग किया गया।

अवसर पर लव फाश्री कच्छ कडवा पाटीदार समाज ट्रस्ट चेरमेन कांतीलाल गोराणी, समाज अध्यक्ष अमृतभाई छाभैया, पाटीदार महिला मंडल की अध्यक्ष दिनाबेन छाभैया, उपाध्यक्षा दमयंतीबेन लींबाणी, तेलंगाना आंध्रप्रदेश कच्छ कडवा पाटीदार महिला संघ अध्यक्षा चंदाबेन लींबाणी एवं कार्यकारीणी सदस्याये, भद्रीनाथ मंदिर मेडचल के अध्यक्ष विाम सिंह, सचिव निशा कार्की भी उपस्थित थी।

गौमाता के प्रतिदन एक रूपये के दान के संकल्प अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रो में गौ ग्रास हेतु गौ दान पात्रो का वितरण तथा इसका जोरदार प्रचार प्रसार किया जा रहा है

कथा वाचक प.पू. आशीषभाई व्यास ने कहा कि इस संकल्प कार्याम से वह अत्यंत ही प्रभावीत है। उन्होने आगे कहा कि हम सभी को संकल्प करना है कि आज के बाद यथा संभव अपने परिवार में गाय के दूध का ही प्रयोग करेंगे । इसके साथ ही साथ अपने कथाओ के माध्यम से अपने भक्तो, दान दाताओ, इष्ट मित्रों को भी गाय के दूध को प्रयोग लाने की प्रेरणा देंगे यह गो भक्ती के प्रति यह मेरा संकल्प है।

फाउण्डेशन के चेयरमेन जसमत पटेल ने कहा कि गौभक्तों से निवेदन है कि गौमाता की सेवार्थ हेतु आप अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चो के जन्मदिन, पित्तरो की पुण्य दिवस आदि किसी भी प्रसंग पर गौमाता के लिए दान देकर जीवन को धन्य बनायें।

यह योजना को प्रारंभ करके 10 वर्ष पूर्ण हुए है और आगामी 1 वर्ष में 20 हजार दान पात्रो का वितरण करने की योजना है। उन्होने सभी से निवेदन किया की दानपात्रो का ज्यादा से ज्यादा संख्या में वितरण किया जाये जिससे नगरद्वय की आस पास की गौशालाओ को हो रही आर्थिक कठीनाईयो में राहत हो।

उत्तम कुमार रेड्डी ने लाभार्थियों के साथ भोजन किया

निःशुल्क चावल योजना की शुरुआत से पूरे राज्य में जश्न का माहौल

सूर्यपेट, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार शाम को सूर्यपेट में एक लाभार्थी परिवार के साथ घर का बना खाना खाया, जिससे राज्य की महत्वाकांक्षी निःशुल्क चावल वितरण योजना की शुरुआत हुई। योजना के तहत उपलब्ध कराए गए उच्च गुणवत्ता वाले चावल का उपयोग करके तैयार किए गए दोपहर के भोजन की मेजबानी पलादुगु बुज्जम्मा और वेंकटैया ने सूर्यपेट शहर के वार्ड खख में अपने निवास पर की।यह एक बड़ी राज्यव्यापी पहल का हिस्सा था, जिसमें जनप्रतिनिधि भोजन में भाग लेने और निःशुल्क चावल कार्यक्रम की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए लाभार्थियों के घर जा रहे हैं। 30 मार्च को हुजूरनगर निर्वाचन क्षेत्र में उगादी दिवस पर आधिकारिक रूप से शुरू की गई इस योजना को पूरे तेलंगाना में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य भर में 3.10 करोड़ लोगों - यानी कुल आबादी का 84% - को हर महीने 6 किलो निःशुल्क चावल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा और कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी 6 अप्रैल को श्री सीता राम कल्याणम में भाग लेने के बाद श्री राम नवमी के अवसर पर भद्राचलम में एक लाभार्थी परिवार के साथ भोजन करके इसमें शामिल होंगे।

मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद शाखा द्वारा अमृत धारा का शुभारंभ

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

सिकंदराबाद स्थित मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद शाखा मंत्री पन्नालाल भाटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिकंदराबाद शाखा अध्यक्ष पंकज राठौर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रकल्प अमृत धारा के तहत अपनी शाखा कि तृतीय अस्थाई अमृत धारा का शुभारंभ पोट मार्केट सिकंदराबाद में कि गई ।इस अवसर पर पोट मार्केट ज्वैलर्स असोसिएशन के महामंत्री सुरेश कोठारी व सह कोषाध्यक्ष कैलाश लोया प्रांतीय अध्यक्ष मनीष नाहर, सिकंदराबाद शाखा भूतपूर्व अध्यक्ष प्रदीप मंखाणा, मदनलाल सांखला , निवर्तमान अध्यक्ष जसवंत राज मुथा,वरिष्ठ नारायण चावड़ा,कैलाश वैष्णव, दिनेश गहलोत, दिनेश पूरी, गौतम भायल, आदि का सराहनीय योगदान रहा।गौ सेवक स्व श्री केवलचन्द राठौड़ की स्मृति में उनके परिवार द्वारा अस्थायी टेंट प्रदान किया गया।कार्यक्रम के अंत में पधारे हुए सभी अतिथियों का एवं सदस्यों गणों का शाखा के अमृत धारा संयोजक जीतू चावड़ा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

राधे राधे ग्रुप द्वारा नियमित अन्नदान के अंतर्गत शुक्रवार को नामपल्ली स्थित पाब्लिक गार्डन, पिलर नं. ए1265 के समीप जरूरतमंद लोगों में अल्पाहार सेवा की गई। इस अवसर पर-सतीश गुप्ता, आशा अग्रवाल, रामप्रकाश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, गोपाल गोयल, महेश गुप्ता, सुशील गुप्ता, संजय गोयल, मायारामजी अग्रवाल, नंदकिशोर अग्रवाल, भगतराम गोयल, अशोक गुप्ता एस.जे, कैलाश चंद केडिया, निर्मला केडिया, प्रीतिका अग्रवाल, ई. जगन, अनिता गोयल, रमेश गोयल, नंदा गोयल, खनैया गोयल, रुचित गोयल, दीपा गोयल, अवनीश गोयल, श्रुति गोयल, अजय गोयल, श्याम सुंदर अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, एवं राधे राधे ग्रुप के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

भाग्यनगर तेलंगाना ज्वैलर्स एवं पॉन ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने मदनलाल रावल

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

मल्लापुर भाग्य नगर तेलंगाना ज्वैलर्स एवं पॉन ब्रोकर ऐसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को मल्लापुर बडेर में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। वर्तमान अध्यक्ष कालुरामकाग व सचिव बाबुलाल मुलेवा ने आम सदस्यों की बैठक में चुनाव कराने का फैसला किया एवं दो चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये। जिसमें नारायण लाल परिहार व चन्द्रप्रकाश गेहलोत शामिल थे। दोनों ने अपने विवेक से बहुत अच्छी चुनाव प्रक्रिया पुर्ण कराई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष में मदनलाल रावल, उपाध्यक्ष-1 मोहनलाल हाम्बड़, उपाध्यक्ष-2 महावीर जैन, उपाध्यक्ष-3 तेजाराम काग, उपाध्यक्ष-4 राजु शर्मा, सचिव तुलसाराम सिन्दडॉ, सहसचिव हरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष - ओमप्रकाश पंवार, मीडिया प्रभारी सुरेश सैणचा

चुने गये। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदनलाल रावल ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

बंजारा हिल्स यूबीआई कॉलोनी में रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना एवं महाप्रसाद के लिए बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर राघवेंद्र राव को आमंत्रित करते हुए सतीश कुमार जाजू एवं आनंद चोपड़ा।

श्री दधिमथी वैदिक गुरुकुल,गोठमांगलोद के अध्यक्ष सोहनलाल दाहिमा (हैदराबाद)एवं ओमप्रकाश दाहिमा (निजामबाद) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंट कर गोठमांगलोद, राजस्थान से संबंधित समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही पुष्कर सदन, पुष्कर हेतु अतरिक्त भूमि प्रदान करने हेतु भी निवेदन किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने संबंधित विषयों में यथा संभव सहायता करने का आश्वासन प्रदान किया।

खबरें जो सोच बदल दें शुभ लाभ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

उत्तम चावल वितरण एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम : उत्तम कुमार रेड्डी

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना के सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को तेलंगाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बढ़िया चावल के मुफ्त वितरण को एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया।इसे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा पहल बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इस योजना को लोगों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है।

हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 6 किलो बढ़िया चावल मिलेगा। सरकार हर साल 13,000 करोड़ रुपये की लागत से 30 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित करेगी। मंत्री ने इसे सामाजिक न्याय का मॉडल बताते हुए कहा कि इससे 3.10 करोड़ लोगों को लाभ होगा – जो तेलंगाना की आबादी का लगभग 85 प्रतिशत है।

मुख्य सचिव शांति कुमारी द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय से सभी जिला कलेक्टरों के साथ आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए मंत्री ने कहा कि यह योजना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है और तेलंगाना की कल्याण यात्रा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, यह योजना लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। हमें इसे ऐतिहासिक और समावेशी प्रयास बनाना चाहिए।उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राज्य की लगभग 85 प्रतिशत गरीब आबादी को इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चावल की आपूर्ति में कोई देरी या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ सही तरीके से किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से उचित निगरानी, सुचारू परिवहन और जन प्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को वितरण प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और विश्वास कायम करने के लिए लाभार्थियों के साथ भोजन भी करना चाहिए।उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन भद्राचलम में एक लाभार्थी के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वह स्वयं सूर्यपेट में एक पीडीएस लाभार्थी के साथ रात्रि भोज करेंगे।

मंत्री ने याद दिलाया कि पहले सरकार मोटा चावल बांटती थी, जो गरीबों को पसंद नहीं था। हालांकि सरकार इस पर हर साल 10,665 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी, लेकिन चावल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसका अधिकांश हिस्सा कालाबाजारी में बेच दिया गया। हर साल 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये का चावल दुरुपयोग किया गया।उन्होंने कहा, विस्तृत अध्ययन और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कई बैठकों के बाद, हमने मोटे चावल के स्थान पर बारीक चावल इस्तेमाल करने का फैसला किया।इस योजना का शुभारंभ 30 मार्च को उगादी के दिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हुजूरनगर निर्वाचन क्षेत्र से किया था।

सम्मेलन के दौरान जिला कलेक्टरों ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। कई जिलों में 99 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल कर लिया गया है और जनता की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है।

शांति कुमारी ने कलेक्टरों को योजना के बारे में गलत प्रचार को रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्टरों से सही और तथ्यात्मक जानकारी साझा करने और कार्यक्रम की सफलता को उजागर करने को कहा।मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही राशन कार्डों का भौतिक वितरण शुरू करेगी। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को तिरंगा कार्ड और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सही तरीके से सत्यापन करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।

उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना के गठन के समय 89.73 लाख राशन कार्ड थे। लेकिन बीआरएस के 10 साल के शासन में केवल 49,479 नए कार्ड जारी किए गए। अब कांग्रेस सरकार के तहत नए कार्ड और सदस्य जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

अभी तक तेलंगाना में करीब 90 लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे 2.85 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। सत्यापन के बाद जल्द ही करीब 30 लाख और कार्ड जारी किए जाने की उम्मीद है, जिससे कुल संख्या 1 करोड़ और कुल लाभार्थियों की संख्या 3.10 करोड़ हो जाएगी।

उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हम संतृप्ति स्तर तक जाएंगे। कोई भी पात्र परिवार छूटेगा नहीं।

सिखवाल समाज की नांदेड से निकलने वाली मासिक पत्रिका सिखवाल दर्पण विशेषांक का लोकार्पण करते हुए सिखवाल समाज नागौरपट्टली के अध्यक्ष अनिल जायवाल एवं प्रमुख समाज सेवी सुरेशचंद्र उपाध्याय मिश्रीवाले। इस अवसर पर नथमल उपाध्याय कुडकी, महावीर पंडित, रामनिवास उपाध्याय, अमर जायलवाल, श्रीनिवास नागला एवं पत्रिका के संपादक जयप्रकाश नागला आदि उपस्थित थे।

छठ पर्व के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी दि. 4 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्ध्य दिया गया और प्रसाद ग्रहण किया गया । जन सेवा संघ के अध्यक्ष आर पी सिंह ने हर्ष और उल्लास से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हेमानगर घाट के प्रभारियों के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक चैती छठ महापर्व का समापन हुआ ।

तेलंगाना सरकार शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करेगी

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा आयोग को एक विस्तृत और कार्यान्वयन योग्य रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया, जो वैश्विक मानकों की आकांक्षा रखते हुए जमीनी हकीकत के अनुरूप हो।शुक्रवार, 4 अप्रैल को एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र-केंद्रित शिक्षा मॉडल के निर्माण के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप जीवन कौशल और शैक्षणिक ज्ञान को समान प्राथमिकता देने के महत्व पर बल दिया।रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पहले ही कई कदम उठाए हैं। इनमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती, अम्मा आदर्श समितियों को फिर से सक्रिय करना, पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म का समय पर वितरण और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजीडेंशियल स्कूलों की स्थापना शामिल है।इसके अतिरिक्त, राज्य शैक्षणिक शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को पाटने के लिए युवा भारत कौशल विश्वविद्यालयों के निर्माण की योजना बना रहा है।बैठक के दौरान चर्चा का मुख्य क्षेत्र प्रारंभिक शिक्षा था, जिसमें आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आवश्यक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। सरकार कथित तौर पर शिक्षकों, सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही है ताकि ऐसी नीतियां बनाई जा सकें जो दीर्घकालिक रूप से समावेशी और प्रभावी हों।बैठक के दौरान शिक्षा आयोग के अध्यक्ष एम मुरली ने क्षेत्र भ्रमण के आधार पर विभिन्न भारतीय राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों से प्राप्त जानकारी प्रस्तुत की। इन तुलनात्मक अध्ययनों से तेलंगाना की नई नीति के रोडमैप को जानकारी मिलने की उम्मीद है।फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के महासचिव डॉ. जयप्रकाश नारायण ने इस बात पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि कैसे पिछले शैक्षिक सुधारों ने छात्रों में रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को धीरे-धीरे कम कर दिया है।

चावल वितरण के दौरान महिलाओं ने तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। शुक्रवार, 4 अप्रैल को मेडक जिले में बढ़िया चावल वितरण के दौरान महिलाओं के एक समूह ने तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा के साथ दुर्व्यवहार किया।यह घटना उस समय हुई जब नरसिम्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र अंडोल में कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। महिलाओं ने नए राशन कार्ड न मिलने पर चिंता जताई। महिलाओं ने पूछा, अगर वे नए राशन कार्ड जारी किए बिना बढ़िया चावल उपलब्ध कराते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास नया राशन कार्ड नहीं है?

30 मार्च को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सूर्यपेट जिले के हुजूरनगर निर्वाचन क्षेत्र से बढ़िया अनाज चावल वितरण योजना की शुरुआत की। रेवंत ने याद दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना पहली बार 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी।1 अप्रैल को तेलंगाना की मुख्य सचिव ए. शांति कुमारी ने नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और राज्य भर के कलेक्टरों से लोगों को अच्छे चावल का उचित वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टरों को मंत्रियों और स्थानीय विधायकों के साथ विचार-विमर्श कर कार्ययोजना तैयार करने और मंडल मुख्यालयों पर वितरण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उत्सवी माहौल बनाया जा सके।उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर भी बल दिया तथा आश्वासन दिया कि चावल का 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉक पहले ही उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचा दिया गया है, तथा शेष स्टॉक आगामी दिनों में भेज दिया जाएगा।नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने ऐसी पहल शुरू की है, जिससे राज्य की 84 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।सफेद राशन कार्ड धारक बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को मोटे चावल के स्थान पर छह किलोग्राम बारीक चावल मिलेगा।89.73 लाख सफेद राशन कार्ड हैं, जिनसे 2.8 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। 30 लाख नए आवेदनों के साथ कुल लाभार्थियों की संख्या 3.10 करोड़ तक पहुंच जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना पर सालाना 10,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी।सरकार को राशन की दुकानों के माध्यम से बढ़िया चावल वितरित करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मोटा चावल बिचौलियों के हाथों में जा रहा था।मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार राशन की दुकानें 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने गरीबों की भूख मिटाने के लिए भोजन का अधिकार अधिनियम लाया था।

रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि 1982-83 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी ने 1.90 रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद एनटी रामाराव ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल योजना शुरू की।

वर्तमान में, सफेद राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मोटा चावल दिया जा रहा है, लेकिन वे इसका उपभोग नहीं कर रहे हैं और इसे चावल मिलर्स को 10 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। चावल मिलर्स चावल को रिसाइकिल कर रहे हैं और इसे 50 रुपये प्रति किलो बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं।

वारंगल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज किया

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना के वारंगल में जिला न्यायालय भवन परिसर को शुक्रवार, 4 अप्रैल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। हालांकि, परिसर की गहन तलाशी के बाद इसे अफवाह घोषित कर दिया गया, पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10 बजे अदालत से धमकी भरे ई-मेल के बारे में सूचना मिली, जो न्यायाधीश के कार्यालय को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि परिसर में बम लगाया गया है और वह फट जाएगा।

पुलिस टीमों ने बम निरोधक इकाई और खोजी कुत्तों के दस्ते के साथ मिलकर परिसर की गहन जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह एक फर्जी ईमेल था।

उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

3 अप्रैल को एक पूर्व माओवादी नेता ने जिला कलेक्टर गौतम पोत्रा को ईमेल भेजकर मेडचल-मलकजगिरी जिला कलेक्टरेट को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई तलाशी में ऐसा कोई उपकरण नहीं मिला।

कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा पुलिस को बम की धमकी के बारे में सूचित किए जाने के बाद विस्फोटकों की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया।

टीजीएसपीडीसीएल ने 57 क्षतिग्रस्त खंभों और 44 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। भारी बारिश के बीच, हैदराबाद के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, क्योंकि पेड़ और शाखाएं गिरने से 57 बिजली के खंभे और 44 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें टीजीएसपीडीसीएल ने तुरंत बहाल कर रिकॉर्ड समय में बिजली बहाल कर दी।

हैदराबाद के सेंट्रल सर्किल सहित कई सर्किलों में बारिश का व्यापक असर हुआ और 7 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) और 23 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए।हैदराबाद साउथ सर्किल ने 11 डीटीआर और 15 खंभों को नुकसान पहुंचने की सूचना दी है। सिकंदराबाद सर्किल में 5 डीटीआर प्रभावित हुए हैं, जबकि सरूर नगर सर्किल में 14 डीटीआर और 3 खंभों को नुकसान पहुंचा है। हब्सीगुडा क्षेत्र में भी प्रतिकूल मौसम की वजह से 7 डीटीआर और 7 खंभों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।बारिश के कारण न केवल बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई, बल्कि गिरे हुए मलबे और फिसलन भरे इलाकों के कारण पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हो गईं।हैदराबाद में भारी बारिश दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ गए, शहर में भयंकर जलभराव हो गया तथा यातायात और बिजली संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गईं।केपीसी जंक्शन, आरटीए अधिकारी (खारीताबाद-सोमाजीगुडा), सैदाबाद स्टेट बैंक कॉलोनी, बशीरबाग, नेकलेस रोड, मुशीराबाद, असेंबली रोड और बंजारा हिल्स सहित अन्य इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हुई।हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी , हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड और अग्निशमन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है तथा वे सड़कों पर पानी भरने से निपटने के लिए यातायात पुलिस अधिकारियों की मदद कर रहे हैं।

एसीबी ने पटनचेरू सिंचाई अधिकारी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तेलंगाना ने संगारेड्डी जिले के पाटनचेरु सिंचाई उप-मंडल कार्यालय पर छापा मारा और एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अधिकारियों के अनुसार सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (एईई) गुम्माडिला रवि किशोर को 7 लाख रुपये की रिश्वत के एक हिस्से के रूप में 1 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। बताया जाता है कि रिश्वत फुल टैंक लेवल (एफटीएल) या बफर जोन में शामिल नहीं होने वाली जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के लिए मांगी गई थी।एसीबी के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही विभाग का एक अधिकारी रामास्वामी फरार हो गया।

दक्षिण मध्य रेलवे

हमें SCRailwayindia पर फॉलो करें
द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं के विवरणों को हमारी वेबसाइट : www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है

ई-निविदा सूचना सं. सी-एसजी-पीटी-एचडीएन-पीएमएस-01, दि. 02.04.2025 PUB/0344

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत उप सीएसटीई/परियोजनाएं/टेली/एससी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित हैं।

निविदा सं. और तिथि: सी-एससी-पीटी-एचडीएन-पीएमएस-01 दि. 02.04.2025, **कार्य का नाम:** दक्षिण मध्य रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क में कवच और 4 जी एलटीई-आर के प्रावधान के लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण इंजीनियर की नियुक्ति, **अनुमानित परियोजना लागत:** रु. 7,49,85,775.79, **बोली सुरक्षा:** रु.3,74,900.00, **कार्य पूरा होने की अवधि:** 24 महीने, **बोली बंद होने की तिथि (बोली देय तिथि):** 02.05.2025 15:00 बजे, **बोली खुलने की तिथि:** 02.05.2025 15:00 बजे के बाद, **प्रस्ताव की वैधता:** बोली बंद होने की तिथि से 120 दिन, **निविदा पुस्तिका की लागत:** रु.0.00

सभी बोलियां भारतीय रेलवे ई-टेंडरिंग पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर हैं। इस निविदा के खिलाफ मैन्युअल ऑफर की अनुमति नहीं है।

डिप्टी सीएसटीई/प्रोजेक्ट्स/ टेली/ सिकंदराबाद

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (https://ireps.gov.in के माध्यम से) PUB/0345

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत मुख्य विद्युत अभियंता, निर्माण, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद द्वारा निविदा की दो पैकेट प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित है।

क्रम.सं.: 1, **एनआईटी सं.:** ई29 सीटीआरडीएससी_01-2025-26 दिनांक 02.04.2025, **कार्य का नाम:** निविदा संख्या ई 29 सीटीआर डीएससी_01-2025- 26 दिनांक 02.04.2025 दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद डिवीजन में काजीपेट-कोंडापाली सेक्शन के बीच ट्रिपलिंग के मद्देनजर प्रस्तावित दोर्नकल यार्ड में मौजूदा ओएचई में संशोधन सहित 65 वर्ग मिमी कैटेनरी वायर और 150/107 वर्ग मिमी संपर्क तार, एल.टी आपूर्ति ट्रांसफार्मर स्टेशनों के साथ 2द25 केवी, 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज, एसी ट्रैक्शन ओवरहेड उपकरण की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, **विवरण:- अनुमानित लागत:** रु. 13,88,88,072.05/-, **पूधरा/बोली सुरक्षा:** रु. 8,44,500.00/-, **दस्तावेज लागत:** ऑनलाइन निविदा दस्तावेज मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है, **समापन अवधि:** 09 महीने, **समापन की तिथि:** 02.05.2025 15:00 बजे।

1) बोली दस्तावेज और अन्य विवरणों के लिए, कृपया वेबसाइट पर लॉगिन करें https://ireps.gov.in

2) बोलीदाता को https://ireps.gov.in के माध्यम से बोली सुरक्षा प्रदान करनी होगी या भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी बांड के रूप में जमा करना होगा। बैंक गारंटी बांड परिशिष्ट-तखख के अनुसार होगा और बोली वैधता अवधि से परे 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, जमा रसीदें, एफडीआर आदि के माध्यम से मैन्युअल भुगतान की अनुमति नहीं है।

3) निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान अपने प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जो निविदा बंद होने से पंद्रह दिन की अवधि है।

4) निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के प्रारंभ होने की तारीख तक किसी भी शुद्धिपत्र (केवल ऑनलाइन जारी) की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

उप. मुख्य विद्युत अभियंता-1/ कॉन/सिकंदराबाद

ई-निविदा सूचना सं. 40-उप मुख्य अभियंता/जीएस/जीएनटी PUB/0346

अधोहस्ताक्षरित द्वारा निम्न कार्य के लिए **07.04.2025 को 15:30 बजे तक आमंत्रित किए गए ई-निविदाएं यहां रद्द की जाती हैं।**

क्रम.सं. 1, निविदा आईडी: 79, **अनुभाग:** उप मुख्य अभियंता/जीएस/जीएनटी, **कार्य का विवरण:** गुंटूर डिवीजन: वेमुरु (वीएमयू) गुड्स शेड में सुविधाओं का विकास।

ई-पोर्टल **https://ireps.gov.in** पर शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है

उप मुख्य अभियंता, गति शक्ति, गुंटूर

निविदा संख्या जीटीएल-ईएम-01-2025-26 दि.: 04.04.2025 PUB/0347

कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत वरिष्ठ मंडलीय विद्युत अभियंता/ अनुरक्षण/ गुंटकल द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित हैं।

निविदा सं.: जीटीएल-ईएम-01- 2025-26, **कार्य का नाम:** गुंतकल डिवीजन: डिवीजन में अकुशल, गैर-स्टार रेटेड ओवरएज एयर कंडीशनर के स्थान पर स्टार रेटेड इन्वर्टर एयर कंडीशनर का प्रावधा। **अनुमानित लागत:** रु.92,49,517.60/-

अंतिम तिथि और समय: 25.04.2025 **को 15.00 बजे**

निविदा और अन्य विवरणों के लिए **https://ireps.gov.in** पर लॉग इन करें। निविदा का शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऑनलाइन जारी किया जाएगा। निविदा दस्तावेज को निविदाकर्ता द्वारा **https://ireps.gov.in** से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

नोट: इस ई-निविदा में भाग लेने/बोली लगाने के लिए, निविदाकर्ता के पास वैध डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) होना चाहिए।

वरिष्ठ मंडलीय विद्युत अभियंता रखरखाव, गुंतकल

A0433

अतिरिक्त निविदा शर्तों/विवरणों के लिए और निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाइट : www.ireps.gov.in या http://www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

DAILY शुभ लाभ Classifieds FIND BUY SELL

CHANGE OF DOB

I, NANDYALA LAKSHMMA Mother of Service No. 2617757H L/Nk NANDYALA VENKATA RAMANA, R/o.1-80, Vill:KBayanaPalli, PO:KrishnamSettyPalle, Teh:Giddalur, Dist:Prakasam, Andhra Pradesh-523357 have changed my Date of Birth from 13-04-1960 to 01-01-1966 vide affidavit dt:04-04-2025 before G.Shobha, Advocate and Notary, Brahmanwadi, Begumpet, Hyderabad.

CHANGE OF NAME & DOB

I, NANDYALA BALA VENKATAIAH Father of Service No. 2617757H L/Nk NANDYALA VENKATA RAMANA, R/o.1-80, Vill:KBayanaPalli, PO:KrishnamSettyPalle, Teh:Giddalur, DistPrakasam, Andhra Pradesh - 523357 have changed my name and DOB from NANDYALA BALAVENKATAIAH, DOB:10-08-1955 to NANDYALA BALA VENKATAIAH, DOB:01-01-1956 vide Affidavit dt:04-04-2025 before G.Shobha, Advocate and Notary, Brahmanwadi, Begumpet, Hyderabad.

CHANGE OF NAME

I, MAMONI SAMANTA, is Legally wedded spouse of No 15689125N, Rank HavildarName. SHAMBHU CHARAN SAMANTA presently residing at Vill-HarkuliBhandarChak, Po Moyna Ps-Moyna, State-West Bengal. Pin-721629, have changed My Name from MAMONI SAMANTA to MAMONI MANNASAMANTA, (my date of birth is 17-04-1993) vide Affidavit Date.03-04-2025 before Mohd MuzibullaBaig Advocate and Notary High Court of Telangana, Tolichowki Hyderabad

CHANGE OF NAME

I NISHA RANEESH is legally wedded Spouse of Service No-14662830M Rank-HAV,Name-Raneesh P, Residing at Ushas, Vayalapra, Aduthila,Madayi,Ezhome, District-Kannur, PIN-670303, State-Kerala. I have changed my name from NISHA RANEESH to NISHA P V Affidavit dated 04 Apr 2025 before X Spl Judicial Magistrate Hyderabad.

CHANGE OF NAME

I SVSL TULASI is legally wedded Spouse of Service No-14674652F, Rank-HAV,Name-Utukuri Kishore, Residing at H.No-4-87-17, Sri Pavani Estate, B.V.C College Road, Batlapalem, Indupalle, District-East Godavari, PIN-533221, State-Andhra Pradesh. I have changed my name from SVSL TULASI to UTUKURI SURYA VENKATA SATYA LAKSHMI TULASI Affidavit dated 04 Apr 2025 before X Spl Judicial Magistrate Hyderabad.

CHANGE OF NAME

I RAJYA LAKSHMI is legally wedded Spouse of Service No-14649522N Rank-HAV, Name-Nidara Iyyavarlu Reddy Residing at H.No- 23-123, Munnam Vari Palem, Chinaganjam, Dist-Prakasam, PIN-523135, State-Andhra Pradesh. I have changed my name from RAJYA LAKSHMI to NIDARA RAJYA LAKSHMI Affidavit dated 04 Apr 2025 before X Spl Judicial Magistrate Hyderabad.

CHANGE OF NAME

I, No.15823850K Hav Sanjay Singh Rajpoot of Aoc records, Aoc Centre, Secunderabad, TS that my mother Name is changed from MANEESHA DEVI to MANISHA DEVI

पेंशन विवादः सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कड़ी फटकार

भारी मुआवजा देने के आदेश की चेतावनी

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

उच्चतम न्यायालय ने एक पेंशन योजना लागू करने में नाकाम रहने पर पंजाब सरकार की शुक्रवार को आलोचना की और चेतावनी देते हुए कहा अब यदि सरकार विफल हुई तो अदालत उसे प्रत्येक याचिकाकर्ता को कम से कम 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देगी।

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह चेतावनी दी। याचिका में योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा की गई पूर्व प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने निजी तौर पर संचालित पंजाब सरकार के

संबद्ध और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज पेंशन लाभ योजना 1986 को लागू करने में विफल रहने और पात्र लाभार्थियों को उनके पेंशन संबंधी अधिकारों से वंचित करने के लिए कड़ी आलोचना की।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति के समय ही अपनी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) निकाल ली थी। उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा देने का सुझाव दिया। अदालत ने हालांकि इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, एक लाख रुपये की दलील हमारे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है। हम पर्याप्त मुआवजा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो अदालत राज्य को प्रत्येक याचिकाकर्ता को कम से कम 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देगी। ये राशि योजना के गैर-कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने राज्य के रुख का विरोध किया, पंजाब निरसन अधिनियम को पूरी तरह से अवैध कहा और इस बात पर जोर दिया कि पेंशन निर्धारण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रति माह 1.5 लाख रुपये का भुगतान होगा।

अदालत ने पंजाब द्वारा अपने आश्वासनों को अमल करने में बार-बार विफल रहने पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति ओका ने चेतावनी दी, यदि राज्य अड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि राज्य से कैसे निपटना है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अदालत के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमने पहले भी दर्ज किया है कि धोखा दिया गया है।पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

पीठ ने सवाल किया कि क्या महाधिवक्ता (एजी) द्वारा की गई पिछली प्रतिबद्धताओं का कोई महत्व है, यदि सरकार उनकी (प्रतिबद्धताओं) अवहेलना करना जारी रखती है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि एजी द्वारा दिए गए किसी भी बयान के साथ संबंधित राज्य अधिकारी का हलफनामा होना चाहिए।

श्री सिंघवी ने अटॉर्नी जनरल का बचाव करते हुए कहा कि प्रयास किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए।

शीर्ष अदालत ने अनुपालन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले को 15 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई समाधान नहीं निकला, तो वह मौद्रिक मुआवजे का निर्देश देते हुए अंतिम आदेश पारित करेगी।

मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण का सफल परीक्षण

नई दिल्ली 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और सेना ने ओडिशा के तट से डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के सफल उड़ान-परीक्षण किये हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को तेज गति के हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मिसाइल के चार ऑपरेशनल फ्लाइट-ट्रायल किए गए। मिसाइलों ने हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर दिया। परीक्षण लंबी दूरी, छोटी-दूरी, अत्यधिक ऊंचाई और कम ऊंचाई पर चार लक्ष्यों को निशाना बनाकर किये गये थे। इससे सेना की संचालन क्षमता प्रमाणित हुई है।उड़ान-परीक्षण हथियार प्रणाली के साथ किये गये। हथियार प्रणाली के प्रदर्शन को एकीकृत टेस्ट रेंज, चांदीपुर द्वारा तैनात रैडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कैप्चर किए गए फ्लाइट डेटा के माध्यम से प्रमाणित किया गया। ये परीक्षण डीआरडीओ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए। इन परीक्षणों ने सेना की परिचालन क्षमता को साबित कर दिया है और दो रेजिमेंटों में हथियार प्रणालियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस मिसाइल प्रणाली को सेना द्वारा उपयोग के लिए डीआरडीओ और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को सफल उड़ान-परीक्षणों के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चार सफल परीक्षणों ने हथियार प्रणाली की क्षमता को फिर से स्थापित किया है।

डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामात ने भी सफल उड़ान-परीक्षण में शामिल टीमों की सराहना की।

हैदराबाद विवि परिसर में आवारा कुत्तों ने हिरण पर हमला किया

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

कांचा गाचीबोवली में वनों की कटाई के परिणामस्वरूप, एक चित्तीदार हिरण, जो आश्रय की तलाश में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के छात्रावास की ओर बढ़ा था, पर शुक्रवार 4 अप्रैल की सुबह आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर हिरण को तुरंत उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां हिरण की हालत में सुधार बताया गया। आवारा कुत्तों द्वारा हिरण पर हमला किया जाना कोई अकेली घटना नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, हर साल 30-40 हिरण इसी तरह के हमलों में मारे जाते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि कांचा गाचीबोवली की कई एकड़ ज़मीन पर पेड़ों को काट दिए जाने के कारण ये जानवर आवारा कुत्तों का आसान शिकार बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉ. मोहम्मद अब्बास ने 2016 की एक शाम को याद किया जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया ही था। जब वे फिल्टर से पानी पी रहे थे, तो परिसर में जंगली कुत्तों के झुंड से भागते हुए एक हिरण दीवार फांदकर उनके हाथों में आ गिरा।

छुट्टियां मना रही ब्रिटेन की महिला से 13.29 लाख की ठगी

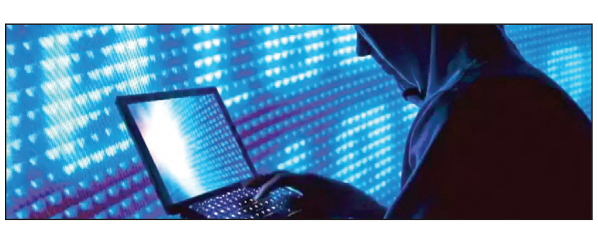

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

छुट्टियों पर आई ब्रिटेन की एक महिला से जालसाजों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर 13.29 लाख रुपये की ठगी कर ली। हैदराबाद में अस्थायी रूप से रहने वाली एक निजी कर्मचारी पीड़िता को एक भारतीय नंबर से फ़ोन आया, जिसमें दावा किया गया कि वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से है। कॉल करने वाले ने पहले उस पर अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध विज्ञापन प्रसारित करने और लोगों को परेशान करने वाले संदेश भेजने के लिए करने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 'दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस' से बात करने की धमकी दी।

जब वह वीडियो कॉल से जुड़ी, तो दिल्ली पुलिस से होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके आधार विवरण का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े एचडीएफसी बैंक खाते को खोलने के लिए किया जा रहा है। उसे बताया गया कि अगर उसकी पहचान सत्यापित नहीं की गई तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।एक अन्य व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए उसे फोन किया। पीड़िता से उसका आधार कार्ड दिखाने को कहा गया और कॉल के बारे में किसी को कुछ भी न बताने की चेतावनी दी गई। जालसाज ने उसे सीबीआई का जाली लेटरहेड दिखाया और धमकी दी कि अगर उसने इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे जेल हो जाएगी।

डर के कारण महिला को 'सत्यापन उद्देश्यों' के लिए पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। उसे 'क्लीयरेंस लेटर' देने का वादा किया गया जिसमें कहा गया कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़ी नहीं है। घोटालेबाजों पर विश्वास करके महिला ने जालसाजों द्वारा बताए गए खातों में कुल 13,29,999 रुपये ट्रांसफर कर दिए।पैसा भेजे जाने के बाद जालसाजों ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।

शराब की दुकानें और बार कल बंद रहेंगे

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

हैदराबाद शहर पुलिस ने राम नवमी त्यौहार के मद्देनजर 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब और ताड़ी की दुकानों और रेस्तरां से जुड़ी बार को बंद करने का निर्देश दिया है।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद द्वारा तेलंगाना आबकारी अधिनियम, 1968 की धारा 20 के तहत बंद करने का आदेश हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों पर लागू होता है। लेकिन स्टार होटलों और पंजीकृत क्लबों के बार को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।यह आदेश सरकार और पुलिस प्राधिकारियों, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग, पुलिस महानिदेशक और आबकारी विभाग को भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका कार्यान्वयन हो।

नागरिकों और दुकानदारों से से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रतिबंध का ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

बुजुर्ग मां-बाप अपने बच्चों को संपत्ति से नहीं कर सकते बेदखल

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

यह बात सही है कि भागदौड़ भरी जिंदगी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से भी सिंगल परिवारों की संख्या बढ़ गई है। शायद इसीलिए माता-पिता और बच्चों के रिश्तों के सामने एक नई चुनौती है। जहां कभी बुजुर्ग माता-पिता को घर की नींव माना जाता था वहीं अब कई बार उन्हें अपने ही बच्चों से सम्मान और देखभाल की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे में जब बुजुर्ग अपने ही घर में अपमान उपेक्षा या मानसिक पीड़ा झेलते हैं तो सवाल उठता है क्या वो अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं।

इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। असल में सीनियर नागरिकों की देखरेख और भरण-पोषण से जुड़ा एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या बुजुर्ग मां-बाप अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर कपल की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने बेटे को घर से निकालने की मांग की थी। इस याचिका में उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण

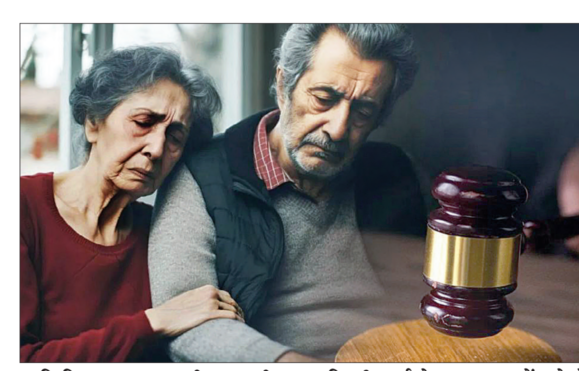

अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का हवाला दिया था। यह कानून बुजुर्गों को भरण-पोषण पाने का अधिकार देता है लेकिन इसमें बेदखली का अधिकार नहीं दिया गया है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों में यह क्लियर किया है कि अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति किसी शर्त के साथ बच्चों को देते हैं और वे शर्तें पूरी नहीं होतीं तो बेदखली संभव है। कानून की धारा 23 के तहत अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति इस शर्त पर किसी को दी है कि वह उसकी देखभाल करेगा लेकिन वह शख्स ऐसा नहीं करता तो वह हस्तांतरण अमान्य माना जा सकता है। ऐसे मामलों में बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं और संपत्ति वापस लेने की मांग कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक फैसले में कहा था कि यदि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल न की जा रही हो या वे प्रताड़ना का शिकार हो रहे हों तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के

तहत गठित ट्रिब्यूनल बच्चों या रिश्तेदारों को घर से निकालने का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अधिकार कानून की धारा 23(2) में निहित है जिसमें बुजुर्ग संपत्ति से भरण-पोषण का हक रखता है और यदि वह संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर दे तो यह हक नए मालिक पर भी लागू होता है।

फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की बेदखली से इनकार कर दिया। बुजुर्ग दंपति ने दावा किया कि उनका बेटा मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करता है। 2019 में ट्रिब्यूनल ने आंशिक राहत देते हुए बेटे को घर के किसी और हिस्से में एंट्री न करने और केवल अपने दुकान और कमरे तक सीमित रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक बेटे के दुर्व्यवहार का कोई नया प्रमाण न हो, तब तक बेदखली का आदेश जरूरी नहीं।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए आठ न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने आठ न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की ओर से एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई।

बयान के मुताबिक, दो अप्रैल को हुई कॉलेजियम की बैठक में जितेंद्र कुमार सिन्हा, अब्दुल शाहिद, अनिल कुमार-10, तेज प्रताप तिवारी, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, मदन पाल सिंह और हरवीर सिंह को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई।

शेयर मार्केट

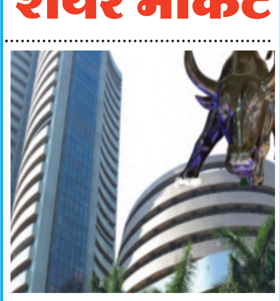

बीएसई : 75,364.69
-930.67 -1.22% ↓
एनएसई :22,904.45
-345.65 (-1.49%) ↓

सर्राफ़ा बाज़ार

(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 91,220/- (प्रति 10 ग्राम)
चाँदी : 89,740/- (प्रति किलोग्राम)

पाइपलाइन लीक होने से हैदराबाद के कुछ हिस्सों में पेयजल आपूर्ति बाधित

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)।

मंजीरा जलापूर्ति योजना चरण 2 के तहत पाटनचेरु-हैदरनगर खंड में 1500 मिमी व्यास वाले पीएससी पंपिंग मेन में बड़े पैमाने पर रिसाव के कारण हैदराबाद के कुछ इलाकों में पेयजल आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। आरसी पुरम, फादर स्कूल और ओल्ड मुंबई रोड पर रिसाव से विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। अधिकारियों द्वारा मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है, तथा यह आज, शुक्रवार, 4 अप्रैल को रात 11 बजे तक चलेगा। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों से कहा गया है कि वे तब तक पेयजल का संरक्षण करें जब तक कि आपूर्ति पूरी क्षमता पर बहाल नहीं हो जाती।

हैदराबाद में पेयजल आपूर्ति बाधित होने वाले क्षेत्र

-ओ एंड एम डिवीजन - 6: एर्रागड्डा, एसआर नगर, अमीरपेट (कम पानी का दबाव)।

-ओ एंड एम डिवीजन - 8: हाफ टेक पॉइंट, बल्क कनेक्शन

-ओ एंड एम डिवीजन - 9: केपीएचबी कॉलोनी, कुकटपल्ली, भाग्य नगर कॉलोनी, वसंत नगर।

-ओ एंड एम डिवीजन - 15: आरसी पुरम, अशोक नगर, ज्योति नगर, लिंगमपल्ली, चंदा नगर, गंगाराम, दीप्ति श्री नगर, मदीनागुडा, मियापुर।

-ओ एंड एम डिवीजन - 24: बिरंगुडा, अमीनपुर, बोल्लाराम।

जल बोर्ड के अधिकारियों ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान करके जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे नियमित आपूर्ति बहाल होने तक पानी का भंडारण और उपयोग समझदारी से करें।

शुभ लाभ का वार्षिक सब्सक्रिप्शन लें और उतने ही मूल्य का विज्ञापन छपवाएं

शुभ लाभ
R. No. 5305
SPACE COUPON Rs. 2500/-
Worth of 1 Advertisement 10x10 Sq. Cm. in Shubh Labh
Validity : 1 Year from the time of Issue
SUBSCRIPTION FORM
Name :
Period of Subscription : Annual Rs. 2500/-
Mode of Payment : CHEQUE / D.D.
Cheque No. & Date .... Drawn
Name of the Executive
SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
4th Floor, T19 Towers, Ranigunj, Secunderabad-500 003 (T.S.)

सुधि पाठकों को यह सूचित करना है कि हिंदी दैनिक शुभ लाभ वार्षिक सब्सक्रिप्शन स्कीम में आंशिक फेरबदल के साथ नये सिरे से सदस्यता अभियान शुरू कर रहा है। रुपये 2500/- के सालाना सब्सक्रिप्शन पर आप निर्धारित अवधि में रुपये 2500/- मूल्य (10x10 वर्ग सेंटीमीटर) का विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कूपन की प्रकाशित फोटो के अनुरूप आप अपनी प्राप्ति-रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8688868345 पर संपर्क करें। - प्रबंधक

सूचना : सुधि पाठकों और विज्ञापनदाताओं से आग्रह है कि वे वार्षिक सब्सक्रिप्शन एवं विज्ञापन की राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए सीधे संस्थान के बैंक खाते में डालें या बार-कोड द्वारा भेजें...

A/C Holder Name : Shree Siddivinayak publications
Bank Name : City Union Bank
OD Account
A/c.No. : 512120020029300
Branch : Balanagar, Hyderabad
IFS Code : CIUB0000464

SHREE SIDDIVINAYAK PUBLICATIONS
Hyderabad Balanagar

तेलंगाना सरकार आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित दो प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं - गोदावरी-बनकाचेरला लिंक योजना और रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (आरएलआईएस) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार 4 अप्रैल को जल सौधा में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि दोनों ही योजनाएं स्थापित जल-बंटवारे समझौतों का उल्लंघन करती हैं और तेलंगाना की सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल आवश्यकताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश द्वारा उचित नियामक प्राधिकरणों से मंजूरी लिए बिना ही इन परियोजनाओं को एकतरफा रूप से शुरू किया जा रहा है।

कानूनी तैयारी के तहत जल्द ही कानूनी विशेषज्ञों, सिंचाई विभाग के स्थायी वकीलों और महाधिवक्ता के साथ एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी में अपने उचित हिस्से की रक्षा के लिए अदालत में योजनाओं का मजबूती से विरोध करेगा।

मंत्री ने कहा, गोदावरी-बनकाचेरला लिंक योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विशाल परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 80,112 करोड़ रुपये है। इस योजना में पोलावरम में गोदावरी नदी से 200 टीएमसीएफटी पानी को बोल्लापल्ली जलाशय और बनकाचेरला हेड रेगुलेटर के माध्यम से रायलसीमा तक मोड़ना शामिल है। प्रस्ताव में गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है।

रेड्डी ने कहा कि यह परियोजना सीधे तौर पर 1980 के गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) के फैसले और 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए) का उल्लंघन करती है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी), कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) या शीर्ष परिषद से अनिवार्य मंजूरी हासिल नहीं की है।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एपीआरए की धारा 46(2) और 46(3) का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास की अनुमति देता है, ताकि केंद्रीय निधियों को सुरक्षित किया जा सके। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे प्रावधान वैधानिक अनुमोदन और पर्यावरण सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते।रेड्डी ने कहा, तेलंगाना ने पहले आरएलआईएस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसका उद्देश्य कृष्णा नदी बेसिन से पानी खींचना है। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने फरवरी में फैसला सुनाया कि आंध्र प्रदेश को आरएलआईएस साइट को उसके निर्माण-पूर्व चरण में बहाल करना चाहिए।

उन्होंने कहा, समिति ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया है और उसे पर्यावरण मंजूरी के लिए फिर से आवेदन करने से पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य, बहाली का विवरण और समयसीमा प्रदान करनी चाहिए। ईएसी का निर्णय तेलंगाना द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य मंचों पर कई बार प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व के बाद आया है।

रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश अभी भी अन्य माध्यमों से परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि तेलंगाना सरकार मूकदर्शक बनी नहीं रहेगी, तथा किसी भी अवैध निर्माण या पानी के बहाव को रोकने के लिए इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में उठाएगी।

मंत्री ने गोदावरी नदी के किनारे बसे एक प्रमुख शहर भद्राचलम की सुरक्षा के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पोलावरम से रायलसीमा की ओर बाढ़ के पानी को बड़े पैमाने पर मोड़ने से नीचे की ओर प्राकृतिक बाढ़ का स्वरूप प्रभावित हो सकता है और मंदिर शहर को खतरा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भद्राचलम शहर को भविष्य में बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए उसके चारों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता मांगेगी।उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं कि गोदावरी के प्रवाह में परिवर्तन के कारण भद्राचलम को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में सिंचाई दक्षता में सुधार लाने के लिए टैंकों और जलाशयों में जल भंडारण बढ़ाने के लिए गाद हटाने के कार्यों के लिए निविदाएं जल्द ही आमंत्रित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी की हर बूंद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। सिंचाई संसाधनों का अधिकतम और वैज्ञानिक उपयोग होना चाहिए। तेलंगाना अपने उचित हिस्से के लिए लड़ते हुए पानी की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

रेड्डी ने पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार की भी आलोचना की, क्योंकि उसने आंध्र प्रदेश को अपनी जल निकासी क्षमता को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने की अनुमति देकर तेलंगाना के हितों की रक्षा करने में विफलता दिखाई।

उन्होंने बताया कि पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर की क्षमता 2005 से 2023 के बीच 44,000 से बढ़ाकर 92,600 क्यूसेक कर दी गई, जिसमें तेलंगाना की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में शीर्ष परिषद की बैठक आयोजित करने में देरी ने आंध्र प्रदेश को आरएलआईएस निविदाओं के साथ आगे बढ़ने की खुली छूट दे दी।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार कानूनी और संस्थागत तंत्र के माध्यम से राज्य के जल अधिकारों की रक्षा करके पिछली गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोथाकोटा सीता दयाकर रेड्डी को तेलंगाना बाल अधिकार प्रमुख नियुक्त किया गया

हैदराबाद, 04 अप्रैल (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना सरकार ने कोथाकोटा सीता दयाकर रेड्डी को तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।3 अप्रैल को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, छह अन्य लोगों को भी आयोग का सदस्य नामित किया गया है। नव नियुक्त सदस्य हैं:1.कंचेला वंदना गौड़, 2. पार्वती चंदना, 3.गोगुला सरिता, 4.प्रेमलता अग्रवाल, 5. बी. कवन कुमार बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अनुसार, अध्यक्ष नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य भी तीन वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे।सरकार की सचिव अनीता रामचंद्रन द्वारा जारी अधिसूचना में महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक को नियुक्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक गोपाल अग्रवाल द्वारा श्री शेषसाई इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर. 98/1, को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गांधी नगर, बालानगर के पास मेडचेल-मल्काजगिरि जिला. हैदराबाद 500037, तेलंगाना स्टेट से मुद्रित तथा प्लॉट नं. ए-23/5 तथा 6, दूसरा माला, ओपीआईई, बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना राज्य-500037 से प्रकाशित। आर. एन. आई रजिस्टर्ड नं. TELHIN/2019/78163, फोन नं. 040-29551811. E-mail : dailyshubhlabh@gmail.com.